असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 मार्च, 2017

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से.....

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही चलने दीजिये । समय पर उठाइयेगा ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इन सब बातों पर कितनी बार चर्चा कीजियेगा ?

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न संख्या- 836 (श्री राम बालक सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।
2- स्वीकारात्मक है ।
3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0ए0 8519/2006 डब्लू0पी0सी0 314/2010 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2013 के अनुसार चौक-चौराहे पर मूर्त्ति की स्थापना निषिद्ध है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायादेश एवं महाधिवक्ता, बिहार के मंतव्य के अनुसार किसी भी चौक-चौराहे पर जो भी सड़कें है, वहाँ कोई मूर्त्ति वर्जित है ।

श्री राम बालक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मुसरीघरारी चौक जो है, वह एन0एच0 28 और एन0एच0 103 का मुहाना है, सरकार ने अभी वहाँ पर पुलिस बल तैनात किया है । विगत कुछ दिनों पहले एक ठाकुरजी सिपाही थे, उनकी वहाँ घटना स्थल पर मौत हो गई ट्रक के द्वारा, कुछ दिन पहले एक ट्रक और कार की टक्कर में.... ।

अध्यक्ष : राम बालक जी, आपने तो उस चौराहे पर मूर्त्ति लगाने की बात कही है ।

श्री राम बालक सिंह : जी । अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि वह चौराहा बहुत ही व्यस्त और चालू है, वहाँ मूर्त्ति लगाने से यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ होगी । ऐसे कई जगह एन0एच0 पर.....

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब इस तरह की व्यस्त सड़कों पर, एस0एच0 पर, एन0एच0 पर मूर्त्ति लगाने पर रोक लगा दी गई है ।

श्री राम बालक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म-भूमि और कर्मभूमि है और सभी दल के लोग

जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयन्ती मनाते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्त्ति लगाने का तात्पर्य यह है कि उस चौराहा पर यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2043 (श्री रामप्रीत पासवान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजनगर थाना के कार्यक्षेत्र में 25 पंचायत है । राजनगर थाना क्षेत्र से रामपट्टी की दूरी 15 कि0मी0 तथा नगर थाना से रामपट्टी की दूरी 5 कि0मी0 है, जो पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है ।

उक्त क्षेत्र में स्थानीय थाना द्वारा सतत निगरानी एवं गश्ती कर अपराध एवं विधि-व्यवस्था को नियंत्रित रखा जा रहा है ।

वर्त्तमान में रामपट्टी बाजार में ओ0पी0 खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, राजनगर प्रखंड 25 पंचायत का प्रखंड है और रामपट्टी को पूर्व से भी प्रखंड बनाने का प्रस्ताव है । रामपट्टी झंझारपुर, इधर पंडौल, इधर राजनगर और इधर मधुबनी, इस बीच में है । यह रोड जो पहले जीर्ण-शीर्ण था, अब वह एन0एच0 बन गया है, बहुत सारी गाड़ियाँ उस होकर जाती है और बराबर उसमें कहीं न कहीं लूट-चोरी-डकैती होती है ।

माननीय मंत्री जी ने बताया है, राजनगर से रामपट्टी की दूरी 12 कि0मी0 है, सड़क पूर्णतया जर्जर है । पुलिस की गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री रामप्रीत पासवान : जबतक सूचना मिलती है, पुलिस पहुँचे तबतक चोर-डकैत भाग जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से थाना खोलने के लिये नहीं आग्रह कर रहा हूँ, एक ओ0पी0 हो और वहाँ कम से कम एक एस0आई0 और आधा दर्जन फोर्स रहे, जो वहाँ के लोगों को सुरक्षा दे सके । यह मैं आग्रह करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2044 (श्रीमती लेशी सिंह)

अध्यक्ष : श्रीमती लेशी सिंह ने श्री विजय कुमार खेमका जी को प्राधिकृत किया है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत के0नगर प्रखंड के मोगलाहा कब्रिस्तान एवं महम्मदपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर के0नगर प्रखंड के तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक- 2 एवं 4 पर अंकित है ।

प्राथमिकता सूची के क्रमांक 1 पर अंकित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा निदेश दिया गया है । कार्य प्रगति पर है । बारी आने पर प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जायेगी ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिये कलक्टर की अध्यक्षता में कमिटी है, जिसके द्वारा सेंसिटीव स्थान देखकर उसकी प्राथमिकता सूची बनाई जाती है । वैसे मुख्यमंत्री

क्षेत्रीय विकास योजना में भी इसको इनक्लूड किया गया है लेकिन वह प्राथमिकता सूची बदलेगी नहीं । यही वस्तुस्थिति है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इन्होंने जो कहा है कि उसकी प्राथमिकता के आधार पर सूची बनी है, जिला पदाधिकारी को दिया गया है, जल्द से जल्द अगर बन जायेगा तो वहाँ के लिये बहुत उपयोगी होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2045 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिला के प्रखंड लकड़ी नवीगंज में स्थापित ओ0पी0 का अपना भवन नहीं है । यद्यपि लकड़ी नवीगंज ओ0पी0 वर्त्तमान में सामुदायिक भवन में चल रहा है तथापि लकड़ी नवीगंज प्रखंड मुख्यालय में थाना सृजन हेतु पुलिस अधीक्षक, सीवान से प्राप्त प्रस्ताव में कतिपय त्रुटि होने के कारण मानक के अनुरूप वांछित प्रस्ताव की माँग पुलिस मुख्यालय के द्वारा की गई है । पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार के स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

ओ0पी0 क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकी या अन्य कार्यों के लिये बसंतपुर थाना जाने की आवश्यकता नहीं होती है । सभी कार्रवाई ओ0पी0 स्तर से ही की जाती है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ओ0पी0 है, उसको अपना भवन नहीं है, पंचायत का भवन है जो जर्जर है, कभी-भी गिर सकता है । पुलिस तो अपराधी को पकड़ती है, उसके पास हाजत भी नहीं है, आरक्षी को रहने का जगह नहीं है । बसंतपुर थाना 15 कि0मी0 है ।

मैंने तो माँग किया कि उसको थाना का दर्जा देते हुये भवन का निर्माण कराया जाय ताकि आरक्षी रहें, अगर वह आरक्षी सुरक्षित रहेगा तभी अपराध पर नियंत्रण कर पायेगा । जब स्वयं रक्षक असुरक्षित हो जायेगा तो अपराध में प्रगति होगी ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भवन का निर्माण कराया जायेगा और थाना का दर्जा दिया जायेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि जो प्रस्ताव एस0पी0 की ओर से आया था, उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, उसके निराकरण के लिये प्रस्ताव माँगा गया है, प्रस्ताव आने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2046 (श्री राणा रणधीर)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में पकड़ीदयाल थाना कांड सं0 07/17 दिनांक 19.01.2017 द्वारा धारा 302, 326, 307, 458, 120 बी0 भा0द0वि0 वादी मदन प्रसाद के लिखित आवेदन के आधार पर दो मोटर-साइकिल पर सवार चार

अज्ञात अपराधकर्मियों एवं अन्य के विरूद्ध ए0के0-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर चार व्यक्तियों को जख्मी कर देने, जिसमें से तीन की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई, के आरोप में अंकित किया गया है ।

पर्यवेक्षण से यह कांड प्राथमिकी नामजद/अप्राथमिक अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य पाया गया है जिसमें मुख्यतः शूटर टूना सिंह सहित कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है । तीन अपराधियों को इस कांड में रिमान्ड किया गया है । अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता पर एस0आई0टी0 का गठन कर वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के तहत कार्रवाई की जा रही है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि दो वर्षों में 44 हत्याएँ एवं 4 डकैती की घटना हुई है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि अपराध नियंत्रण हेतु शेखपुरवा रोड में पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है । कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों तथा सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0आई0टी0 टीम का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही है । इस क्षेत्र में लगातार सघन गश्ती एवं वाहन चेकिंग भी की जा रही है ।

टर्न-2/आजाद/20.03.2017

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से उस सूची के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी भी घटना के पर्यवेक्षण के लिए, उद्भेदन के लिए वहां के एस0डी0पी0ओ0 अधिकृत होते हैं सरकार के तरफ से और वे घटना का उद्भेदन करते हैं । मैं कल ही क्षेत्र से आया हूँ, मंत्री जी ने कुछ कहा है और कुछ कार्रवाई की सूची पढ़ी है । लेकिन हालत यह है कि गोली चलने के बाद अपराधियों द्वारा रंगदारी के लिए दो दिन पहले से होली त्योहार में लगातार फोन आ रहे हैं, घटना का उद्भेदन अगर सही प्रकार से हुआ है और अपराधी जिनका नाम लिया है, अगर वह पकड़ा गया है तो फिर अपराधियों का मनोबल क्या इतना बढ़ा हुआ है कि जेल से या बाहर से लगातार उनको फोन किया जा रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है .....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, पूरक यह है कि घटना का उद्भेदन ठीक से नहीं हुआ है और दो वर्षों से लगातार इस तरह की घटनायें हो रही है । एस0डी0पी0ओ0 का सरकार तीन साल में तबादला करती है । वहां के एस0डी0पी0ओ0 महोदय को चार साल हो गया है, वे ए0एस0पी0 भी बनाये गये हैं । चुनाव कार्य में उनको वंचित किया गया था उनके कार्यशैली और पक्षपातपूर्ण रवैय्या को देखते हुये । इन सब चीजों के बाद भी लगातार घटनाओं की सूची, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे यहां आये थे तो मैं उनको दी थी । डी0जी0पी0 साहेब को भी मिलकर दिया था, लगातार हर महीने .....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री राणा रणधीर : सरकार क्या वहां से डी0एस0पी0 साहब को हटाना चाहती है और सक्षम पदाधिकारी को भेजकर जो नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है । इससे लोगों के अन्दर भय व्याप्त है, इसपर कोई कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, एस0आई0टी0 का गठनकिया गया है, कार्रवाई हो रही है, दो महीना पहले की यह घटना है, अब किसको हटाया जाय और नहीं हटाया जाय, अगर उनपर कोई आरोप रहेगा तो उनको सस्पेंड किया जायेगा । नहीं हटाया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, लगातार घटनायें घट रही है और जैसा माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी ने कहा है कि वहां पर लगभग दो दर्जन हत्यायें हुई है, दिन-दहाड़े वहां पर ए0के047 का इस्तेमाल हो रहा है और जो वहां डी0एस0पी0 श्री विजय कुमार जी हैं, पिछले चुनाव में उनको हटाया गया था, इसीलिए कि ठीक तरीके से वे विधि-व्यवस्था को मेनटेन नहीं कर पा रहे थे । महोदय, क्या औचित्य है और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम नहीं हटायेंगे तो क्या ऐसे अधिकारी जो अपराध बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपराधियों से सांठ-गांठ जिस डी0एस0पी0 का है, सरकार क्यों नहीं हटाना चाहती है, क्या वजह है, सरकार की नीति है कि हम राज्य में कहीं पर 3 वर्ष पर हटायेंगे, जब निर्वाचन आयोग ने उन्हें दोषी पाया और दोषी पाये जाने के बावजूद भी आप कहते हैं कि हटायेंगे नहीं तो आखिर इसका क्या कारण है ? आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां पर अपराध बढ़े ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, स्पेसिफिक कोई आरोप हो कि यह-यह चीजें हैं, हम उसकी जाँच कराकर के ही सरकार .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई अलग-अलग आरोप, स्पष्ट आरोप है, वह सब सूचनायें माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी को दीजियेगा, सरकार उसपर विचार करेगी ।

(व्यवधान)

आप सब सूचना माननीय मंत्री जी को दीजियेगा । उन्होंने कहा है कि हम विचार करेंगे, आप दीजियेगा तब न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : 2047 माननीय सदस्य श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2047(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत जामो थाना का अपना भवन नहीं है । वर्तमान में यह थाना जामो बाजार स्थित सामुदायिक भवन में

कार्यरत है । इस सामुदायिक भवन में तीन कमरे एवं एक बरामदा है । इस भवन में थाना प्रभारी एवं पुलिस बल को कार्य करने में परेशानी नहीं होती है ।

जामो थाना भवन के भू-अर्जन हेतु 57,49,880/-रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं सम्पूर्ण राशि विमुक्त किया जा चुका है। भू-अर्जन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जामो थाना का भवन बनाया जायेगा तो कब तक बनवाया जायेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि राशि दे दी गई है, जमीन ज्यों ही अर्जित हो जायेगी तो कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, वहां जमीन उपलब्ध कराकर के सी0ओ0 भेज दिया है ?

अध्यक्ष : ठीक है, वह प्रक्रिया चल रही है न । ठीक है । प्रश्न सं0-2048 ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपलोगों ने कहा, उसपर सरकार ने कहा है कि कोई स्पेसिफिक आरोप हो तो दीजिए, सरकार उसपर विचार करेगी ।

(व्यवधान)

यहां सदन में स्थानान्तरण नहीं होता है ।

माननीय मंत्री ।

तारांकित प्रश्न सं0-2048(श्री मो0 नवाज आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में गोठहुआ पंचायत के करवाँ गांव में स्थित कब्रिस्तान खाता सं0-350, खेसरा 406, रकवा 0.24 डिसमिल इसकी कब्रिस्तान अनुमंडल स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के 131 पर अंकित है ।

प्राथमिकता सूची के क्रमांक 41 तक के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पूर्ण है एवं क्रमांक-69 तक के कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । बारी आने पर प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी की जायेगी ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमवद्ध ढंग से घेराबंदी किये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका,2014 की कंडिका 6(34) में भी 'कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना' को शामिल किया गया है ।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सारे मापदंड को कब्रिस्तान की घेराबंदी पूरा करती है, आप सेनसेटिव कब्रिस्तानों को घेरने का काम करते तो हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से पूरे आरा विधान सभा

में आपके द्वारा एक भी कब्रिस्तान नहीं घेरा गया, कब तक इस कब्रिस्तान को घेराबंदी करने का काम करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने कहा कि क्रमानुसार कलक्टर की अध्यक्षता की जो कमिटी है, वह उसका निर्णय करती है । जब इसकी बारी आयेगी तो इसको भी करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2049(श्री नारायण प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत आदर्श भवन बैरिया का निर्माण कराया गया है, जो पूर्ण है । बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा दिनांक 24.10.2016 को उक्त भवन थाना प्रभारी, बैरिया को हस्तानान्तरित किया जा चुका है ।

2 एवं 3. वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत आदर्श थाना भवन बैरिया का निर्माण कार्य की जॉच पुलिस महानिरीक्षक(आधुनिकीकरण),बिहार,पटना एवं मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से करायी गयी जॉच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भवन का निर्माण कार्य प्राक्कलन के मानकों के अनुरूप कराया गया है । चहारदिवारी का निर्माण कार्य दिनांक 29.09.2016 से प्रारंभ किया गया है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-2050(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2051(श्रीमती अरूणा देवी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

तारांकित प्रश्न सं0-2052(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत के बकुआ गांव स्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-9 पर अंकित है ।

प्राथमिकता सूची के क्रमांक-1 एवं 2 का प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी एवं 2, झंझारपुर को जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है । बारी आने पर प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी की जायेगी।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमवद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

टर्न-3/अंजनी/दि0 20.03.2017

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, लगातार घटनायें घट रही हैं और इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि दो दर्जन हत्यायें हुई हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं दिन-दहाड़े ए0के0-47 से बिहार में और इस अपराध से पूरा बिहार चिंतित है और आप भी चिंतित हैं महोदय । महोदय, मेरा आग्रह इतना ही है कि जो वहां के डी0एस0पी0 हैं, जिनको भारत निर्वाचन आयोग ने हटाया था फिर उनको लाने का क्या औचित्य था, दूसरे डी0एस0पी0 को लाते । हमलोगों का आरोप है कि जो विजय कुमार, डी0एस0पी0 हैं उनका अपराधियों से सांठ-गांठ है, संतलिप्ता है, वे अपराधियों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं, मेरा माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र बाबू से आग्रह होगा कि उनको वहां से हटाइये । सरकार की नीति भी है...

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, सरकार ने बताया कि जिस घटना का जिक्र है, उसके लिए एस0आई0टी0 गठित करके कार्रवाई हो रही है, चार पकड़ा गया है, तीन को रिमांड पर लिया गया है, सारी चीजें सरकार ने विस्तार से बताया है । जहां तक किसी पदाधिकारी के खिलाफ आरोप की बात है तो सरकार ने कहा है कि उसके बारे में सारी सूचनायें दे दीजिए, वो उसकी जांच कराकर देखेगी, अब इसके बाद आगे क्या बचता है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता यही है कि जो वहां अपराध बढ़ रहा है.....

अध्यक्ष : आपकी चिन्ता का संज्ञान सरकार लेगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, कैसे रोकेगी ?

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान लेगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: सरकार तो बोले महोदय ।

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान लेगी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष एक ही सवाल को तीन-तीन बार रिपीट कर रहे हैं, वे अपनी गरिमा को भी समाप्त कर रहे हैं । सदन में विपक्ष के नेता सरकार को सूचना दे रहे हैं, सरकार उस सूचना को ग्रहण कर रही है और स्पष्ट बात बता रही है। एक ही बात को आप बार-बार उठाइयेगा तो आपका ही मान घटनेवाला है और आपका नोटिश भी लेनेवाला कोई नहीं मिलेगा । आप उधर हाउस को डिसऔर्डर किये हुए हैं और माननीय भाजपा के नेता सत्यनारायण प्रसाद प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रतिपक्ष के नेता पर ही प्रश्न उठ रहा है कि आपके और्डर को माननीय सदस्य फौलो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से कोई बात उठाकर सदन के कार्य को बाधित कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-2053(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित छजना पंचायत पूर्णरूप से एवं रामनगर का आंशिक भाग का नियंत्रण लौकही थाना के अधीन है । वर्त्तमान समय में लौकही थाना द्वारा सतत् निगरानी तथा सघन गश्ती कर उक्त क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण रखा जाता है । छजना पंचायत के गांवों का घोघरडीहा थाना से दूरी 12-18 किलोमीटर तथा फुलपरास थाना से औसत दूरी 20-25 किलोमीटर है । लौकही थाना से रामनगर एवं छजना पंचायत की औसत दूरी 30-35 किलोमीटर है । घोघरडीहा प्रखंडान्तर्गत अवस्थित छजना पंचायत पूर्ण रूप से एवं रामनगर के आंशिक भाग को घोघरडीहा थाना के नियंत्रण में करने हेतु पुलिस अधीक्षक, मधुबनी से प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2054(श्री लाल बाबू राम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में मुरौल प्रखंड में कोई ओ0पी0 संचालित नहीं है । यह क्षेत्र सकरा थाना के अंतर्गत पड़ता है । सकरा थाना से मुरौल प्रखंड की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है । मुजफ्फरपुर पूसा रोड एवं समस्तीपुर रोड के द्वारा यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है । मुरौल में थाना सृजन हेतु पूर्ण प्रस्ताव की मांग पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से की गयी है । पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना से विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2055(श्री रवि ज्योति कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4512, दिनांक 29.08.1990 में सरकारी वाहनों के लिए 110 लीटर ईंधन निर्धारित है । वित्त विभाग के पत्रांक 6328 दिनांक 24.12.1997 एवं पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 1729, दिनांक 22.04.2000 द्वारा संवेदनशील जिलों, पटना मुख्यालय एवं भागलपुर पुलिस थानों के पेट्रोलिंग गाड़ियों के लिए प्रतिमाह डीजल की अधिसीमा प्रतिमाह 110 लीटर से बढ़कर 175 लीटर निर्धारित की गयी है । साथ-ही, उग्रवाद प्रभावित जिलों के देहाती क्षेत्रों में अवस्थित थानों के लिए प्रतिमाह 225 लीटर ईंधन एवं शहरों में अवस्थित थानों के लिए 200 लीटर ईंधन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है ।

2- अस्वीकारात्मक है

3- कंडिका-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी हे ।

श्री रवि ज्योति कुमार : महोदय, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि पूरे बिहार के थानों में 110 लीटर ही ईंधन मुहैया कराती जाती है । यह सिर्फ भागलपुर एवं पटना के लिए नहीं होनी चाहिए , पूरे बिहार के थानों के लिए होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री रवि ज्योति कुमार : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार कबतक पूरे बिहार के थानों के लिए 110 लीटर से अधिक ईंधन व्यवस्था कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो बताया है कि आवश्यकतानुसार 175 लीटर तक सीमा बढ़ा दी है ।

श्री रवि ज्योति कुमार : सर वह एस0आर0ई0 प्रोग्राम है, उसमें वह उग्रवादी क्षेत्रों के लिए है और थानों में 110 लीटर ही मिलती है । अगर कहीं होती है तो उसके लिए आवेदन दिया जाता है तब कहीं जाकर मुहैया कराया जाता है ।

अध्यक्ष : तो इसमें क्या दिक्कत है, आवश्यकता बताते हैं तो मिल जाता है ।

श्री रवि ज्योति कुमार : महोदय, उसमें लेट होती है क्राईम कंट्रोल एवं लॉ एण्ड और्डर में ।

तारांकित प्रश्न सं0–2056(श्री विजय कुमार खेमका)

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है ।

पूर्णियां जिला में केला आधारित कोई उद्योग नहीं है अपितु मक्का आधारित निम्न कुल तीन इकाई यहां है । खाद्य प्रसंस्करण के समेकित विकास योजनान्तर्गत स्थापित की गयी है । पहला– स्काई लार्क फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्णियां, राठी फीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूर्णिया, रूपम मैनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पूर्णियां । घोषित नीति के अनुरूप सरकार अपने स्तर से कोई इकाई स्थापित नहीं करती है, मात्र उद्योगों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करती है । भविष्य में अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होता है तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत सारी सुविधायें देय होगी ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि एक तो कोसी और पूर्णियां में 16.24 लाख मैट्रिक टन मकई की उपज वहां होती है ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि तीन प्लांट है मकई के बारे में, केला के बारे में नहीं । उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नहीं खोलती है, कोई अगर प्राइवेट इंटरप्रेन्योर आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सरकार उनको मदद करती है ।

श्री विजय कुमार खेमका : उसी के संबंध में कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : मैं पूरक पर आ रहा हूँ । दूसरा मंत्री जी ने कहा कि वहां केला की खेती नहीं है, जबकि रूपौली विधान सभा और धमदाहा विधान सभा क्षेत्र एवं उससे सटा हुआ बनमंखी और पूर्णियां वहां पर अत्यधिक केला की खेती होती है, मंत्री जी उसको देखवा लें और यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे वहां के प्रभारी मंत्री, कृषि मंत्री भी बैठे हुए हैं और उनके संज्ञान में है कि मक्का एवं केले की खेती वहां कितनी होती है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप जो बताये कि पी0पी0मोड पर या प्राइवेट के माध्यम से फैक्ट्री खुलेगी । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार की कोई ऐसी नीति भविष्य में है कि ताकि वहां के किसानों को उचित मूल्य मिल सके मक्का का, मजदूरों को काम मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके तो इसके लिए वहां पर मकई पर आधारित कोई उद्योग खोलने का सरकार विचार रखती है ?

अध्यक्ष : सरकार तो बता ही चुकी है ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने पहले ही कहा कि औद्योगिक नीति जो बनी है 2016 में, यदि कोई उद्मी केला पर आधारित या मक्का पर आधारित कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उस नीति का लाभ उनको मिलेगा । चूंकि सरकार कोई उद्योग खोलती नहीं है, यदि निवेशक उसके लिए इच्छुक हैं तो सरकार सुविधा देगी ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय,.....

टर्न-4/शंभु/20.03.17

अध्यक्ष : क्या ? उसमें कोई पूरक तो आप पूछ नहीं रहे हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, 1975 से लेकर 1978 में उसी जिले बनमनखी में चीनी मिल था और चीनी मिल बंद हो गयी.....

अध्यक्ष : क्या इससे संबंधित पूरक है ?

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, उसी से संबंधित है चीनी मिल वहां समाप्त हुई और ईख की खेती उस एरिया से समाप्त हो गया।

अध्यक्ष : चीनी मिल खुल जायेगा तो केला मक्का का क्या होगा ?

श्री विजय कुमार खेमका : उसी पर मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से.....

तारांकित प्रश्न सं0-2057(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के ग्राम नवागढ़ी कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्रखंड स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची के क्रमांक-8 पर अंकित है। प्राथमिक सूची के क्रमांक-6 पर अंकित कब्रिस्तान की घेराबन्दी की जा रही है। बारी अपने पर प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबन्दी की जायेगी। कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है।

तारांकित प्रश्न सं0-2058(श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-आंशिक स्वीकारात्मक है। बखरी अनुमंडल में अतिथि गृह नहीं है। अनुमंडल स्तर पर जिला अतिथि गृह निर्माण किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः बेगुसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल में जिला अतिथि गृह निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, बखरी अनुमंडल की स्थापना करीब आज से 23 वर्ष पूर्व हो चुका है। बखरी अनुमंडल में जो भी पदाधिकारी पदस्थापित हैं उनको रहने के लिए किसी प्रकार का आवास मुहैय्या नहीं किया गया है, न आवास का निर्माण किया गया है। खासकर के बेगुसराय जिला, समस्तीपुर जिला और खगड़िया जिला के सीमावर्ती क्षेत्र पर अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित है। वहां से दूसरे जिला के पदाधिकारी आनेजाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने उत्तर में जो बताये हैं उसपर पुनर्विचार करने की कृपा करते हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-2059(श्री अमीत कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान के घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-208 पर अंकित है। प्राथमिक सूची के क्रमांक 1 से 17 तक के कब्रिस्तान की घेराबन्दी हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल-1 सीतामढ़ी एवं कार्य प्रमंडल-2 पुपरी को निदेश जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा दिया गया है। बारी आने पर कब्रिस्तान की घेराबन्दी करायी जायेगी। कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराने जाने की नीति है।

श्री अमीत कुमार : महोदय, संवेदनशीलता के हिसाब से तो अभी भी दुर्गा पूजा में सबसे सेंसेटिव एरिया रहा वह रीगा प्रथम। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर उसको करा दिया जाय।

तारांकित प्रश्न सं0-2060(श्री लाल बाबू राम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के सिजाबलपुर चौक एवं सबहा चौक मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जिला की ओर जानेवाली एन0एच0 28 पर मुजफ्फरपुर शहर से करीब 30 कि0मी0 दूरी पर अवस्थित है। देहाती क्षेत्र होने के कारण वहां अभी वहां कोई ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता नहीं है। जिस कारण उक्त स्थल पर कोई प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है। उक्त दोनों चौक सकरा थाना अन्तर्गत आता है जिसकी निगरानी एवं विधि व्यवस्था का नियंत्रण थाना स्तर से किया जा रहा है। वाहनों के दबाव के कारण कभी-कभी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे थाना के द्वारा

त्वरित कार्रवाई कर नियंत्रित कर लिया जाता है। यातायात के सुगम संचालन हेतु थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षकों को समय-समय पर निदेश दिया जाता है।

श्री लाल बाबू राम : सर, वहां पर जाम रहने के कारण बराबर एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक व्यवस्था करा दिया जाता तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है।

तारांकित प्रश्न सं0-2061(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि तुर्कोलिया थाना का अपना भवन है जो पुराना है। वर्तमान में प्रशासनिक रूप से कार्य संचालित करने में कोई कठिनाई नहीं है। तुर्कोलिया थाना भवन के मरम्मति की स्वीकृति प्रदान करते हुए 6 लाख 50 हजार 35 रूपये के प्रस्ताव पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कार्य करने हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहूंगा कि वह बहुत पुराना भवन है, उसकी मरम्मति तो होती है, लेकिन जो हालात है उस थाना का संचिका बचा पाना मुश्किल है और उसके जितने भी कर्मी है उनको परेशानी होती है। दूसरा वहां हाजत का जो साइज है वह इतना छोटा है....

अध्यक्ष : तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार : हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि पुनः उसपर विचार करते हुए थाना को भवन देने का काम करें।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसको देखवा लिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-2062(श्री शमीम अहमद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा कि कैसे उसकी घेराबन्दी हो, सूची में कैसे शामिल हो मैं आग्रह करूँगा कि उसको शामिल करके घेराबन्दी करवा दें।

तारांकित प्रश्न सं0-2063(श्रीमती समता देवी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, जहां तक गया जिला के मोहनपुर प्रखंड अन्तर्गत तिलैया स्थित पंजाब नेशनल बैंक को बाराचट्टी पंजाब नेशनल बैंक में सम्मिलित करने का प्रश्न है-स्वीकारात्मक है। ग्राम ढंगरा में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा अवस्थित है जिससे ग्राम को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो रही है। उपरोक्त के आलोक में अन्य बैंक शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती समता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि बाराचट्टी विधान सभा के अन्तर्गत प्रखंड मोहनपुर, ग्राम तिलैया में पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोला गया था, लेकिन किसी कारणवश बाराचट्टी पंजाब नेशनल बैंक में सम्मिलित कर दिया गया था। इस बैंक का सर्विस क्षेत्र भोहला, धरहरा, अंकोला पड़ता है। बाराचट्टी की दूरी लगभग 10 कि0मी0 पड़ता है।

अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने तो बताया है कि ढंगरा बाजार में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत है उससे काम चल रहा है।

तारांकित प्रश्न सं0-2064(श्री राजीव कुमार ऊर्फ मुन्ना यादव)(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2065(श्री रामदेव राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, माली जाति का इथनोग्राफिक रिपोर्ट अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना से प्राप्त हो चुकी है। विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। तदुपरान्त एतद् संबंधी अनुशंसा भारत सरकार को भेजने के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामदेव राय : महोदय, 2015-16 में ही इथनोग्राफिक रिपोर्ट पेश कर दिया गया और सर्वाधिक विदित चीज है- माली जाति याद कर लीजिए सबलोग माली जाति को कि जब से मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है, तब से कृषि कार्य शुरू हुआ है किसी न किसी रूप में और कृषि कार्य में माली की अहम भूमिका रही है- पौधा लगाना, संरक्षण करना, उसको पालना पोषणा माली पर ही निर्भर करता है। आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी माली की वही स्थिति है। लेकिन आज तक उसपर कोई विचार नहीं हुआ। इसपर होना चाहिए 2015-16 से जो रिपोर्ट इनके पास पेंडिंग है क्या ये सदन के सामने पटल पर रखेंगे ? क्रमशः

टर्न-5/अशोक/20.03.2017

श्री रामदेव राय : क्रमशः.. क्या ये सदन के सामने पटल पर रखेंगे और दूसरा अविलम्ब उस पर विचार करके फाईनल करेंगे कि माली जाति को अनुसूचित जन जाति में दर्ज किया जाता है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ,मंत्री : महोदय, जो रिपोर्ट में आयी है उसमें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का जो मामला है वही क्लीयर करने के लिए कहा गया है कि किस में शामिल किया जाय, इसके प्राप्त होते ही भारत सरकार को रिकोमेन्ड कर दिया जायेगा ।

श्री रामदेव राय : मैं केवल इनफारमेशन के तौर पर कहता हूँ कि बिहार में जन जाति की संख्या सर्वाधिक कम है, बिल्कुल कम है, जो भी नौकरी मिलती उसमें भी वह आरक्षण देते हैं और वह पड़ा का पड़ा रह जाता है, अगर माली जाति को संलग्न कर देते

हैं, तो इसका लाभ हमारे बिहार को भी मिल सकता है, ये माननीय मंत्री जी को इनफॉरमेशन देना चाहता हूँ ।

डा0 सुनील कुमार : महोदय, माली जाति आर्थिक रूप से कमजोर जाति है, इसकी रिपोर्ट सरकार को वर्ष 2015-16 में ही आ गई है, कई जातियों को सरकार ने अतिपिछड़ा को अनुसूचित जाति किया है लेकिन रिपोर्ट के आने बावजूद माली जाति को छोड़ दिया गया , मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ...

अध्यक्ष : सरकार ने तो बताया कि रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति दोनों के बारे में उल्लेख है, वही सरकार स्पष्ट करा रही है कि दोनों में से किसमें जाने लायक है ।

डा0 सुनील कुमार : महोदय, दो साल हो गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2066(श्री नन्द किशोर यादव)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2067(श्रीमती वर्षा रानी)

अध्यक्ष : इन्होंने प्राधिकृत किया है माननीय सदस्य श्री रामविलास पासवान को ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री :महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत ग्राम राघोपुर की जनसंख्या 2011की जनगणना के अनुसार 5622 है, ग्राम को बिहार ग्रामीण बैंक से बैंकिग सुविधा उपलब्ध है एवं ग्राम में यूको बैंक एवं बिहार ग्रामीण बैंक की बी.सी.ए. कार्यरत्त हैं ।

3- कंडिका-2 स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाका है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृषक को और व्यापारियों को काफी दिक्कत होता हैं, अगर बैंक एक खुल जाता हैं तो कृषकों को काफी सुविधा होगी ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि दो-दो बैंक की शाखा वहां कार्यरत हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2068(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय 1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अनुक्रमांक 8450 को कुल 35.60 अंक प्राप्त था, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की पांच गुणी संख्या में अभ्यर्थियों को ड्राईविंग परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया था, परीक्षोपरान्त विभिन्न कोटि के कुल 135 सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया, अनुक्रमांक 8450 अ.पि.व. कोटि के अभ्यर्थी हैं, इस कोटि में अनुशंसित कुल 15 अभ्यर्थियों में से अंतिम स्थान पर अनुशंसित

अभ्यर्थी, जिनका अनुक्रमांक 7815 है, को कुल 38.40 अंक प्राप्त है । इस प्रकार अनुक्रमांक 8485 को कम अंक रहने के कारण सफल घोषित नहीं किया गया ।

3–कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2069(श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक है ।

2–जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला समनव्यक भारतीय स्टेट बैंक, गया के द्वारा सूचित किया गया है कि लोक अदालत में सुनवाई के क्रम में कुछ बकायेदारों के द्वारा लोन नहीं लेने की शिकायत की गई है, जिसके आलोक में जांच कराई जा रही है और जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर देने का निर्देश दिया गया है । आगे समनव्य के द्वारा यह भी सूचित किया गया हैं कि यदि बकायेदारों के द्वारा लोन नहीं लेने की बात सत्यापित होती है तो कर्ज को माफ कर दिया जायेगा ।

3– कंडिका –2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव :अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उनको नोटिश दिया गया है कर्जदारों को और उनको यदि ऐसा पाया जायेगा कि उनको लोन नहीं दिया गया है तो कर्ज माफ कर दिया जायेगा । कर्ज तो माफ कर दिया जायेगा लेकिन जो कर्ज उनके नाम पर जो लोग, बिचौलिया लोग निकाल लेते है, ऐसी घटना वहां पर एक सेन्ट्रल बैंक ऑफ जोगापुर, चितावकला में ही अवस्थिति हैं महोदय, और जब एक बैंक वहां अवस्थित है इसके बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा से वहां के दूसरे लोगों को लोन देना, इसका मतलब उससे भंयकर घोटाले का संकेत है महोदय और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल बैंक औंफ जोगापुर में ऋण घोटाला के संबंध में एफ.आई. आर. हुआ था उसमें कई लोग जेल गये थे बावजूद इस तरह की घटनायें नहीं रूक रही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार इस घटना पर त्वरित कार्रवाई के लिए कोई विशेष टीम जिसमें बैंक के अधिकारी भी हो, कमीश्नर हो, ऐसे नहीं कि कमीश्नर की जांच का आदेश दिया गया और वे अधिकृत कर दिये डी.एम. को और डी.एम. अधिकृत कर दिये एस.डी.ओ. को और एस.डी.ओ. अधिृकत कर दिये बी.डी.ओ. को .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है 15 दिन में ..

श्री विनोद प्रसाद यादव : नहीं, महोदय । बहुत ही गंभीर मामला है महोदय, वहां पर कई लोग जेल जा चुके हैं और गरीब लोगों को जब नोटिस जाता हैं तब वह संज्ञान में आता है कि मेरे नाम पर लोन हुआ है, कितना गंभीर मामला हैं तो मै चाहता हूँ कि कमीश्नर के अध्यक्षता में मंत्री महोदय घोषणा करें, क्या कमीश्नर की अध्यक्षता में इसकी वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच कराने का काम करेंगे ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, जहां तक बैंक प्रशासन का सवाल हैं, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। मगर यह शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ बैंकों की मिली भगत से ऐसे लोगों के नाम पर ऋण निकाले जा रहे हैं तो जो बैंक प्रशासन के उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनको भी निदेश दिया जायेगा और माननीय सदस्य यदि कह रहे हैं कि कमिश्नर से इसकी जांच करा दी जाय तो कमीश्नर से भी जांच करा ली जायेगी मगर हमने तो कहा कि यदि 15 दिनों में प्रतिवेदन आता है और प्रतिवेदन संतोषजनक नही होता है तो एसे भी सरकार कारवाई करती मगर जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कमीश्नर के स्तर पर इसकी जांच कराई जाय तो सभी बिन्दुओं पर कमिश्नर, मगध प्रमण्डल जो हैं उनको स्वयं इसकी जांच करने का निर्देश दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2070(श्री अजीत शर्मा)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 26.01.2017 को भागलपुर अमरपुर सड़क मार्ग को हबीबपुर थाना अन्तर्गत स्थित अम्बे पोखर की घटना के विरोध में ग्रामीणों द्वारा घंटों जाम कर दिया गया था ।

2– अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर अमरपुर मार्ग जाम होने के कारण एस.डी.ओ. भागलपुर द्वारा पिस्टल निकाल कर गोली नहीं चलाई गई, दिनांक 26.1.17 को भागलपुर अमरपुर मार्ग को ग्रामीणों के द्वारा जाम करने के उपरान्त स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीणों को समझा बुझा कर सड़क जाम को शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया ।

3– वस्तुस्थिति यह है कि उक्त स्थल पर प्रतिमा स्थापित है, सड़क मार्ग को जाम करने के विरूद्ध डेढ़ से दो सौ अज्ञात लोगों के विद्ध मोजाहिदपुर थाना काण्ड संख्या 10/17 दिनांक 26.01.17 दर्ज किया गया है । काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ये सूचना गलत है, मैं वहां गया था, वो जाम मूर्त्ति हटाने को लेकर था, मूर्त्ति हटाया गया, वहां सी.ओ. गये थे, बाद में एस.डी.ओ. गये और अखबार में यह फोटो है कि उनके हाथ में रिवाल्वर है और पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, यह बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं मंत्री महोदय इसकी जांच होनी चाहिए, आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय इनसे कि आप मुख्यालय से वरीय पदाधिकारियों से इसकी जांच करायें और जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है महोदय, आई.जी.,भागलपुर से इसकी जांच करा ली जायेगी ।

टर्न-6/ज्योति

20-03-2017

तारांकित प्रश्न सं0-2017(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में तैयार नहीं है । प्रश्नगत कब्रिस्तान के अतिक्रमण की जॉच के बिन्दु पर अंचलाधिकारी, भरगामा को नापी कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी , अररिया द्वारा लिया गया है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2072 (श्री नितिन नवीन)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि गृह आरक्षी विभाग के अधिसूचना संख्या 2/ पी-01-10-10/2012 गृह आरक्षी- 6244 दिनॉक 25-7-14 के अंतर्गत पटना नदी थाना का सृजन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 25-7-2014 से की गयी ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि पटना नदी थाने में अभी तक कुल 3 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं जिसमें से एक काण्ड नाव से बिक्री हेतु अवैध शराब लेकर आ रहे व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़े जाने से संबंधित है तथा दो काण्ड विविध श्रेणी के है । अवैध बालू खनन, गांजा, अफीम, चरस इत्यादि के तस्करी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि नदी थाना अन्तर्गत होने वाले अपराध की घटना को रोकने हेतु नदी थाना में उपलब्ध नाव/नाविक तथा थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है एवं सतत् निगरानी रखी जा रही है ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, इस थाने का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया था और माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, अभी तक कम एप.आई.आर. हुआ है जैसे हमने एक कहा तो उन्होंने दो तीन कहा । मेरा एक ही सवाल है कि इसमें दो सेक्शन होमगार्ड के दिए गए थे एस.एच.ओ. के तहत एक को लगा दिया गया बैंक में, सुरक्षा के लि ए और एक को ट्रैफिक में लगा दिया गया तो क्या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया उनके कार्यशैली पर सवाल नहीं उठता है जब थाना में अधिकारी रहेंगे नहीं फोर्स रहेगा ही नहीं तो केस करेगा कौन और अपराधी पकड़ेगा । अपराध जो पकड़ने वाले अ धिकारी होंगे ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री नितिन नवीन : मेरा पूरक प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये उद्घाटन किया गया उसकी दुर्दशा...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री नितिन नवीन : हम पूरक पूछ रहे हैं । उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेवार अधिकारी जो यह थाना की दुर्दशा है अध्यक्ष महोदय, कि एक एस.एच.ओ. के नीचे दो सेक्शन फोर्स है- दोनों अधिकारियों में से एक को ट्रैफिक में लगा दिया गया है और एक को बैंक में लगा दिया गया है तो जब सेक्शन फोर्स रहेगा ही नहीं तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन, केस दर्ज कौन करेगा तो निश्चित रुप से मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठता है और मुख्यमंत्री जी की कार्यशाली को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल है इसमें

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ ही नहीं रहे हैं ।

श्री नितिन नवीनर : पूरक पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय । मुख्यमंत्री जी के इस कार्यशैली का जो जवाब ..

अध्यक्ष : आपने 17 बार मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया, कह रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस कार्यशैली में उनके द्वारा योजनायें जो शुरु की गयी उसको इम्पलीमेंट नहीं करने के लिए जो अधिकारी दोषी है उनपर क्या सरकार कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह बहुत गंभीर है हम इसको देखवायेंगे, जॉच करवायेंगे और प्रतिवेदन मांगेंगे ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, क्या दो हजार..

अध्यक्ष : आपने देखा कि नहीं, आपने सीधा पूरक पूछा सरकार ने तुरंत रेसपौंड किया । उसी तरह का पूरक हो तो पूछिये ।

श्री नितिन नवीन : 14 जनवरी 2017 को जो घटना घटी अगर वह थाना ऐक्टिव रहा होता तो क्या उस घटना को टाला नहीं जा सकता था ? अध्यक्ष महोदय, जो दिसम्बर 2017...

अध्यक्ष : यह हाईपोथेटिकल है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2073 (श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है चूँकि पुल का नामकरण उसी विभाग ने बनाया है जिनकी प्रोपर्टी होती है वही करता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2074 (श्री अब्दुस सुबहान)

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य -अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 2075(श्री मुंद्रिका प्रसाद राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के सोनवर्षा कब्रिस्तान एवं इसुआपुर प्रखंड के अमरदह कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमशः क्रमॉक-151 एवं 167 पर अंकित है ।

सोनवर्षा कब्रिस्तान में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा अमरदह कब्रिस्तान का सीमांकन करने एवं सीमांकन के क्रम में अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्देश अंचल अधिकारी, इसुआपुर को जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा किया गया है ।

प्राथमिकता सूची के क्रमॉक-42 पर अंकित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु योजनाओं की प्रशसनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । बारी आने पर प्रश्नगत कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी जाएगी ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसीक्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2076 (श्री नंद कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यवस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

उक्त दोनों कब्रिस्तान की जमीन अतिक्रमित नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधि कारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2077(श्री अमीत कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमॉक 378 पर अंकित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक जिले के कब्रिस्तान से लेकर दूसरे जिले के कब्रिस्तान तक घूम रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : तो महोदय, प्राथमिकता सूची में नहीं है । कलक्टर की अध्यक्षता वाली कमिटी प्राथमिकता तय करती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 278(श्रीमती कुंती देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी प्रखंड के ग्राम- सरौंजी में दो कब्रिस्तान है । उसमें से एक की घेराबंदी पूर्व में विधायक मद से की गयी थी । वर्तमान में उसका कुछ हिस्सा टूट गया है । उक्त कब्रिस्तान का खाता सं0-237, प्लॉट नं0-2648, रकवा-3.31 एकड़ है ।

सरौंजी ग्राम का दूसरा कब्रिस्तान का खाता सं0-237, प्लॉट नं0-1817, रकवा-1.20 एकड़ किस्म जमीन कब्रिस्तान में ग्राम-कबीरपुर का शव दफन किया जाता

है । उक्त कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2079(श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद , मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । राज्य सरकार का राज्य में अपने स्तर से नयी चीनी मिल स्थापित करने का कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है । राज्य सरकार द्वारा राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों एवं मजदूरों के हित में राज्य में निजी सार्वजनिक, सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु प्रोत्साहन पैकेज 2006 की घोषणा की गयी थी जिसे आद्यौगिक प्रोत्साहन पैकेज के तर्ज पर और निवेश हेतु आकर्षक एवं प्रभावकारी बनाने हेतु प्रोत्साहन पैकेज 2014 की घोषणा की गयी है । किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड में वर्तमान में गन्ने की खेती मुख्य रुप से गुड़ निर्माण हेतु की जाती है । बहादुरगंज प्रखंड में चीनी मिल स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव अबतक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । यदि बहादुरगंज प्रखंड में चीनी मिल स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव किसी निवेशक से प्राप्त होगा तो सरकार उन्हें नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगा कि किशनगंज जिला पूरे बिहार में सबसे गरीब जिला माना गया है और वहाँ से किसान जो है मजदूरी करने के लिए पलायन करता है पंजाब , हरियाणा मजदूरी करने के लिए जाता है अगर जिस हिसाब से गन्ना वहाँ हो रहा है हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि अगर गन्ना मिल का कोई प्रस्ताव आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में किया जाय तो वहाँ का जो किसान गन्ना की खेती करने वाला है उसमें एक उत्साह भी होगा और गन्ना खेती जिसतरह से होता है वहाँ से किसान को मजबूरन सिल्लीगुड़ी बगल का वहाँ का इस्लामपुर में बेचा जाता है तो हम चाहेंगे कि वहाँ के किसान की परिस्थिति को देखते हुए वहाँ एक गन्ना मिल जो उद्योग होता है उसको खोला जाय ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, सरकार लगतार यह बात कह रही है कि कोई प्रस्ताव आयेगा तो सरकार विचार करेगी । अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास प्रस्ताव उद्योग के लिए आ क्यों नहीं रहा है यह तो माननीय मंत्री जी बतायें ।

टर्न–7/20.3.2017/बिपिन

तारांकित प्रश्न संख्या–2080 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड के मनियारी में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है । कार्यपालक अभियंता, कनीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 के प्राक्कलन के अनुसार ही ईंट, बालू, सिमेंट का उपयोग हो रहा है । कार्य की गुणवत्ता के संबंध में जिला पदाधिकारी ने इसे ठीक बताया है। प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य प्रगति पर है । इसे जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, क्या सरकार कब्रिस्तान घेराबंदी का ही प्राथमिकता रखता है, तो क्या गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की इच्छा रखती है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्या चीफ इंजीनियर से इसकी जांच कराने का विचार रखती है अगर सही काम हो रहा है तो?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: माननीय सदस्य के अनुरोध पर मुख्य अभियंता को भेज कर इसकी जांच करवा दी जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन के पटल पर रख दिए जाएं ।

कार्यस्थगन की सूचना

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20.03.2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं : –

1. श्री संजय सरावगी
2. श्री मिथिलेश तिवारी
3. श्री विद्या सागर केशरी
4. विजय कुमार खेमका
5. श्यामबाबु प्रसाद यादव
6. सचीन्द्र प्रसाद सिंह
7. श्री राणा रणधीर
8. श्री विजय कुमार सिन्हा

आज दिनांक 20.03.2017 को सदन में वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मॉगों [खंड–08 (परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)] पर वाद–विवाद एवं मतदान का कार्य निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन निमावली के नियम–172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपरोक्त सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय....

अध्यक्ष : अब शून्य काल चलने दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, कहने दीजिए । महोदय, होली के बाद मधवरपकड़ीदयाल में लगातार व्यवसायियों को धमकी दिया जा रहा है । रंगदारी मांगा जा रहा है और कहते हैं हत्या कर देंगे नहीं देने पर । उस परिस्थिति में महोदय, वहां डी.एस.पी. जो हैं और अभी माननीय सदस्य का सवाल भी आया था और माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम स्थानान्तरण नहीं करेंगे । तो हमारा कहना है कि वैसे डी.एस.पी. के रहते अपराध रूक नहीं रहा है, व्यवसायी से रंगदारी मांगी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है । तो माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि क्या उस डी.एस.पी. को....

अध्यक्ष : यह पूरक थोड़े ही है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः सरकार का वक्तव्य , महोदय, सरकार का जवाब हो ।

अध्यक्षः सरकार ने उस समय भी कहा था प्रेम बाबू ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः सरकार ने कहा था कि नहीं हटायेंगे महोदय ।

अध्यक्षः सरकार ने कहा था कि आपकी बातों का संज्ञान ले रही है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः नहीं, कहां ली ?

अध्यक्ष : नहीं, मंत्री जी ने कहा था ।

श्री प्रेम कुमार नेता विरोधी दलः महोदय, महोदय ...

अध्यक्ष : अब चलने दीजिए ।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

शून्यकाल

श्री अमीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, ''सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बैरगनियॉ में 21, सुप्पी प्रखंड में 9 तथा रीगा प्रखंड में 9 भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय है । अतएव जनहित में इन विद्यालयों को सरकार अविलम्ब भूमि उपलब्ध करावें ।''

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, ''गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर-सोनडीहा सड़क से ग्राम-लालगढ़ होते हुए भटकुरहा नदी तक 02 कि.मी. सड़क नहीं रहने से आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

आमजनों के कठिनाई को देखते हुए उक्त सड़क का अविलम्ब निर्माण कराने की मॉग सरकार से करता हूँ ।''

श्री मो0 नेमतुल्लाहः अध्यक्ष महोदय, ''गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के ग्राम-सरैया नरेन्द्र के खुटालीगंज बाजार पर अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर स्थिति में है और इसका भवन का छत कभी भी गिर सकता है ।

अत: सरकार अत्यन्त लोकहित में भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार अतिशीघ्र कराये ।''

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, ''मधुबनी 1975 में ही जिला बना परंतु आज तक मधुबनी सदर अस्पताल को जिलास्तरीय अस्पताल के लिये निर्धारित आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गई है । यहां 500 की जगह 185 बेड हैं । आई0सी0यू0 में 50 की जगह मात्र 5 बेड है ।

मधुबनी सदर अस्पताल में आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हों ।''

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्रीमती भागीरथी देवी

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, ''भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन अधिक दिखाया जाता है लेकिन बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन काफी कम रहती है जबकि बच्चों का भोजन पोषाहार एवं पोशाक राशि अधिक नामांकित बच्चों के हिसाब से दिखाया जाता है ।

अतएव मैं सदन के माध्यम से इसकी जॉच कराने की मॉग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ''डॉ0 रामनरेश यादव सहायक प्रधानाध्यापक सर्जरी विभाग पी0एम0सी0एच0, पटना प्रख्यात एवं लोकप्रिय सर्जन हैं । वे दरभंगा से पटना आने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त कर गये और उनका ईलाज स्पाईनल इंज्यूरी हॉस्पीटल बसंतकुंज नई दिल्ली में चल रहा है । पैसे की कमी के कारण ईलाज में कठिनाई हो रही है ।

अत: ईलाज के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।''

अध्यक्ष : श्री ललन पासवान

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री संजय सरावगी

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री विजय कुमार खेमका

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ''नालन्दा जिला अन्तर्गत करायपरशुराय प्रखंड के चौकी हुडारी के नजदीक लोकाइन नदी में शाखा नदी पर सटर युक्त छिलका निर्माण होने से आम किसानों को फायदा पहुंचेगा ।

अत: किसान हित में छिलका निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।''

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, ''बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड स्थित 'पासोपुर बसही' सड़क वर्षों से गढ्ढ़े में तब्दील है जिसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बार-बार निविदा निकाली जाती है और विभिन्न बहाना बनाकर रद्द कर दी जाती है जिससे आमजनों में भारी आक्रोश है । सरकार शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करे ।''

अध्यक्ष : श्री विनय बिहारी

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, ''सिवान जिलान्तर्गत असॉव नामक थाना लम्बे समय से नहर की जमीन में अवस्थित है । जमीन की उपलब्धता के बावजूद दूसरे-दूसरे पंचायत में स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया शुरू है जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं ।

अत: उक्त आसॉव नामक थाना को पूर्व से अवस्थित स्थान पर ही रखने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।''

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, ''औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल मुख्यालय है किन्तु यहां विद्युत प्रमण्डल कार्यालय नहीं रहने के कारण दाउदनगर अनुमंडल के जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि विद्युत प्रमंडल कार्यालय की दूरी लगभग 35 कि0मी0 है ।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दाउदनगर में विद्युत प्रमंडल कार्यालय खोलने की मांग करता हूं ।''

अध्यक्ष : श्री विद्या सागर केशरी

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, ''अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में काली मंदिर के पास अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है । जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए काली मंदिर के पास से अतिक्रमण मुक्त कराने की मॉग मैं सरकार से करता हूं ।''

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री वशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ''रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखण्ड के तेतराढ़ गॉव किसी प्रकार के पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है जिससे ग्रामीणों के आवागमन में असुविधा होती है ।

सरकार से मॉग करता हूं कि बड़हरी-धर्मपुरा पथ से तेतराढ़ गांव तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।''

(व्यवधान जारी)

टर्न : 08/कृष्ण/20.03.2017

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

शून्यकाल समाप्त हुआ ।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, जितेन्द्र कुमार एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार के किसी भी जिले में मूंग का बीज कृषि विभाग द्वारा किसानों को नहीं पहुंचाया गया है जबकि मूंग की बुआई 20 अप्रैल तक मान्य है । राष्ट्रीय बीज निगम ने बीज आपूर्त्ति हेतु निविदा में भाग लिया था, जिसका विभाग द्वारा निविदा का निपटारा नहीं किया गया । भारत सरकार के मानक के अनुरूप राष्ट्रीय बीज निगम से मूंग की आपूर्त्ति के लिये किसी निविदा की जरूरत नहीं है । एकल निविदा पर वित्त विभाग से राय मांगी थी । वित्त विभाग ने स्पष्ट लिखा है कि जरूरी स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम से मूंग आपूर्त्ति करा सकते हैं, पर विभाग की लापरवाही के कारण पूरे बिहार के किसान मूंग बीज से अभी तक वंचित हैं ।

अत: राज्यहित में किसानों को मूंग बीज की अवलिंब आपूर्त्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कल दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

अनुपस्थित । सभा-सचिव ।

याचिकाओं का उपस्थापन

सभा सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरणी के अनुसार 73 याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

परिवहन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	:	59 मिनट,
जनता दल (यूनाईटेड)	:	52 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	:	39 मिनट,
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	:	20 मिनट,
सी0पी0आई0(एम0एल0)	:	02 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	:	02 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	:	01 मिनट,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	:	02 मिनट,
निर्दलीय	:	03 मिनट ।

प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

''परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 60,05,80,000/–(साठ करोड़ पांच लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री तार किशोर प्रसाद, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं एवं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय,

राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।''

अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं सूचना एवं जनसंपक विभाग, यह तीनों विभाग इसके साथ गिलोटिन में है । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा इम्पौरटेंट विभाग है, जिसपर चर्चा नहीं कराकर इसको पेंडिंग में रखने का, तो इस सरकार पर अफसोस है महोदय, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के बजट को मुख्यपार्ट पर होना बहुत जरुरी था, इसपर बहस होना चाहिए था और इस पर बहस का गुंजाईश भी है, आप भी यह कह सकते हैं कि गुंजाईश है लेकिन अभी तक इस सदन में इस विभाग के मंत्री महोदय भी नहीं है, यह भी एक विषय बना हुआ है। खैर, अगर परिवहन विभाग के बारे में कहा जाय तो राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु सुरक्षित परिवहन प्रणाली का होना बहुत ही जरुरी है महोदय, लेकिन गौर करें महोदय तो 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में प्रस्तावित बजट में 4. 30 करोड़ अधिक है और दूसरी तरफ 2016-17 की राशि जनवरी, 2017 तक मात्र 7. 31 प्रतिशत ही खर्च हो पायी है, अब इतनी बड़ी राशि दो माह में कैसे खर्च होगी या सरेंडर होगी, यह इस सरकार की लापरवाही का एक जीता-जागता नमूना है । यही नहीं महोदय, हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने में भी विभाग अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है और तो और महोदय एक तरफ ड्राईविंग लाईसेंस में जो आम लोगों की दुर्दशा होती है, इतना लंबा समय लगता है, मिलता नहीं है और दूसरी तरफ जिला परिवहन कार्यालयों मे भ्रष्टाचार चर्चित है, व्याप्त भ्रष्टाचार है और महोदय परिवहन निगम के बस अड्डों का भी बहुत ही बुरा हाल है, कोई आम सुविधा नहीं है, चाहे वह पटना हो, या अन्य जिलों का हाल हो, यह देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त एक और विषय है महोदय कि औरंगाबाद जिले में व्यवसायी चालक प्रशिक्षण का शोध संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और यह 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक महोदय उसमें कोई चालकों का प्रशिक्षण तक शुरु नहीं हुआ । अत: महोदय चूंकि राज्य सरकार का परिवहन विभाग अपना लक्ष्य पाने में विफल है, इसलिए 10/- रुपये का कटौती प्रस्ताव कहता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये इसे स्वीकार करें और इसको अपने बजट में प्रावधान करें । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार ।

श्री राजेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा परिवहन विभाग के मांग के पक्ष में और प्रतिपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय यह सर्वव्यापी है कि राज्य में राजस्व संग्रह का मुख्य माध्यम और बहुत बडा माध्यम

परिवहन को माना जाता है । महोदय आज राज्य में अनेक प्रकार के लाभकारी योजनाओं के साथ साथ जो परिवहन विभाग में सड़क की दशा में गुणात्मक सुधार और खासकर शराबबंदी की वजह से जो राज्य में शराबबंदी लागू हुआ, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना का जो सीमा था, जो रफ्तार था, जो प्रतिशत था, उसमें काफी कमी आयी है । महोदय, इस राज्य में शराबबंदी के माध्यम से एक तरफ गरीबों के शौक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से उसमें रफ्तार आयी है, तो दूसरी तरफ सड़क की दुर्घटना में काफी कमी भी आयी है । महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को और माननीय गठबंधन के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को और उप-मुखिया भाई तेजस्वी यादव जी को, कि आज परिवहन के मामले में राज्य के प्रति जो सोच बना और उसके लिए बजट में जो प्रावधान बना, वह काबिलेतारीफ है । आज शहर में जो स्थिति बना हुआ है, खासकर पटना के शहर में परिवहन की व्यवस्था सुढ़ढ़ करने के लिए तीन अरब एक्तीस करोड़ एकसठ लाख रुपये से राजकीय टर्मिनल बनाने की योजना सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है । महोदय 39 बस स्टैंड नगर निकायों में खोलने का व्यवस्था किया गया है । महोदय, 13 शहर समुदायों के लिए 227 बसों का क्रय करके और विभाग को देने का काम किया गया है .....

(व्यवधान)

भारत सरकार बिहार से बाहर नहीं है ।

क्रमशः

टर्न्र-10/सत्येन्द्र/20-3-17

श्री राजेन्द्र कुमार(क्रमशः) महोदय, भारत सरकार का जो पैसा है वह भारत सरकार के अपने घर का पैसा नहीं है, वह तमाम भारत सरकार में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों का हिस्सा है और हिस्सा के तहत माननीय संजय सरावगी जी बोले हैं बहुत अच्छा लगा लेकिन भारत का ही पार्ट बिहार है और बिहार का हिस्सा जो चाहिए वह निश्चित तौर पर हिस्सा में जो कटौती हुई है और भारत सरकार के द्वारा जो बिहार के साथ खासकर के शौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है आपको निश्चित तौर पर बिहार के होने के नाते बिहार के तरफ से भारत सरकार पर बोलना चाहिए था । हम कहना चाहेंगे कि आज बिहार के विषय पर आप भारत की तारीफदारी सदन में करते हैं । क्या आपको बिहार के गरीबों का ख्याल नहीं है, क्या बिहार के विकास के लिए आपके दिल में दर्द नहीं है, क्या बिहार का विकास आप नहीं चाहते हैं? हम खासकर के कहना चाहेंगे अगर आप ये बात बतलायें हैं तो हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे सदन के माध्यम से कि देश की जो हालत खासकर के बी0जे0पी0 के माध्यम से जो बनाने का प्रयास हो रहा है आज कहना चाहेंगे कि देश के कोने कोने में धार्मिक उन्माद फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, आज देश को महोदय किस तरफ और किस दिशा में ले जाने का प्रयास ये भाजपा वाले लोग कर रहे हैं । इसलिए खासकर के हम कहना चाहेंगे कि आज इस देश में जो विकास की रफ्तार है उसमें बिहार अपना स्थान प्रथम रखने का काम किया है ।

हम कहना चाहेंगे कि आज बहुत सारे जिलों में जिला परिवहन कार्यालय और वहां के कर्मियों के रहने के लिए जो आवास का निर्माण कराया गया है वह काबिलेतारीफ है । हम कहना चाहेंगे कि खासकर के चालक प्रशिक्षण शोध संस्थान जो खोला गया औरंगावाद में, आज वहां कार्य प्रगति पर है और खासकर के हम कहना चाहेंगे कि बिहार राज्य में यह प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर के और प्रशिक्षण देकर के प्रशिक्षित चालकों को वाहन चलाने के लिए सरकार जो कार्य कर रही है निश्चित तौर पर यह काबिलेतारीफ है । हम कहना चाहेंगे कि आज सरकार के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा खासकर महिलाओं के हित में जो लगातार काम किया गया है आज निश्चित तौर पर आज पूरा देश उसको सराह रही है महागठबंधन की सरकार को और महोदय, बिहार में खासकर महिलाओं के लिए यह सरकार जो सोच बना रखी है हमेशा सरकार चाहती है और उस सोच के तहत महिला के आरक्षण की बात हो या खासकर के विद्यालयों में महिलाएं, बच्चियां कैसे अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति आगे बढ़ें, इसके लिए यह सरकार हमेशा काम कर रही है और उसी कड़ी में आज सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के तहत व्यवसायिक खासकर के जो व्यवसायिक तरीके से हमारी महिलाएं जो चालक के रूप में अपना निबंधन करवाती है जो उनके लिए खासकर के जो वाहन तिनपहिया है, तिनपहिया चालक के रूप में उनका जब निबंधन होता है वह टैक्सी मैक्सी इत्यादि का। हमारी सरकार के द्वारा प्रोविजन किया गया है कि जिस गाड़ी को वह चलायेंगी उस वाहन का राजस्व कर नहीं लगेगा । आपको हम बतलाना चाहेंगे, माननीय महोदय हम कहना चाहेंगे कि आज सरकार के द्वारा महागठबंधन के द्वारा जिस महिलाओं को हमेशा प्रताड़िता किया जाता था, आज यही राज्य है, यह देश है यह देश के मनुवादी सिद्धांतो के तहत यह सब किसने बोला था आज जानने के लायक है कि यह बोला गया था कि नारी और शूद्र शिक्षा के लायक नहीं, यह किस सोच के तहत कहा गया था नारी को देश को भागीदारी से अलग करने का प्रयास किया था आखिर यह महागठबंधन की सरकार ने इस चीज को देखा और देखने का काम किया और प्रयास किया । महोदय, इस देश में खासकर के जो गरीब को छांटने का प्रयास किया गया, 1990 की बात है, हम कहना चाहेंगे 90 के दशक के पहले जो गरीबों की हालत थी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था उसको दिलाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया और जब लालू जी अधिकार देने का काम किया तो लोगों को बेचैनी बढ़ी और गरीबों के राज्य, महिलाओं के राज्य को, अति पिछड़े के राज्य को, बैकवर्ड के राज्य को जंगल राज बोला गया । हम महोदय पूछना चाहेंगे विपक्ष के साथियों से कि इस देश में जो संविधान बना है इस देश के संवैधानिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार हमलोगों का, इस देश के संविधान में बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर सभी जाति और विरादरी के लिए व्यवस्था की और इस संविधान का अनुकरण आपका देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी किया करते हैं और आज विश्व स्तर पर जो आपका संविधान है उसको सराहा जाता है । आज कारण क्या है, इन गरीबों के हक के हकमारी के लिए

आप हमेशा यह कोशिश करते रहते हैं और खासकर के जो चालक के रूप में रहता है वह चालक कौन है, उसको चिन्हित करने की जरूरत है, जिनको आरक्षण खत्म करने की बात आप करते हैं उन्हीं समाज के लोग चालक हैं, अति पिछड़ा के लोग चालक हैं इनके आरक्षण को समाप्त करने की बात आप कहते हैं और जब इनके विकास की बात होती है तो महागठबंधन सरकार पर आप ऊंगली उठाने का प्रयास करते हैं । महोदय, हम कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ आज सड़क हादसे के मामले में, पहले रोड पर चलने के बाद यह पता चलता था, जब यहां से पटना से मोतिहारी की दूरी हमलोग तय करते थे, नवादा की दूरी करते थे छपरा की दूरी करते थे तो रास्ते में महोदय कितना एक्सीटेंड मिलता था, रोड पर हमेशा एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट दिखता था अगर कोई दिन किसी व्यक्ति ने पूछ दिया और उठाने चला गया तो प्रशासनिक रूप वह उठाने वाले व्यक्ति को, मदद करने वाले व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा दिया जाता था । आज सरकार मनावता के आधार पर यह प्रोविजन लायी है, यह व्यवस्था की है कि अगर रोड पर आज कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गिर कर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है तो जो व्यक्ति उसको सहयोग करता है, मदद कर के होस्पीटल तक पहुंचाता है, हमारी सरकार प्रोविजन लायी है कि वह ले जाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत भी प्रशासन के द्वारा किया जायेगा । महोदय, हम बतलाना चाहेंगे कि आज सरकार के द्वारा जो गांव के गरीब के साथ-साथ आम लोगों के लिए सोच बनायी है सरकार हमेशा चाहती है, आज स्वास्थ्य विभाग में दिन दूनी रात चौगुनी जिला स्तर पर सभी होस्पीटलों में जो स्थिति बना हुआ है, प्राइवेट होस्पीटल की स्थिति से अच्छा स्थिति जिला के सभी स्वास्थ्य विभाग होस्पीटलों का हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग पर ऊंगली उठता है । हम कहना चाहेंगे महोदय कि निश्चित तौर पर बिहार विकास के रास्ते पर है इसलिए हम विपक्ष के साथियों से कहना चाहेंगे कि सकारात्मक सोच के तहत बिहार आगे बढ़ रही है इसको आगे बढ़ने दें। इसी चीज को आधार बनाते हैं और लोकतंत्र पर निश्चित तौर पर एक प्रहार होते जा रहा है, एक हिन्दुत्व का नारा देकर के देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आखिर देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं । आज देश में एक साम्प्रदायिक ताकत उभरता हुआ नजर आ रहा है महोदय हम कहना चाहेंगे।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, डॉ0 अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय आज जो हालात बना हुआ है, यह देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह देश हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाई का देश है, इसमें आवाज देकर के गृह युद्ध के तरफ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है । हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे विपक्ष के साथियों को इस देश के गरीब के लिए जो सरकार हमेशा काम कर रही है खासकर के दलितों के लिए लगातार योजनाएं बन रही है और योजनाओं के तहत दलित आगे बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से विकास के रास्ते पर जा रहे हैं । यह देखकर के प्रतिपक्ष के साथियों का धड़कन बढ़ गया है कि जिनको हम दबाकर के सदियों से

रखे थे उसको उठाकर के खड़ा करने वाला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव उसके साथ खड़ा है । इससे इनकी बेचैनी बढ़ रही है, हम कहना चाहेंगे साथियों को कि आज लालू यादव और नीतीश कुमार जब तक हैं और उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी है जो आज उभरता हुआ नेता के रूप में हैं, इस देश के युवाओं के धड़कन के रूप में जब सामने आये हैं तो इनके बेचैनी बढ़ी है । हम कहना चाहेंगे साथियों, हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग पर ऊंगली उठाते हैं, हम प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहेंगे आप जिनके तरफ ऊंगली उठा रहे हैं वह उनके पुत्र हैं जो समाजिक आन्दोलन के आपके मंसूबे को पानी फेरने का काम किये उनके वह पुत्र हैं और समाजिक आन्दोलन के बाद आज नहीं कल आपको बतलाने का काम करेगा कि सामाजिक आन्दोलन कर के समाज को समरसता देने वाले और बराबरी का, गैर बराबरी जो आप रखे थे बराबरी का दर्जा देने वाला का सुपुत्र आज नहीं कल आपको समझाने का काम करेंगे इसलिए प्रतिपक्ष के साथियों, आज जिनके ऊपर ऊंगली उठाते हैं वह निश्चित तौर पर राजनीति के कर्पूरी, लोहिया के बीच से निकलकर के आने वाले ताकत के बीच से पैदा होकर वहां आये हैं। हम कहना चाहेंगे साथियों कि आपकी पहचान आपकी सोच इस देश को हमेशा तोड़ने की है और महागठबंधन के साथियों की सोच हमेशा इस देश में जोड़ने का है इसलिए खासकर के हम कहना चाहेंगे, आपकी आदत है, परिवहन विभाग के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसी के तहत कर्पूरी लोहिया के सोच को इम्पलीमेंट करते हुए लालू जी और नीतीश जी सामने आये। (क्रमशः)

टर्न–11/मधुप/20.03.2017

...क्रमशः ....

श्री राजेन्द्र कुमार : लालू जी की राजनीतिक रूप से हत्या करने का आपने प्रयास किया लेकिन बिहार में दो–दो लाल देकर राजनीति को मजबूत करने का काम लालू यादव जी के द्वारा किया जा रहा है । जो व्यक्ति बिहार की बागडोर सम्भाल चुके हैं माननीय नीतीश कुमार, उनका जवाब आपके पास नहीं है । हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का जवाब आपके पास नहीं है और न होगा ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : निश्चित तौर पर संवैधानिक तरीके से यह देश जो विकास कर रहा है, उसमें बिहार अव्वल तरीके से आगे बढ़ रहा है । हम कहना चाहेंगे कि राज्य में जो ओवरलोडिंग था, आज ओवरलोडिंग को भी सरकार कंप्यूटराइज्ड तरीके से रोकने का काम की है । खास तौर पर हम कहना चाहेंगे कि शहरी यातायात को व्यवस्थित करने के लिये, आप जानते हैं शहर के सामूहिक विकास के लिये आज सरकार के द्वारा 227 लक्जरी बस राज्य के सभी कोनों से चलाने का काम किया गया है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, हम अंत में एक सलाह सरकार को देना चाहेंगे ।

(व्यवधान)

आपको बेचैनी है, आपको बिहार का विकास देखकर बेचैनी है । लेकिन आप जो अंदाजा लगाये हैं, वह कभी बिहार में चलने वाला नहीं है ।

हम सरकार को सलाह देना चाहेंगे कि आज गॉव में हम जब जाते हैं, शहर में काम करने वाले, महोदय, खास करके परिवहन मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जब गॉव में हमलोग जाते हैं है तो गॉव से चलकर जो मजदूर शहर में आते हैं और रोजगार की तलाश में आते हैं, आने-जाने में उनको जो खर्च आता है, अगर मजदूरी मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है तो ठीक है लेकिन जिस रोज उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता है, मजदूरी नहीं मिलता है, उस रोज आने-जाने में उनको काफी परेशानी होती है और खर्च वहन करना पड़ता है । हम चाहेंगे कि सुदूर देहात का जो प्वायंट सब है, वहॉ से शहर तक मजदूरों को आने के लिये कोई यातायात का प्रोवीजन लाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रत्नेश सादा : माननीय सभापति महोदय, परिवहन विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, इस संसार में मनुष्य लाख - दो लाख प्रतिदिन पैदा होते हैं लेकिन इंसान कभी-कभी पैदा होता है । देश में अस्पृश्यता, छुआछूत और भेदभाव जब अधिक बढ़ गया था तो मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में भगवान बुद्ध को इस पृथ्वी पर आना पड़ा था, कबीर को आना पड़ा था, संत रविदास को आना पड़ा था, संत सुदर्शन को आना पड़ा था समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिये ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : कृपया शांति बनाये रखें । आपस में बात नहीं करें ।

श्री रत्नेश सादा : आज जब से हमारे मुखिया नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इंसान के रूप में आये हैं, तब से इन्होंने इस बिहार के सभी वर्गों के अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या महिला हो, सभी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा देने का काम किया । इतना ही नहीं, जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग को सुदृढ़ करके समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का काम किया । एक इंसान के रूप में नीतीश कुमार आये हैं ।

महोदय, नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं, कबीर की वाणी है -

''कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मॉगे खैर,
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर ।''

महोदय, नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं, उनको किसी से भेदभाव नहीं है । सभापति महोदय, हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने 2014 में, 2015 में महिला

लोगों के कहने पर उन्होंने शराबबंदी लागू किया, पूर्ण शराबबंदी । जिससे बिहार के जितने भी गरीब-गुरबा शराब के लत से प्रेरित थे, महिलाएँ परेशान थीं, आज उस घर में खुशहाली छा गई है । हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जो निश्चय लिया है, सात निश्चय के तहत हर घर नल, हर गली पक्की सड़क, पक्की नाली एवं रोजगार पाने के लिये युवाओं को एक हजार रूपया प्रतिमाह भत्ता देने का जो निर्णय लिया है, यह सराहनीय काम है ।

महोदय, सबसे ज्यादा सीख लेने का देश या विदेश के लोगों ने किया है तो मानव श्रृंखला में पूरे बिहार के लोगों ने दिखा दिया नीतीश कुमार के प्रति समर्पण की भावना को, माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच थी कि पूरे बिहार में दो करोड़ लोग मानव श्रृंखला में साथ देंगे लेकिन पूरे बिहार के लोग माननीय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी के कहने पर, 21 जनवरी को 4 करोड़ लोग सड़क पर उतर आये और शराबबंदी को पूर्ण समर्थन दिया । यह सीख लेने का काम है ।

महोदय, सड़क दुर्घटना में कमी आई है, अपराध में कमी आई है शराबबंदी से। 2006-07 से लेकर 2015-16 में हमारी सरकार को राजस्व परिवहन विभाग का लक्ष्य था 1350 करोड़, जिसके विरूद्ध 1070.97 करोड़ की वसूली की गई है । पूर्व के वर्ष में 10.8 प्रतिशत के विरूद्ध नवम्बर माह, 2016 तक कुल 787.49 करोड़ की वसूली की गई है । महोदय, सड़कों की दशा में गुणात्मक सुधार - 2016-17 माह नवम्बर तक कुल 5,11,934 वाहनों का निबंधन हो चुका है । आज आधुनिक जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया है जो अबतक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, नालन्दा, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, बाँका, मोतिहारी, रोहतास, गोपालगंज, कैमूर, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार, बेगूसराय, मुँगेर, शेखपुरा, वैशाली, पूर्णिया आदि जिलों में परिवहन कार्यालय खोला गया है और सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है । अरवल, अररिया में निर्माण कार्य प्रगति में है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहानाबाद, बक्सर, मधेपुरा, लखीसराय, सहरसा एवं औरंगाबाद जिलों में परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा । महोदय, हमारी सरकार द्वारा परिवहन विभाग में चालक का प्रशिक्षण केन्द्र एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई है ।

...क्रमशः...

टर्न-12/आजाद/20.03.2017

..... क्रमशः .....

श्री रत्नेश सादा : वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक नये क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने की योजना है । हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत जिस महिला चालकों को महिला के नाम से निबंधन दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया का है, उनको निःशुल्क टैक्सी, मोटर, मैक्सी के चालन में शतप्रतिशत कर की छूट दी गई है । महोदय, यह हमारी सरकार की नीति है । महोदय, आज सड़क की सुरक्षा पिछले दशक

से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है । सभापति महोदय, लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 वित्तीय वर्ष 2016-17 माह नवम्बर तक प्राप्त आवेदनों की कुल 9,35,685 है, जिसका निष्पादन किया गया है, जो कुल 97 प्रतिशत से अधिक है । महोदय, हमारे बिहार में वाहन प्रदूषण केन्द्र 208 है और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम शहरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नुरूम योजना से प्राप्त करीब 150 बसों का परिचालन निगम के द्वारा किया जा रहा है । इतना ही नहीं हाल ही में प्रकाशपर्व के तहत महोदय, गुरू गोविन्द सिंह महाराज के 350वें जयन्ती पर आयोजित प्रकाश पर्व के अवसर पर आगुन्तकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क परिवहन हेतु विभाग द्वारा 150 बस एवं 100 ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है, यह हमारी सरकार की सराहनीय कदम है ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य की सभी सड़कों पर बड़ी संख्या में निजी बसों का अवैध बसों का परिचालन हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इसपर थोड़ा ध्यान दीजिए । महोदय, परमीट एवं एक गाड़ी के निबंधन संख्या लेकर कई गाड़ियों का उपयोग किया जाता है । कभी तो एक ही नम्बर पर कई गाड़ी चलती है माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसपर भी ध्यान दिया जाय । वाहन मालिक गाड़ी के लिए जिस मार्ग का परमीट लेते हैं, उस मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन नहीं कर दूसरे मार्गों पर, छोटे-छोटे मार्गो पर उसका परिचालन करते हैं । इससे काफी परेशानी होती है । आज की तिथि में गांवों तक अच्छी सड़क बन गई महोदय, फिर भी बस मालिक गांवों में जाने के लिए परिचालन का परमीट नहीं लेते हैं, इसपर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सहरसा जिला में बसस्टैंडों की स्थिति काफी दयनीय है । जो आज गड्ढ़े में तब्दील हो रहा है । सहरसा जिला में बसस्टैंड को परिवहन निगम का जो स्टैंड है, उसमें सुधार करने की कृपा की जाय । महोदय, गया जिला में शेरघाटी बसडीपों की जमीन को डिविजनल मैनेजर के द्वारा कुछ खास लोगों को दे दिया जाता है, इसकी विभागीय पदाधिकारी से जॉच करायी जाय । एक ही परिवार के करीब 7-8 लोगों के नाम पर बिना विभागीय आदेश के आवंटन कर दिया गया है, जो जनहित में महोदय अविलम्ब बसस्टैंड को अतिक्रमणमुक्त किया जाय ।

सभापति महोदय, आज जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद को कुछ नेता कह रहे हैं कि सदमा में पड़े हुये हैं, टूटकर कहा था । मैं उनसे कहता हूँ कि भाई जी जिस प्रकार वहां मुँह छिलाकर के मुख्यमंत्री बने हैं, यहां से वे भी मुँह छिलाकर चले जायं वही । सभापति महोदय, दो आदमी का नाम सुने होंगे, एक आदमी को आज तक बेल नहीं दे रही सरकार, पूरे देश के लोगों ने जाना, आज उसको बेल नहीं मिल रहा है, उसका नाम है आशाराम । इनको अभी तक बेल नहीं मिल रहा है, दूसरा व्यक्ति है झॉसा राम, जिन्होंने बिहार में ही नहीं पूरे देश की जनता को झॉसा में ला करके वोट लेकर के और अपने गद्दी पर आसन होते हैं और अब पता चल गया है देश की जनता को, जिस प्रकार से आशा राम का बेल नहीं मिल रहा है, उसी प्रकार

इस झॉसा राम को देश की जनता कभी गद्दी पर बैठने नहीं देगी महोदय, यह है झॉसा राम की करतूत ।

महोदय, इतना ही नहीं आज हमारे मुखिया का जो प्रशंसा हो रहा है, उस झॉसा राम को 2019 में हमारे जो इन्सानरूपी महान मुख्यमंत्री हैं, 2019 में उस झॉसा राम को देश के सभी जनता मिलकर के उनको सुप्रीमकोर्ट से बन्द करा देंगे, उनको कभी बेल देश की जनता नहीं होने देगी । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत, बहुत धन्यवाद ।

डॉ0 सी0एन0गुप्ता : सभापति महोदय, जैसा कि हमारे मुख्य सचेतक ने कटौती प्रस्ताव पेश किया था वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ । उनकी बातों को मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा लेकिन जो मुख्य बातें हैं, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूँगा । जो बजटीय आंकड़े दिये गये हैं उनके द्वारा, वह सही है । जो हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने की बात कही गयी है, उसमें सरकार काफी पीछे है, इसपर ध्यान देना चाहिए । ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य सुविधाओं का समय पर नहीं मिलना हम नागरिकों के लिए वह उचित नहीं है, इसपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए । ट्रांसपोर्ट ऑफिसों में बिचौलियों का बोलबाला है, सरकार इसपर ध्यान नहीं दे रही है, इसपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए । जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है कि परिवहन निगम के द्वारा अधिकतर बस अड्डों का बुरा हाल है, नागरिक सुविधा का घोर अभाव है, इसपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए । राज्य सरकार द्वारा औरंगाबाद में व्यवसायिक चालू प्रशिक्षण सह शोध संस्थान के स्थापना का जो निर्माण करना है, वह अभी लंबित है, पूरा नहीं हुआ है, उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए । हमारी जो ट्राफिक सिस्टम है, उसमें सुधार की आवश्यकता है । जो ओवरलोडिंग है, उसपर कंट्रोल करना चाहिए । इसपर पुलिस की मदद लेनी चाहिए । ओवरलोडिंग से सभी जानते हैं कि यह दुर्घटना का कारण बनता है और पोल्यूशन का कारण बनता है । जिसको हमें सुधारना चाहिए । राजस्व की वृद्धि के लिए मॉझी में चेकपोस्ट, औरंगाबाद एवं गोपालगंज में चेकपोस्ट बनना चाहिए, जो पूर्ण-रूपेण कार्य रूप नहीं कर रही है, वहां लाखों रू0 का सरकार की क्षति होती है, इसपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए । जैसा कि हमको जानकारी है कि जनवरी, 2017 से ड्राईविंग लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन में काफी रूपये बढ़ा दिये गये हैं । जो ड्राईविंग लाईसेंस पहले 140रू0 में मिलते थे, अब 480रू0 में प्राप्त हो रहे हैं, जो लर्निंग लाईसेंस पहले 140रू0 में मिलते थे, वह अब 480/-रू0 मिल रहे हैं, इसपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए । पीपा पुल सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें लाईट नहीं होने के कारण आवागमन खतरे से खाली नहीं है । राज्य में ड्राईविंग लाईसेंस, ऑनर बुक एवं स्मार्ट कार्ड कई जिलों में नागरिकों को नहीं दिया जा रहा है, कई जिलों में यह बैंकलॉग काफी बढ़ा है, इसपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए । जैसा कि मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है, अगर हम स्वस्थ्य नहीं रहेंगे तो सारी चीजें बेकार साबित हो जायेगी ।

टर्न–13/अंजनी/दि0 20.03.2017

डॉ0सी0एन0गुप्ता...क्रमशः.. बड़े अफसोस की बात है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को यातायात का पूरक मानती है और गिलोटिन में शामिल करके स्वास्थ्य विभाग का बहुत महत्व नहीं रहने दिया गया ।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के द्वारा फुलवारी में एम्स की स्थापना की गयी थी तथा वर्त्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिहार को एक और एम्स दिया लेकिन अब तक राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं करायी, यह बिहार के करोड़ों गरीब जनता के साथ धोखा और अन्याय है।

महोदय, पी0एम0सी0एच0 में 112 दवाओं की जगह मात्र 12 दवायें ही गरीबों को मिल रही है, इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी सरकार को कड़ा निर्देश दिया था लेकिन सरकार ने पटना उच्च न्यायालय की अवमानना कर दी है । पी0एम0सी0एच0 के सर्जिकल डिपार्टमेंट में लेप्रोस्कोपी विभाग को अलग से स्वतंत्र रूप से प्रारंभ करना था, वह दस वर्ष पहले की बात है, जिसे अभीतक कार्यान्वित नहीं किया गया । जहां 21 डाक्टर तथा नर्सेज स्टाफ की जगह, 1 डाक्टर तथा एक नर्स के सहारे ही चल रहा है। यह सरकार की उदासीनता का परिचायक है । राज्य के अधिकांश जिलों में महिला डाक्टरों की कमी है तथा पी0एच0सी0 में तो कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं है।

महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार एवं मजदूरों के लिये कार्डधारकों के परिवार के सदस्यों की भर्त्ती होने पर 30 हजार रूपये वार्षिक उपचार की सुविधा करने की व्यवस्था है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ की सुविधा सभी पर लागू किया जाय, यह हमारा अनुरोध है ।

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये माँ कार्यक्रम के जरिये हर माह नौ तारीख या उस दिन अवकाश रहने पर दूसरे दिन देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पतालों में गर्भवती के लिये निशुल्क उपचार एवं सभी जांच उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, जो नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है, उसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

महोदय, सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पहले तीन बार हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी0पी0भी0जी0आर0एल0, सुगर, एच0आई0वी0, ऑस्टीजियन, ब्लड प्रेशर और अल्ट्रा सोनोग्राफी आदि आवश्यक जांच निशुल्क मुहैया कराये जाने की व्यवस्था की गई है लेकिन यह व्यवस्था सभी जगह पूरी नहीं की जा रही है, इसकी जानकारी दी जाय ।

महोदय, सरकार ने नौ वर्ष पूर्व आबादी के अनुरूप बेहतर इलाज के लिए पी0एच0सी0 को छः बेड से तीस बेड में तब्दील करने की योजना की स्वीकृति दी थी।

प्रथम चरण में 534 पी0एच0सी0 में 414 पी0एच0सी0 में बढ़ाने की रणनीति बनायी गयी थी, जिसमें 239 पी0एच0सी0 में बेडों की संख्या बढाने के लिये कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें 167 पी0एच0सी0 में ही 30 बेड तब्दील हुये हैं ।

सभापति महोदय, पूरे देश में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या 11,365 के लगभग है, जबकि बिहार में ही यह संख्या 2392 के लगभग है, यानी देश के कुल आबादी के 9 प्रतिशत् की आबादी कुष्ठ रोगी से पीड़ित है, वहीं बिहार में ही 15 वर्षों में बढ़कर 15 फिसदी हो गया है, इसमें उपचार की आवश्यकता है । बिहार में कुष्ठ रोगियों की समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने से कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है । इसे रोका जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार लिंगानुपात के मामले में 25वाँ स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय आसैत प्रति हजार पुरूष पर 940 महिला है। भ्रूण हत्या रोकने के लिये सरकार ने भ्रूण परीक्षण की जांच कराने के लिये अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर शिकंजा कसने का आदेश वर्ष 2015 में दिया था लेकिन यह अभी तक नहीं हो सका है, सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए ।

सभापति महोदय, पूरे बिहार में 2020 अल्ट्रासाउंड केन्द्र है, जहां भ्रूण का परीक्षण किया जाता है तथा कुछ जांच केन्द्रों में जांच में कन्या की जानकारी देने पर उसकी हत्या कर देने का धंधा जोरों पर चल रहा है । इसी आशय को लेकर सरकार सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर शिकंजा कसने का आदेश दिया है । भ्रूण हत्या रोकने के लिये सरकार जांच एजेंसी पर कार्रवाई करे । फेक अल्ट्रासाउंड बिहार के प्रत्येक जिले और देहाती क्षेत्रों में धड़ल्ले से चलायी जा रही है, सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए ।

सभापति महोदय, बिहार में कैंसर पीड़ित लोगों के इलाज के लिये, प्राथमिक कैंसर जांच के लिये सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है, न ही कैंसर का कोई एक बड़ा अस्पताल है । मुझे जानकारी है कि टी0एम0एच0 आज भी एशिया का प्रतिष्ठित प्रतिस्थान है, महाराष्ट्र की आबादी बिहार के लगभग है, यहां भी इस तरह का अस्पताल खोलने पर विचार करना चाहिए ।

सभापति महोदय, दवा घोटाला उजागर होने के बाद दो सालों से अस्पतालों में दवाओं की खरीद बाधित है । नतीजन 234 दवाओं की जगह मात्र 15-20 दवाओं से काम चलाया जा रहा है । वहां जाने वाले मरीजों के साथ ही संस्थागत प्रसव, बंध्याकरण तथा टीकाकरण की संख्या में भारी गिरावट आयी है । आप सभी जानते हैं कि जब भाजपा सरकार में थी तो अस्पतालों में न केवल लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब वह संख्या घट गयी है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें, कंक्लूड करें ।

डॉ0सी0एन0गुप्ता : हमारे छपरा जिला में शेखपुरा सब-हेल्थ सेंटर है, 10-15 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, भवन के अभाव में वह काम नहीं कर रहा है । राज्य में 20 प्रतिशत से

ज्यादा दवा बिना लाईसेंस के चल रही है, जिनके विरूद्ध कोई छापेमारी नहीं हुई क्योंकि इनके माध्यम से सरकार को महीना मिलता है । बड़ी संख्या में लाईसेंसधारी दवा दुकानों पर बड़े हास्यापद आरोप लगाकर निलम्बित कर दिये जाते हैं । इसकी जांच आवश्यक है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप समाप्त करें ।

डॉ0 सी0एन0गुप्ता : सभापति महोदय, शुरू में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य राजेश कुमार ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, इस सभा में उपस्थित सभा के तमाम् माननीय सदस्यों एवं बिहार से आये हुए तमाम् स्नेही हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, सरकार के परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके पक्ष में एवं विपक्ष की ओर से जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, वर्ष 2000 के पहले जब हमारा बिहार के साथ झारखंड का अस्तित्व था और उस अस्तित्व के साथ जब हम बिहार में थे तो हमारी सारी खनन भूसम्पदा और कई पावर सब स्टेशन जो बिजली जेनरेट करता था, जब हम वर्ष 2000 में शेष बिहार से जाने गये तो हमारे पास आय के लिए, बिहार की गरीब जनता की सेवा के लिए सरकार को बहुत बड़ी चुनौती मिल गयी और उस चुनौती में हमारे पास कहने को मात्र दो चीज रह गयी.....

....क्रमशः.....

टर्न-14/शंभु/20.03.17

श्री राजेश कुमार : क्रमशः.....हम एक तरफ उत्तरी बिहार में बाढ़ का मार झेलते थे तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ का मार झेलते थे। हमारे इस छोटे बिहार जैसे राज्य में हमारे पास इनकम का कोई स्रोत नहीं था और तत्कालीन उस समय जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री वर्तमान में भी नीतीश कुमार जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती के तहत जब हम परिवहन विभाग को देखते हैं तो वाणिज्यकर के बाद किसी के आय का स्रोत माना जाता है तो वह परिवहन विभाग है। आज के डेट में परिवहन विभाग का मूल स्रोत आय का 2015-16 में 1070.97 करोड़ वसूली किया है। हम समझते हैं कि यह गरीब जनता के आनेवाले हित का काम होगा। मैं परिवहन विभाग को बधाई देता हूँ कि ये जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़े हैं उसमें पिछले वित्तीय वर्ष से 10.8 प्रतिशत लक्ष्य में आगे हैं। तीसरी तिमाही यदि फर्स्ट तिमाही की बात करें, थर्ड तिमाही की बात करें तो अब तक परिवहन विभाग ने जो बिहार के लिए आय की वसूली की है उसमें 2016-17 के लिए 888.70 परसेंट की वसूली अब तक कर चुकी है दिसम्बर माह तक के लिए-

मैं इस पक्ष में माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी का, लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी यादव का जो ओजस्वी सोच है, बिहार को आगे ले जाने की सोच है और जिस तरह से केन्द्र सरकार के बिना कॉपरेट किये हुए अपने संशाधन से प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए इन तीनों नेताओं ने जिस तरह से राज्य को अपनी ओर मुतातिव किया है, पूरा देश आज हमारी तरफ देख रहा है और तत्कालीन जो केन्द्र के नेता थे और दूसरे नेताओं ने हमारे राज्य को एक आम सभा में कहा था कि बिहार राज्य तो बीमारू राज्य है और मैं गौरव से इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रकाश उत्सव के माध्यम से हमलोगों ने राज्य का संदेश दिया है कि बिहार की वह मिट्टी हम उस मिट्टी को लेते हैं जो चम्पारण की गांधी के धरती से पैदा होनेवाले और चाणक्य के धरती से पैदा होनेवाले लोग हैं और हम अपनी लीमिट आय संसाधन के बावजूद अपनी राज्य की जनता की सेवा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 2017-18 हेतु 1800 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य रखा है परिवहन विभाग वसूली का हम समझते हैं कि यह 1800 करोड़ इन लक्ष्य से हम यह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से थर्ड तिमाही में इन्होंने लक्ष्य का निर्धारण किया है और परिवहन विभाग 31 मार्च को जो अगले वित्तीय वर्ष में 1800 के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज हम सदन में बार-बार देखते हैं कि पार्लियामेंट में 33 प्रतिशत आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने यह पहले साबित कर दिया है कि आप 33 प्रतिशत का आरक्षण पार्लियोमेंट में पारित नहीं करोगे तो जो बिहार में प्रावधान किया गया है कि 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देकर के नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि महिला के सशक्तिकरण के लिए हम प्रावधान करेंगे और उस प्रावधान का उदाहरण परिवहन विभाग ने जो दिया है- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चालक महिलाओं के लिए निबंधन में पूरी तरह से छूट दी और यहां जानकर प्रसन्नता होती है कि बिहार जैसे बीमारू राज्य कहनेवाले लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सबक है कि यहां हमारी महिलाएं टैक्सी, मोटर कैब और मैक्सी जैसी चीज चला रही हैं। यह शत प्रतिशत परिवहन विभाग ने अपनी भूमिका देकर के और माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने जो महिलाओं के लिए जो शत प्रतिशत अपने अथी में छूट का प्रावधान किया है। हम समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण का यह सबसे बड़ा उदाहरण और सपोर्ट है। आज जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने एक तरफ सौ दिन का वादा करके और हमारे मुखिया प्रदेश के मुखिया बिना कोई वादा किये हुए सात निश्चय का योजना उन्होंने लाया है हम समझते हैं कि सौ दिन का उदाहरण दें और अपनी सरकार का उदाहरण दें तो कहीं तुलना में नहीं आयेगी। सौ दिन में एन0डी0ए0 सरकार ने जरूर किया है कि सौ दिन में एक बहुत ठोस निर्णय लिया कि जवाहर लाल विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना नाम कर दिया। आपने

योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया- और तो और इंदिरा गांधी आवासीय योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना नाम रखा है। हम समझते हैं कि सौ दिन की यदि यह उपलब्धि है तो यह जरूर है, लेकिन आप जरूर नाम बदलिये लेकिन आप जब गरीब के लिए दी गयी इन सारी योजनाओं का नाम तो परिवर्तित कर दिया। आपने बखूबी किया, लेकिन जिस तरह से आपने राज्यांश में परिवर्तन किया, आप यदि नाम बदलने में विश्वास रखते हैं तो आपको हंडरेड परसेंट राज्यांश देना चाहिए था कि आपने नाम बदला है तो हमने राज्यांश में बढ़ोत्तरी किया। आपने 90 परसेंट राज्यांश को घटाकर के 60 परसेंट किया, हम समझते हैं कि यह बिहार की जनता के लिए और बिहार के लोगों के लिए अन्याय है।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राजेश कुमार : हम यदि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से भ्रूण हत्या की बात आ रही है और जिस तरह से अभी भ्रूण हत्या पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा स्टेप लिया है । उसमें जिस तरह से भ्रूण हत्या होने के लिए लिंग अनुपात में परिवर्तन न हो, ज्यादा उसमें परिवर्तन न हो उसके लिए उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड में प्रावधान किया है हम समझते हैं कि वह काबिले तारीफ है।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : ठीक है, अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राजेश कुमार : और लिंग अनुपात पहले जानकर कि बेटी है भ्रूण में भी हत्या की जाती है उसके लिए मैं बारंबार उनको बधाई देता हूँ कि इसपर मंत्री महोदय पहल करके जो प्रयास किया है हम समझते हैं कि वह काबिले तारीफ है।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : ठीक है, धन्यवाद।

श्री राजेश कुमार : दो मिनट महोदय। अल्पसंख्यक विभाग ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है हम समझते हैं कि आपने अपने कम संसाधन से जैसा कि मैने कहा कि हमारे पास अपना कोई रिसोर्स नहीं है, हमारे पास अपना कोई संसाधन नहीं है, हमारे पास न कोई फैक्ट्री है, हमारे पास न कोई प्राकृतिक संपदा है तो हम कहां से रिसोर्सेज लाते, उसके बाद भी अल्पसंख्यक विभाग ने लाभुकों को 8743 लोगों में 89.62 करोड़ का प्रावधान करके आपने जो गरीब अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मदद किया है उसके लिए भी.....

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश कुमार : हमारे क्षेत्र का कुछ मामला है माननीय मंत्री जी के ध्यान में सदन के माध्यम से बात लाना चाहता हूँ कि हमारा कुटुम्बा विधान सभा बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर रेफरल अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है, हाल में आपके प्रयास से ऑपरेशन थियेटर भी चालू हो जायेगाा, लेकिन वहां पर अभी अल्टट्रासाउंड मशीन बंद है। वहां पर महिला डाक्टर की कमी है, सदन के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूँ। मुझे आपने सदन में जो समय दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

टर्न–15/अशोक/20.03.2017

श्री जयवर्द्धन यादव उर्फ बच्चा यादव : सभापति महोदय, वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में और माननीय विपक्ष के सदस्य के द्वारा लये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ, सदन का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद । महोदय हम सब जानते हैं कि परिवहन विभाग जो है वह लोकउपयोगी है ही साथ ही साथ ही व्यवसायिक दृष्टिकोण से बिहार सरकार के राजस्व के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हैं । पिछले वर्षों में हमारे जो औसतन जो राजस्व कमाई की जो दर हैं वह 20.48 प्रतिशत है और वर्त्तमान वर्ष में भी महोदय हमलोग अधिकतम राजस्व कमाने लिए कम से कम 10 प्रतिशत और बढ़ोत्तरी इसमें हो गई हैं महोदय, इसलिए बिहार सरकार के परिवाहन विभाग बधाई के पात्र है, माननीय मंत्री के कुशल के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्वमें यह सम्भव हो पाया है । इसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूँ महोदय । साथ ही महोदय, हम सब जानते हैं कि भारत में वाहन जो निबंधन हो रहा है, व्यवसायिक वाहन और निजी वाहन को मिलाकर के उसमें अव्वल प्रदेशों में बिहार का नाम आ रहा हैं, निश्चित रूप से परिवहन विभाग जो है महोदय इसमें अग्रेतर भूमिका निभाई है महोदय और परिवहन विभाग के माध्यम से ही यह सम्भव हो पााया हैं कि हम निबंधन के लिए भारत में अव्वल प्रदेशों में पहुंच पायें हैं साथ ही महोदय जो एक नई दिशा, नया एक पहल है महोदय, लोकउपयोगी जिसको कहा जाय, आये दिन महोदय हम सब देखते हैं पिछले वर्षो से परिवहन कार्यालय में जो स्थानीय जिला के परिवहन कार्यालय हैं महोदय, यहां पर जो फुट फॉल हैं, जो लोगों का आना–जाना हैं, विभिन्न कारणें से, चाहे चालान जमा करने के लिये हो या ड्राईविंग लाईसेंस का विषय हो, या जो भी परिवहन विभाग से संबंधित कार्य हों, फुट फाल काफी बढ़ा है महोदय । आने वालों की जो संख्या है, व्यक्तियों की वह काफी बढ़ी है, इस दिशा में सबसे उपयोगी हुआ है कि विभिन्न जिला में पिछले वर्षों में भी माननीय बिहार सरकार के नेतृत्व महोदय जो आधुनिक परिवहन कार्यालयों का स्थापना की गई हैं विभिन्न जिला में और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी महोदय कम से कम मेरे बगल का भी जिला हैं अरवल महोदय वहां पर भी हमलोग परिवहन कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं महोदय, इसके लिए भी माननीय परिवहन विभाग, माननीय बिहार सरकार को बहुत बहुत धयवाद देता हूँ महोदय । महोदय, चालक प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में वाहन चालक प्रशिक्षण जो हैं वह आज के दिन में, जिस तरह से वाहनों का परिचालन हो रहा हैं और हमारे यहां तो विशेष तौर पर चूंकि आप देख रहे हैं कि निबंधन काफी संख्या में हैं

महोदय और वाहनों का जो परिचालन हो रहा है इसलिए कुशल वाहन चालक हों, इसकी बहुत आवश्कता थी, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध भूमि में औरंगाबाद में महोदय एक चालक प्रशिक्षण सोध संस्थान की स्थापना हो रही है महोदय । यह अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल है, मारूति सूजकी से कॉलिब्रेशन करके और बिहार सराकार इसकी स्थापना कर रही है, यह सरकार की अनूठी पहल हैं महोदय और इसका लाभ जो हैं हमारे यहां रोजगार सृजन में भी मिलेगा, जो वाहन चालक हैं उनको भी यह अवसर मिलेगा कि कुशल वाहन चालक बनने के लिए प्रशिक्षण लें और जो लोग रोजगार के क्षेत्र में महोदय रोजगार के लिए भी यह अति आवश्यक हो गया है कि वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे रोजनगार भी प्राप्त कर सकें । महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महोदय, महिलाओं के लिए स्पेशल बस चल रही हैं, हमारे यहां से, पााालीगंज बस डीपों से भी माननीय जी के पहल पर महिला स्पेशल बस चल रही है, महिला की सुरक्षा के लिए आवश्क है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महोदय हमलोगों ने देखा है कि महिला जो चालक हैं उनको प्रशिक्षित करके वाहन दिया जा रहा है यह निश्चित रूप से प्रतीक हो जायेगा, महिलायें जब व्यवसायिक वाहन, बड़े वाहन को लेकर सड़कों पर उतरती हैं तो यह अपने आप में बिहार सरकार की एक अनूठी पहल है इसके लिए मै बिहार सरकार को, परिवहन विभाग को धन्यवाद देता हूं । महोदय, साथ ही सड़क सुरक्षा का जो विषय है महोदय, इस विषय में महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री परिवहन के अध्यक्षता में बिहार सरकार सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन हुआ हैं महोदय और मुख्य रूप से इसका जो लक्ष्य हैं महोदय, वर्त्तमान की सड़क दुर्घटनाओं में जो जान-माल की क्षति होती है, उसको 50 प्रतिशत गिराने का जो लक्ष्य रखा है 2020 तक महोदय यह निश्चित रूप से सबके लिए जान माल तो सुरक्षा करेगी ही और साथ में वाहनों को भी जो उनका स्पीड वगैरह हैं उसको कंट्रोल करने में काफी जागरूकता, एक वाहन सुरक्षा उससे होगा, सड़क सुरक्षा के लिए, इसके लिए बिहार सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ महोदय, इसके अलावा जो लोक सेवा अधिकार है महोदय, इसमें में भी हमलोगों ने देखा हैं कि लाखों एप्लीकेशन जो हैं सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परिवहन विभाग में आये है और परिवहन विभाग में महोदय 95 प्रतिशत से ऊपर ऐसे आवोदनों का निष्पादन कर दिया है और सफल निष्पादन किया हैं महोदय । इसके लिए परिवहन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महोदय । साथ ही सड़को को बेहतर मैन्टेन रखने के लिए और सड़को को भारी वाहन से ज्यादा क्षति नहीं हो इसके लिए मुख्य रूप से वेईंग रिजन्स की स्थापना हो रही है, कम्प्यूटर के माध्यम से जिसको कम्प्यूटराईज धर्म कांटा कह सकते हैं महोदय, इसके लिए भी जो कि मसौढ़ी में अभी स्थापित हो रही हैं और पटना, बिहटा और फतुहा में स्थापित हो चुकी हैं महोदय । हम सब

जानते हैं महादेय इस पूरे रूट पर सबसे अधिक बालू से भरे हुये जो वाहन हैं वो चल रहे हैं और ओभर लोडिंग के चलते, मेरा क्षेत्र भी इसी रूट में पड़ता है, इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज को कि ओभरलोडिंग के चलते बहुत क्षति होती हैं वहां की सड़कों की । इसलिए महोदय, निश्चित रूप से लोकोपयोगी साबित होगा और सड़कों का बेहतर रख रखाब हो पायेगा और सड़के मजबूत रहेंगी, इसके लिए परिवहन विभाग को धन्यवाद देता हूं । पर्यावरण के दृष्टि से महोदय, जो प्रदूषण है उसके लिए वाहन, आज सबसे ज्यादा अगर कोइ जिम्मेवार है तो वह वाहन हैं । प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न जगहों पर प्रदूषण जांच केन्द्र वगैरह बैठाया गया है, जिसकी सख्या 208 है, इसके लिए बिहार सरकार को, परिवहन विभाग को धन्यवाद देता हूं महोदय । निरूम के अन्तर्गत जो अरबन रूरल मीशन के अन्तर्गत 150 बसों का परिचालन, सफल परिचालन हो रहा हैं इसके लिए भी परिवहन विभाग बधाई का पात्र है महोदय । साथ ही महोदय सबसे महत्वपूर्ण अभी जो प्रकाश पर्व आयोजित हुआ था पटना में, गुरू गोविन्द सिंह जयन्ति के अवसर पर, इसमें अगर किसी ने सफल और बहुत जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निभाई है तो परिवहन विभाग ने निभाई है । श्रद्धालुओं के परिचालन के लिए करीबन 150 बसों का सफल परिचालन किया गया, पूरे प्रकाश पर्व का जो एरिया था उसमें और श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई । इसकी ख्याति, प्रकाश पर्व का जो आयोजन हुआ इसकी ख्याति देश प्रदेश सब जगह गई महोदय, इसके लिए परिवहन विभाग ने बहुत ही सफल भूमिका निभाई हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। ई-रिक्शा और जलयान का भी परिचालन हुआ था, इसके लिए भी परिवहन विभाग को, राज्य सरकार को महोदय धन्यवाद । साथ ही

सभापति(डा. अशोक कुमार): अब आप कंक्लूड कीजिए ।

श्री जयवर्द्धन यादव उर्फ बच्चा यादव : अपने क्षेत्र को लेकर एक आग्रह होगा कि करीब पचास वर्ष पुराना मेरा पालीगंज बस डिपो है, मैंन पूर्व में माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को रखा था, तो मेरा आग्रह होगा महोदय कि बस डिपों भवन का जिर्णोधार करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करें । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डा. अशोक कुमार): धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, मुझ को वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट भाषण पर बहस में भाग लेने के लिये आपने जो मुझको समय दिया इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं । परिवहन विभाग पर बोलने का अवसर मुझे दिया गया है, महोदय परिवहन विभाग मानवीय जीवन की विकास के लिए बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती हैं । परिवहन विकास का जो भी रास्ता बिहार में अभी खुला है जिसके चलते व्यवसायिक रूप से शिक्षा में, सारे जगह जो गांव के भी लोग हैं, ये परिवहन सुविधा उपलब्ध होने से लोग को शिक्षा भी मिल रहा हैं लोगों का स्तर भी बढ़ रहा है और जिस रूप में

बिहार सरकार का मनोयोग हैं, बिहार सरकार की मानसिकता है आदरणीय मुख्यमंत्रीजी की जो दृष्टि हैं, बिहार की स्मिता, बिहार की दृष्टि, बिहार की पौराणिक गाथा बिहार की अपनी इतिहास का उन्नत कायम करके देश में और दुनिया में पुनः अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया । परिवहन विभाग के साथ बिहार का अपना जो चिन्तन था, बिहार के बारे में जो सोच था वह बदला है । बिहार आज देश और दुनिया में क्रमशः

टर्न-16/ज्योति

20-03-2017 क्रमशः

श्री लक्ष्मेश्वर राय : बिहार आज देश और दुनिया में जिस बिहारी के नाम पर लोग बिहारी के नाम से लोग सकुचा जाते थे । आज लगता है कि बिहारी के नाम को देश और दुनिया के लोग प्रतिष्ठा से देखते हैं । राज्य का कानून होता है और राज्य का मुखिया जो होता है उनके व्यक्तित्व से, उनके चिंतन से, उनकी सोच से राज्य का नक्शा और उसके मानचित्र का प्रदर्शन होता है । आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमको लगता है कि देश में बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है । परिवहन विभाग के साथ साथ सारे विभाग के विकास का रास्ता खुला है । हम खास कर बिहारी के बारे में कहना चाहते हैं और हम खास कर विरोधी दल के नेता और विराधी पार्टी के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अपनी अस्मिता बदलिये । आज देश की जो परिस्थिति है उसमें सारे लोग मिल कर बिहार को बनाईये नहीं तो जो बिहार अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी से और उनके सत्याग्रह शताब्दी समारोह से हमको सीख लेनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी के चम्पारण सत्याग्रह से बिहार ही नहीं बल्कि इस देश में आजादी के आन्दोलन को एक मजबूत आधार मिला और बिहार से उस राष्ट्रीय आन्दोलन को, आजादी के आन्दोलन को बड़ी मजबूती मिली लेकिन आज गांधी जी की स्थिति है, जो सत्य अहिंसा के पुजारी हैं लेकिन आज लगता है कि देश की स्थिति डांवा-डोल है । देश की स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव होता है तो बम फूटता है, चुनाव होता है तो आतंकवादी पकड़ाता है । चुनाव से पहले नहीं पकड़ाता बाद में पकड़ाता है, हमारा कहना है कि ये गांधी जी के प्रयोग की जो धारती रही, कर्म की जो धरती रही है, गांधी जी के साथ हमारे जो बुद्ध की धरती रही और बुद्ध के बाद महावीर जी का यह कर्म क्षेत्र रहा है । आज गया, नालन्द की दुनिया में जो प्रसिद्धि थी, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यह प्रसिद्धि पुनः कायम हो रही है । हम चाहेंगे विरोधी दल के नेता जी से या विरोधी पार्टी से कि इस अस्मिता को बनाईये कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी देश में अपना परचम फहरायेंगे चाहे परिवहन का मसला हो या स्वास्थ्य का मसला हो । यह ठीक है कि विधान सभा के अंदर में लड़ाई लड़नी चाहिए लेकिन बाहर में जो हमारी बिहारी अस्मिता है, बिहारी जो हमारी

सोच है वह निश्चित रुप से मजबूत रहे लेकिन वह कमजोर हो रहा है । आज आप देखिये कि चम्पारण्ण सत्याग्रह आन्दोलन – चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह पर गांधी जी को याद करते हैं । निश्चित रुप से आजादी के बाद और आजादी में बिहार की बड़ी भूमिका रही है । एक पर एक हमारे नौजवान हंसते हंसते शहीद हो गए । देश की आजादी में बिहार की बड़ी भूमिका है । भगत सिंह जी के, देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में, तो बिहार ने उनके कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेज को भगाने में देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभायी है लेकिन आज बिहार अपने नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से, नीतीश कुमार जी के परिश्रम से आज मजबूत स्थिति में है । आप सबों को चाहिए कि बिहारीपन को मजबूत करिये । आने वाले समय में गांधी जी की कर्म क्षेत्र हो, चाहे यह बुद्ध का क्षेत्र हो, महावीर जी का क्षेत्र हो यह पुनः हमारा बिहार देश में सर्वोच्च राज्य में विकसित राज्य में, सुन्दर राज्य में अपने को स्थापित कर पाये । आज जो स्थिति पिछले दिन लखनऊ में हुयी कि चुनाव के समय में बम फूटा, चुनाव के समय में आतंकवादी पकड़ाता है तो कहीं न कहीं दोष है भाई । आज गांधी जी, जो सपना सपनाए थे, सपना में सोचते थे कि हमारा देश बड़ा सुन्दर होगा । योगी का नहीं यह संत का होगा । लेकिन आज देश में वैसे लोग आ रहे हैं कि देश की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की गरिमा भी नहीं बचा पा रहे हैं । नीतीश कुमार जी अपनी गरिमा के चलते देश और दुनिया में प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए जाने जाते हैं लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सबसे बड़ी शासक पार्टी आज देश के संविधान से लेकर और उसमें हमारा जो मौलिक अधिकार है धर्मनिर्पेक्षता का, उसको भी कमजोर करने में लग गए हैं । देश की स्थिति बहुत खराब है । देश का जो मौलिक अधिकार है, धर्म निर्पेक्षता है, वह लगता है कि तार तार होने की स्थिति में है । आप देख लीजिये दिल्ली की स्थिति, आज देख लीजिये उत्तर प्रदेश की स्थिति जब चुनाव होता था तो शासक पार्टी के अध्यक्ष बोलते थे कि इस पार्टी के वर्कर को मैं टांग के बांधूगा यह कौन कानून है आप रिऐक्शन कराके, आप धर्म को बांटकर यदि आप चाहते हैं कि राजनीति करे, सत्ता में आये तो बहुत लम्बा नहीं चलेगा । सत्ता में जरुर आप आ जायेंगे लेकिन देश टूट जायेगा । यह भारत देश है यहाँ हिंदु मुस्लिम सिख इसाई आपस में है भाई । यह सबों का देश है । यह महात्मा गांधी का देश है । यह भगत सिंह का देश है। यह चन्द्रशेखर का देश है । आपने आजादी में नहीं योगदान दिया आपने आजादी में अपना खून नहीं बहाया । आपके परिवार के लोग आपके वंशज के लोग आजादी में भूमिका अदा नहीं किए । क्या होगा उस इतिहास को आप देखिये और परखिये । हम आप सबों से चाहते हैं कि यदि चाहते हैं कि भारत बचेगा तो उसके बाद कहते हैं कि हम बिहारी के साथ साथ हम गौरव के साथ कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, ठीक बात है कि जो अभी भारत की स्थिति है निश्चित रुप से

पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हैं कि भारत की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी इसीलिए सहिष्णुता जिसपर पूरी भारी बहस चली देश में आज चूर चूर हो रही है । बिहार एक मिसाल है, बिहार एक इतिहास है जो पौराणिक इतिहास के साथ था । नीतीश कुमार का एक इतिहास कायम है, नीतीश कुमार, यदि धर्म के बारे में सीखना हो तो नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए । प्रकाश पर्व महोत्सव हुआ सिख धर्म का जो उनके गुरु थे उनके बारे में सारे बिहार के लोगों ने प्रकाश पर्व को देखा है । बिहारियों कों और बिहार के आदरणीय मुखिया को दुनिया में प्रतिष्ठा मिली इसीलिए प्रतिष्ठा मिली की धर्म, सहिष्णुता सीखाता है, धर्म आपसी मेल भाव सद्भाव सिखाता है । धर्म नहीं कहता है कि लड़ाओ, धर्म नहीं कहता है कि एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछालो । धर्म कहता है कि धर्म वह है जिसके अंदर में मानवीयता हो । धर्म वह है, धर्म तो राजनीतिक धर्म होना चाहिए कि जिस धर्म के नाम पर जिस संविधान के नाम पर हम शपथ खाते हैं उस संविधान के प्रति दायित्व होना चाहिए । जवाबदेह होना चाहिए । लेकिन आज हमारा देश की जो शासक पार्टी है और शासक जो प्रधानमंत्री जी हैं वह आप देख लीजिये, हम सबों से कहना चाहते हैं कि बिहार में कि सभी जनता और यहाँ आदरणीय माननीय सदस्य से कि सचेष्ट हो जाईये कि आने वाले समय में बिहार का भी वैसा ही रुप चाहते हैं । आज हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस रुप में बिहार के विकास के मोड्ल के साथ साथ सहिष्णुता, शांति, अमन चैन जो कायम किए हैं उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं विरोधी पार्टी के लोग इसीलिए इस तोड़ने को बचाने के लिए आक्रामक होना चाहिए । आपको भी निश्चित रुप से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए । कानून का गलत रुप में वे लोग प्रयोग करते हैं । आपने देखा पिछले दिन कि बढ़िया से भगवा का कपड़ा पहने हुए हैं लेकिन कुर्सी उल्टाते हैं यह कौन धर्म हैं ? मंदिर जाते हैं तो आस्तिक बन कर जाईये केवल पूजा से मंदिर नहीं होगा, निष्ठा और ईमानदारी से होगा । आपने अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने कर्त्तव्य के प्रति यदि आप जिम्मेदार हैं तो धार्मिक व्यक्ति हैं । धार्मिक व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं जो प्रकाश महोत्सव मनाकर दुनिया को दिखा दिया कि धर्म मानवता के लिए होता है, धर्म देश के लिए होता है । धर्म इन्सानियत के लिए होता है और एक दूसरे को खुशी देने के लिए होता है खुशी छीनने के लिए नहीं होता है । ये चिंता की बात है देश में कि आने वाले समय में धर्म को ही नहीं ये लोग जो उस शब्द को कहिये अहंकार या उस शब्द का यह रुप कि हिन्सा करके ये लोग चाहते हैं इस मुद्दा को गलत तरीका से बढ़ायें, जनता क्या सोचेगी मैं किस रुप में इन लोगों को भेजा, वे कराहते होंगे । कराहते इसलिए कि याद करिये कि हमारे जो अभी कृषि मंत्री है बिहार के केन्द्र सरकार में कभी किसान के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर खेत में हम सिंचाई की सुविधा देंगे । हम बिहार

को विशेष पैकेज, हम बिहार को विशेष सुविधा देंगे लेकिन कहाँ चला गया उनकी सुविधा । उनकी सुविधा कहाँ चली गयी? उनकी सुविधा- अब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं । अब वे बेचारे गुजरात चुनाव की तैयारी में लग गए तो यह नहीं चलेगा । देश में धर्म होनी चाहिए संविधान की जो रक्षा करेगा, संविधान के दायरे में जो रहेगा वह व्यक्ति देश का सर्वोपरि और धर्म के लायक होगा । लेकिन आज धर्म चूर-चूर हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से आज सीखना चाहिए खास कर धर्म को मानने वाले से कि दूसरे धर्म का सम्मान करो, आपका भी सम्मान बढ़ेगा और जो गांधी जी का सपना था, जो अम्बेदकर का सपना था, लोहिया और जे.पी. का सपना था, वह पूरा होगा और राम महोदय, सभापति महोदय, राम मर्यादा के ....

(व्यवधान)

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : जरा धैर्य से सुना जाय । आप सुनिये न । उनकी बात सुनिये । आपको मौका मिलेगा । शांति । आपको मौका मिलेगा । आप भी अपनी बात कहियेगा । बोलने दीजिये उनको ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाये जाते थे । इस देश का रामायण रामचरितमानस में यदि धार्मिक हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा पात्र है, एक पात्र है तो राम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता था।

क्रमशः

टर्न-17/20.3.2017//बिपिन

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः जिसको लोग, मर्यादा पुरूषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं । लेकिन राम को मानने वाले अपने मर्यादा को खतम कर दिया । राम की जो मर्यादा थी, राम का जो चरित्र था, वह आज चकनाचूर हो रहा है । अब राम नहीं, जय श्रीराम धर्म के लिए, ये राम मर्यादा पुरूषोत्तम जो अपनी पितृ भक्ति, अपनी श्रद्धा भक्ति । राम सत्ता के लिए ....

सभापति : माननीय सदस्य शांति बनाए रखें ।

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: अरे यार, यह व्यवस्था बंद करिए ?

सभापति(डा0 अशोक कुमार): यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: महोदय, राम मर्यादा के लिए दुनिया में जाने जाते हैं ....

सभापति(डा0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : दो मिनट सर । राम मर्यादा के लिए दुनिया में जाने जाते हैं । लेकिन राम कहां चला गया, जय श्रीराम का ईंटा ? राम, जय श्रीराम का नाम अब सत्तावादी हो गया, भोगवादी हो गया । अब ये लोग संत नहीं, महंत हो गए । यह कैसे चलेगा ? देश

का संविधान खतरे में है, देश की एकता-अखंडता खतरे में है । इसीलिए आज एक ओर देश को बचाने में ....

सभापति(डा0 अशोक कुमार): आप आप समाप्त कीजिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकताबद्ध हो इस देश में लड़ाई लड़े । इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विनोद कुमार सिंह: सभापति महोदय, आज सदन के अंदर सरकार के द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 47, 20, 30 एवं 24 के विरूद्ध जो कटौती प्रस्ताव रखी गई है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : 10 मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री विनोद कुमार सिंह: जी ।

सभापति महोदय, मैं विषय से विषयान्तर होना नहीं चाहता और विषय पर ही हम चर्चा करना चाहेंगे और बाद के वक्ताओं से भी अपील करेंगे कि विषय से विषयांतर होना नहीं चाहिए, यह आग्रह है हमारा ।

आज जो बिहार के अंदर में पिछले चुनाव में चर्चा थी कि बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है....

(व्यवधान)

बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है, इसकी सच्चाई परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जो खस्ताहाल है, उस पर हम चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं ।

(व्यवधान)

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : बैठे-बैठे मत बोलिए । सरावगी जी, आप पुराने सदस्य हैं ।

श्री विनोद कुमार सिंह: सभापति महोदय, जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग सभापति महोदय, हालांकि मूल सब्जेक्ट जिस पर माननीय मंत्रीजी का जवाब आना था, वह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आना था लेकिन आपने अगवा कर लिया है परिवहन विभाग को और परिवहन विभाग से ही हम प्रारंभ करना चाहेंगे ।

परिवहन विभाग से ही हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो बिहार के अंदर में परिवहन विभाग में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो लगाने की चर्चा की गई थी और आज डी.टी.ओ. डिपार्टमेंट के द्वारा उसपर लगाया नहीं गया और उसके अंदर में घोर धांधली ही व्याप्त है । हम चर्चा करना चाहेंगे परिवहन विभाग पर और माननीय मंत्री जी अपने सवाल के जवाब में उत्तर देंगे कि औरंगाबाद में जो कॉमर्शियल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 2015 तक खोलना था और उसका इस्टिमेट भी बढ़ता जा रहा है और आजतक वह ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना तक नहीं हो सका औरंगाबाद के अंदर में ।

सभापति महोदय, परिवहन निगम का जो हाल है, बेहाल है । राज्य के अंदर, जैसे कि हम कटिहार से आते हैं और कटिहार से पटना आने में शहर से 330 कि0मी0 की लम्बी दूरी तय करके आते हैं और थोड़ी-थोड़ी त्रूटियों के कारण परिवहन राज्य निगम की जो बसें हैं, जहां-तहां पड़ी हुई रहती है । क्यों नहीं कम खर्च में उसको

मौटरेबुल बना दिया जाए ? यह मेरा आग्रह है माननीय परिवहन विभाग के मंत्रीजी से । पूरे राज्य के अंदर में बसों की जो स्थिति है, हालांकि माननीय विधायक लोग तो बस पर चढ़ कर सफर नहीं करते, चढ़ कर सफर करना चाहिए । राज्य के अंदर प्रत्येक जिलों के मुख्यालय के अंदर जितने भी बस स्टैंड स्थापित किए गए हैं, उधर से आप जाएंगे, तो माननीय विधायक दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि आपको या तो सीसा बंद करना पड़ता होगा या तो नाक बंद करना पड़ता होगा । शौचालय का वही हाल, लैट्रीन-बाथरूम का वही हाल, यात्री शेड में बैठने का वही हाल और जबर्दस्ती से बस के अंदर में, जीप के अंदर में सवारियों को गर्दन पर हाथ देकर और उसका झोला-झक्कर छीनकर उसको बैठाने का काम और उछलता हुआ बस पर बैठाने का काम, क्या आपको सुधार लाने का काम नहीं करना चाहिए ? इस राज्य के अंदर में परिवहन विभाग के बस अड्डों को ठीक करने का आप इरादा रखते हैं ?

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहेंगे और यह भी कहना चाहेंगे कि ये अपने जवाब में इन बातों की चर्चा करेंगे । ओवरलोडिंग ट्रक ठीक है कि शराबबंदी में भारतीय जनता पार्टी ने आपका समर्थन किया और बिहार के अंदर, देश के अंदर में भी शराबबंदी होना चाहिए लेकिन शराब पीकर चढ़ने वाले जो ड्राइवर लोग थे, उसमें बंदिश हुआ है लेकिन ओवरलोडिंग के कारण जो एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होते रहती है, इसपर आपका ध्यान और ख्याल नहीं है । आप देख लीजिए, आज परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग एक साथ बैठे हुए हैं । हम आपके माध्यम से सभापति महोदय, बोलना चाहेंगे कि आज हम स्वास्थ्य विभाग पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे । स्वास्थ्य विभाग पर यह चर्चा करना है हमें कि लिखा रहता है कैलेंडरों में- स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है । फैमिली प्लानिंग कराकर स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, यह भी चर्चा किया कि पहला बच्चा अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं । क्या जांच कराएंगे सदन के अंदर में ? सदन के अंदर में जांच कराने के लिए आप तैयार हैं ? यहां तो पांच-पांच, दस-दस बच्चे क्या, बिहार के अंदर में एक-एक व्यक्ति को 17 से 20-20 बच्चा है । उसका फैमिली प्लानिंग नहीं होता है और जिसका दो और तीन बच्चा है उसका फैमिली प्लानिंग किया जाता है । इस पर भी समान भाव, समान कानून होना चाहिए ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): शांति । शांति ।

श्री विनोद कुमार सिंह: सभापति महोदय, आज राज्य के अंदर हम बताना चाहेंगे सभापति महोदय आपके माध्यम से कि आज प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारियों को भी नीली बत्ती । स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । बिहार के प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारियों को भी नीली बत्ती और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस में भी नीली बत्ती । नीली बत्ती । सभापति महोदय, जब हमलोग कहीं ट्रैफिक जाम में फॅसे हुए रहते हैं तो उसमें माननीय मंत्री जी का भी गाड़ी फॅसा हुआ रहता है । पीछे से एम्बुलेंस सायरन देता हुआ जब आता है, तब मंत्रीजी कहते हैं कि यह कहीं-न-कहीं रोगी का है,

रोगी का है, जरा-सा इसको रास्ता दे दो और जब रास्ता दिया जाता है और मंत्री के गाड़ी के आगे जब एक सिविल एस.डी.ओ. की गाड़ी गुजर जाती है, तब तो लगता है, कहते हैं कि यह तो एस.डी.ओ. गया, यह तो डी.एम. गया । आपका हालत वही है कि ट्रैफिक जाम में जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाना आप चाहते हैं तो आपका भी वही हाल हो जाता है जो हाल जेनरल पब्लिक का होता है ... क्रमशः

टर्न-18/कृष्ण/20.03.2017

श्री विनोद कुमार सिंह (क्रमशः) इसलिए मेरा यह आग्रह है कि प्रशासन के गाड़ियों से नीली बत्ती को हटाना चाहिए तब लगेगा कि मरीज है नहीं तो समझेंगे कि बिहार के अंदर सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पेशेंट हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग का जो हालत है, इस सदन के अंदर गोल-गोल भाषण दिये जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? बिहार के अंदर सरकारी अस्पतालों में आप चले जाय, आउट डोर और इनडोर के अंदर दवाओं की कितनी कमी हो गयी है ? जब से इस राज्य के अंदर दवा घोटाला हुआ है, आप पी0एम0सी0एच0 के अंदर चले जायें, वहां जो दवा का हाल है स्वास्थ्य मंत्री जी, हम चर्चा करना चाहते हैं, आउट डोर में 65 दवा दिये जाने का सरकार का प्रावधान है लेकिन पी0एम0सी0एच0 के आउट डोर में मात्र 7 दवायें एवेलेबुल है । जहां आप को मुफ्त दवा 33 देनी चाहिए ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, इनडोर में 127 दवायें रहनी चाहिए लेकिन पी0 एम0 सी0 एच0 के अंदर मात्र 32 दवायें एवेलेबुल हैं । यह कौन पूरा करेगा ? बिहार के अदंर जो सरकारी अस्पताल हैं, आपने चर्चा की थी कि चार सालों में बिहार के सभी जिलों में हम मेडिकल कॉलेज स्थापित करा देंगे ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): आप कंक्लूड कीजिये ।

श्री विनोद कुमार सिंह : इस बिहार के अंदर मात्र एक एम्स फुलवारी शरीफ में है । आप ने जमीन नहीं दिया इस बिहार के अंदर एम्स की स्थापना के लिये, जिसके कारण दूसरा एम्स बन कर तैयार नहीं हुआ । आज बिहार के मरीजों का क्या हाल होता होगा ? राजा और रंक दोनों को बराबर होना चाहिए । लेकिन राजा के पेट में दर्द होगा तो दिल्ली में एम्स में इलाज करायेंगे, कैंसर होगा तो बंगलोर और मुम्बई चले जायेंगे, हार्ट और ब्रेन में परेशानी होगी तो बंगलोर चले जायेंगे, ब्रेन में एक्सीडेंट होगा तो वह सिल्लीगुड़ी चले जायेंगे । लेकिन एक गरीब का बेटा 500, 600 किलो मीटर, जो पटना के दूर-दराज इलाकों में रहते है, उसका क्या हाल होता होगा ?

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री विनोद कुमार सिंह : सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आप का समय समाप्त हो गया है ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अभी समय समाप्त नहीं हुआ हैं महोदय । सात निश्चय में स्वास्थ्य विभाग को नहीं रखा, सात महीने के अंदर सात निश्चय को आप ने सात समुंदर पार कर दिया । बिहार का कतई विकास नहीं हो सकता है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): आप समाप्त कीजिये ।

श्री विनोद कुमार सिंह : राजा और रंक का एक समान इलाज कराना चाहते है स्वास्थ्य मंत्री जी तो माननीय मुख्यमंत्री से समझौता करके ऐसा उपाय हम सब मिल बैठ कर करें कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में इलाज कराने के लिये आयें तभी बिहार का कायाकल्प हो सकता है नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): धन्यवाद । मा0स0 श्री अमीत कुमार ।

श्री अमीत कुमार : सभापति महोदय, आज मुझे परिवहन विभाग के बजट के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने का मौका मिला है । आज जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके बारे में हम ज्यादा बताना नहीं चाहेंगे । बिहार की जनता जान रही है और जागी हुई है, जिसका जवाब उन्होंने पिछले चुनाव में दिया । आज जो परिवहन विभाग काम कर रहा है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है । आज हर जिला में जाकर देखिये, एक सुंदर और आकर्षित कार्यालय का निर्माण किया गया है, जो करीब 20 जिलों में बन चुका है, अगले साल 6 जिलों में पूरा होने जा रहा है, हमको लगता है कि अगले 5 साल में सभी जिलों में बन जायेगा । आज हर जिला में जहां परिवहन नहीं था, वहां माननीय मंत्री जी ने बस उपलब्ध कराने का काम किये हैं । हमारे भी विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध कराया है । मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बैरगनिया से चार-चार बसें उन्होंने दी है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सीतामढ़ी सीता जी की जन्मभूमि है और सीतामढ़ी से पटना आने-जाने के लिये एक भी सरकारी बस नहीं है । इसलिए वहां सरकारी बस देने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जहां से इतिहास लिखा गया, रामायण में भी सीता जी का जिक्र है और सीता जी के कारण रामायण बना है ।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में परिवहन विभाग में 25 परसेंट के आस-पास वृद्धि हुयी है नीतीश जी के नेतृत्व में और आगे भी होगी । पिछले साल जहां कि 13.5लाख करोड़ के विरूद्ध करीब 10 हजार 70 की वसूली की गयी है। इस साल भी 15 लाख करोड़ का टारगेट है, जिसमें हमारी सरकार 6 माह के अंदर 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरी कर ली है और हमको लगता है कि इसको अगले 6 माह में पूरा कर लिया जायेगा । आप कहीं जाते हैं तो आप महिलाओं को वाहन चलाते हुये देखते होंगे । महिलाएं अपना जीविकोपार्जन करना चाहती है तो हमारी सरकार ने उसको मजबूत करने का काम किया है और उनके टैक्सी, ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में जो खर्च होता है, हमारी सरकार ने मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है और यह माननीय नीतीश

कुमार जी के नेतृत्व हुआ है । यह सराहनीय कदम है । नीतीश जी की सरकार ने हमेशा उनके साथ न्याय करने का काम किया है । पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने किया था । हमको याद है यू0पी0ए0-2 की सरकार थी, उस समय भी हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में वहां महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गयी, लेकिन वहां विपक्ष के लोगों ने सुना नहीं और आज तक वह बिल पड़ा हुआ है । हम तो सदन में भी बोलते हैं कि अब तो महिलाओं को उनका हक दीजिये, उनको 33 की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण देकर आप बताईये कि आप महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है । आप गुंडा राज बनाना चाहते हैं यू0पी0 को, आप सोच रहे हैं कि यू0पी0 में जीत गये, बहुत बड़ा तीर मार लिये हैं लेकिन आप सोचिये, गोवा का मुख्यमंत्री और वहां का 6 मंत्री चुनाव हार गये, इसका मतलब कि वहां की जनता आप को नकार चुकी है । भले ही वहां सरकार आप ने पैसे के बल पर बनाया । लेकिन वहां की जनता आप को नकार चुकी है । आप पंजाब को भी याद कीजिये, पंजाब में आप की क्या स्थिति है ? वहां भी जनता आप को नकार चुकी है । मणिपुर में भी आप ने पैसे के बल पर सरकार बनाया, यह भूलनेवाली बात नहीं है ।

(व्यवधान)

पैसे के बल पर सरकार चला लीजियेगा लेकिन लोगों के मन में आप नहीं जा सकते हैं । आप उनके बारे में सोच नहीं सकते, आप की मानसिकता नहीं है । अगर मानसिकता होती तो साम्प्रदायिक ताकत को बढ़ावा नहीं देते । जिस पर बीस-बीस केस चल रहे हैं, उन को मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करते आप ।

(व्यवधान)

आप को सोचना चाहिए कि 13-13 केस का कॉगनीजेंस हो चुका है लेकिन आप ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है । बोलते है कि भगवा रंग में पूरे देश को ला देंगे । यह महात्मा गांधी के आंदोलन का क्षेत्र है, आज से सौ साल पहले महात्मा गांधी ने यही से आंदोलन की शुरूआत की थी और अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया था । मैं आप को विश्वास दिलाता हूं, अप्रील आ रहा है 10 अप्रील,1917 में महात्मा गांधी जी ने यहीं से शुरूआत की थी और हमारे नेता फिर से चम्पारण से शुरू कर रहे हैं और 2019 में पूरे देश में महागठबंधन के नेतृत्व में आप को खदेड़ कर भगाने का काम हमलोग करेंगे । यह आपको मानना पड़ेगा । आप को मंथन करना है कि कैसे चलेगा ? हमारे नेता ने कर के दिखाया कि हमलोग सभी धर्मों को एक साथ मानते हैं, सभी धर्मों को एक साथ आगे लेकर चलने का काम करते हैं । अभी हाल में जो पर्व मना है 350 साल बाद, उसमें उन्होंने जो कर के दिखाया, जब हम पंजाब चुनाव में गये थे, दिल गदगद हो जाता था, वहां के लोग पूछते थे कि भाई, आप बिहार से आये हैं, तारीफ इस तरह करते थे, पकड़ कर आदर के साथ बैठाते थे और मिठाई खिलाने का काम करते थे । जो टूरिस्ट हमारे यहां नहीं आते थे, वह अब सोचते हैं

कि हम बिहार जायेंगे । नीतीश जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, उस के कारण यह हुआ है । आप को मंथन करना पड़ेगा इस विषय पर कि आज बिहार कहां से कहां जा रहा है । कभी परिवहन के लिये हम को याद है, आज से दस साल पहले सीतामढ़ी जाने की बात सोच कर डर लगता था कि हमको सीतामढ़ी जाना पड़ेगा क्योंकि 12 घंटा, 14 घंटा जाने में लगता था, आज जो व्यवस्था परिवहन विभाग के हिसाब से हुआ है नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, आज हम सीतामढ़ी से पटना 3 घंटा में आने-जाने का काम करते हैं । आप को मालूम होना चाहिए, हम जब सीतामढ़ी जाते थे बस से, टैक्टर से, नाव से, ऑटो से तब जा कर सीतामढ़ी पहुंचते थे लेकिन आज एक बार किसी भी गाड़ी पर बैठिये, चाहियेगा तो ऑटो से भी पहुंच जाईयेगा सीतामढ़ी । आज यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है ।

...क्रमश :...

टर्न-19/राजेश/20.3.17

श्री अमीत कुमार : ...क्रमश:... गॉव-गॉव में आज कहीं भी चले जाइये, आप ऑटो रिक्शा देखियेगा, तो हर गॉव में, हर गरीब आज ऑटो रिक्शा चला करके अपना घर चला रहा है, यह सरकार की ही देन है, परिवहन विभाग और पथ निर्माण विभाग की वजह से आज हर गॉव में रोड बना है, जिसके कारण आज गरीब आदमी भी अपना भरण-पोषण कर रहे हैं, पहले महोदय शादी-ब्याह में बहुत ही दिक्कत होता था, गरीब आदमी सोचते थे कि कैसे हम स्कार्पियो लेंगे, लेकिन आज गॉव में या कहीं भी शादी ब्याह हो या उसका कोई परिवार बीमार हो, तो लोग ऑटो से भी उसको लेकर चला जाता है, यह देन हमारी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह उनकी देन है ।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग की बात ये लोग करते हैं, आप चले जाइये एम्स में, आप चले जाइये पी0एम0सी0एच0 में या गॉव के किसी भी ब्लॉक में चले जाइये, तो आज वहॉ डाक्टर हैं, कुछ-कुछ कमियॉ थीं, लेकिन विगत डेढ़ वर्षो में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कदम उठाये हैं,उससे बहुत सी चीजें सुधर रही हैं और हम आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें सुधार होगा लेकिन मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे ससौला में पी0एच0सी0 का बिल्डिंग नहीं बना है, बैरगनिया और रीगा में नया बिल्डिंग बना है लेकिन ससौला में बाकी है, कृपया वहॉ पर ध्यान दें, अगर वहॉ पर एक बिल्डिंग बन जायेगा, तो मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा । सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग में आप कहीं भी चले जाइये, अल्ट्रासाउण्ड का हर जगह व्यवस्था किया गया है ताकि गरीबों को कहीं जाना न पड़े, इसके लिए अल्ट्रासाउन्ड का व्यवस्था किया गया है और आज जांच केन्द्र खुल रहा है, आज हर तरह का व्यवस्था वहॉ पर लाया जा रहा है, यह देन हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का

है, हमलोग हमेशा गरीब गुरुआ का सोच रखते हैं, परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, आज बिजली का देखिये, आज आप कहीं भी जाइये, बिजली की व्यवस्था के बारे में किसी बूढ़े बुजुर्ग से मिलियेगा, तो लोग कहते हैं कि बऊआ बिजली जल छई, आज तक हमनी सब ई सब न देखले रहिली, बाप रे बाप नीतीश जी बहुत बड़ा काम कर दिहले, महोदय, यह परिवर्तन आया है, बच्चे लोग पढ़ने के लिए पहले परेशान हो जाते थे लेकिन अब जब शाम को बिजली कट जाता है, तो लोग बोलते हैं विधायक जी लाईन कट जाय छे, तो पढ़े में दिक्कत होवे छई तो क्यों, ये बिजली देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि परिवर्तन आ रहा है, हमारी सरकार ने कटौती नहीं की है, केन्द्र की सरकार ने कटौती की, जहाँ 10 प्रतिशत राज्य सरकार को पहले देना पड़ता था, आज 40 प्रतिशत देना पड़ता है ।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री राहत कोष में मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करुंगा कि मुख्यमंत्री राहत कोष जो है, उसमें राशि बढ़ाने का काम किया जाय क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो कैंसर के पेसेन्ट हैं, जो हार्ट के पेसेन्ट है, उनको एक डेढ़ लाख में नहीं पूरा होता है, अगर उसको तीन से चार लाख तक कर दिया जाय, तो बहुत से गरीब लोगों का कल्याण होगा और आगे भी काम होगा । बहुत सी बातें थी ..... (व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री अमित कुमार: सभापति महोदय, कुछ बातें और हैं जो माननीय मंत्री जी से कह दें । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सीतामढ़ी से एक दो बस और दे दीजियेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, चूंकि माँ जानकी की जन्मभूमि है, नहीं, अभी चार बस मिला है, अगर और एक दो बस मिल जायेगा, तो बहुत राहत होगा, चूंकि इसमें हँसने की बात नहीं है, आदमी की इच्छा बराबर बढ़ते रहती है, आप अभी विधायक हैं, मन में आता होगा कि हम एम0पी0 बन जायेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, फिर सोचियेगा कि योगी जी के जैसा भोगी जी बन जाइयेगा, तो बहुत अच्छा होगा, तो सोचने के लिए कोई नहीं रोका है, हमलोग यही सोच रहे हैं । इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि चार मिला है, दो और दे दीजियेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा । धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री रामविलास पासवान ।

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, आज परिवहन विभाग के जो अनुदान प्रस्ताव आये हैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आपने जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यावाद । परिवहन विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रह का महत्वपूर्ण विभाग है । वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2015-16 के बीच राजस्व का प्रति औसत 20.4 प्रतिशत की वृद्वि दर रही है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्धारित दर 13.500 करोड़ की वृद्वि से अधिक 10.7095 करोड़ की वसूली की गयी है, पूर्व में 10.8 प्रतिशत से अधिक इस वित्तीय वर्ष में वसूली की गयी है, कुल 1500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2017 तक 77.39 करोड़ की

वसूली की जायगी । आज वाहनों का निबंधन राज्य में हो रहे हैं । आर्थिक विकास वृद्वि व्यवस्था में सुधार एवं सड़कों की दशा में गुणवत्ता में सुधार के कारण वाहनों की निबंधन एवं विक्री में भारी वृद्वि हुई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2016-17 के माह नवंबर तक कुल 5,11,934 वाहनों का निबंधन हो चुका है। आधुनिक जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केन्द्र निर्माण राज्य में सभी जिलों में जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केन्द्र मोतिहारी, रोहतास, गोपालगंज, कैमूर, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुर, वैशाली एवं पूर्णियॉ जिलाओं में आधुनिक जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अरवल एवं अररिया में केवल निर्माण कार्य प्रगति पर है, इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहानाबाद, बक्सर, मधेपुरा, लख्खीसराय, सहरसा एवं औरंगाबाद जिला में आधुनिक परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा । चालक प्रशिक्षण केन्द्र शोध संस्थान की स्थापना बिहार राज्य तथा मारुति सुजुकी भागीदारी औरंगाबाद में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है । माह जनवरी, 2017 तक इसका निर्धारित कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । मित्रों आज विपक्ष के द्वारा आप देखे होंगे कि इसतरह का तो कभी किसी माननीय सदस्य के द्वारा और उस दिन विपक्ष के एक सदस्य के द्वारा टेबुल को उठा दिया गया, हमको तो लग रहा था कि जो वहॉ पर लिख रहे थे, कहीं उनको बहुत ज्यादा खतरा न हो जाय, यह सब माननीय सदस्य को उचित नहीं लगता है कि यह सब करना चाहिए, विरोध करना चाहिए विपक्ष को, ऐसा नहीं कि वहॉ पर जा करके किसी को जान का खतरा हो जाय, टेबुल को पटक दें, या और कुछ कर दें, आज भी आप देखे होंगे मित्रों, कि आज यू0पी0 के चुनाव का बड़ी ही प्रशंसा कर रहे हैं, 8 नवंबर मित्रों, जिस दिन नोटबंदी हुआ, तो इस नोटबंदी का क्या इशारा था, इस नोटबंदी से यह इशारा था कि यू0पी0 का चुनाव, गोवा का चुनाव और पंजाब का चुनाव, यह चुनाव नोटबंदी था और यह नोटबंदी इसलिए किया गया था कि अपना समेटकर रख लो और दूसरे को नोटबंदी करा दो और आज जब चुनाव खत्म हो गया मित्रों, तो अब यह फ्री हो गया, जिस तरह से सप्ताह में 10 हजार निकालो, सप्ताह में 20 हजार निकालो, सप्ताह में 50 हजारा निकालो और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया ।

क्रमशः

टर्न-20/सत्येन्द्र/20-3-17

श्री राम विलास पासवान (क्रमशः): सभी जगह नोट के धन के बल पर यू0पी0 के चुनाव में सारे पार्टियों को पैसा का क्राईसिस हुआ लेकिन इनके द्वारा जो पैसा समेट कर रख लिया गया था वही पैसा धन के उपयोग से यू0पी0 का चुनाव जीतने का काम किया है । आगे आपने देखा होगा सभापति महोदय, पिछली बार ईंट मंगवाकर के राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के नाम से सरकार बनाया था और इस बार नोटबंदी के नाम पर यू0पी0 का चुनाव जीता है । महोदय, भारत निर्माण की बात हमलोग करते हैं और ये भगवा निर्माण का बात करते हैं । सभापति महोदय, बार-बार आपलोग सुनते हैं भाजपाई के

साथी आर0एस0एस0 के साथी के द्वारा ये आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण कोई मोहन भागवत जी दिये हैं कि हमलोग के डॉ0 भीम राव अम्बेदकर जी संविधान में जाकर के दिये थे लेकिन ये लोग कहते हैं अबकी सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे । ये आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं, वे सत्य बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित कर के पूरे देश को झकझोरने का काम करते हैं । सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी..

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, हम व्यवस्था पर खड़े हैं । आज परिवहन विभाग पर बहस हो रहा है और वहां के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान: संजय जी बैठिये न, काहे बुरा लग रहा है..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) नहीं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया गया है ।

(व्यवधान)

बोलने पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री के बारे में उनका नाम नहीं कहा गया है, नाम नहीं लिया गया है।

श्री राम विलास पासवान: माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सात निश्चय..

श्री भोला यादव: सभापति महोदय, ये संजय सरावगी जी आसन को हमेशा धौंस देते हैं...

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार)नहीं नहीं, इनके धौंस से आसन कोई डरता है क्या ?

(व्यवधान)

सरावगी जी, सुनिये ऐसा कोई नियम नहीं है।

(व्यवधान)

नाम नहीं लिया गया है, नाम लेने का नहीं है। उन्होंने सरकार के ऊपर बोला है, होगा तो नाम हटा दिया जायेगा ।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण जो लागू किया है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी सात निश्चय को लागू किये हैं चाहे वह बिजली हो, घर घर नल से जल देने की बात हो, चाहे वह बसावट की सड़कें हो, माननीय मुख्यमयंत्री जी ने आज महिलाओं को भी आरक्षण देकर के उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है । सभापति महोदय, आज जो एक्सीडेंट होता है शराबबंदी से पूरे देश को बिहार से पूरे देश को सीखना चाहिए कि शराबबंदी से यहां एक्सीडेंट, लूट, डकैती खत्म हो गया है । आज शराबबंदी से पूरे देश को यह सीखना चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, परिवहन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ । राज्य के सर्वांगीण विकास में परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका है महोदय ।

महोदय परिवहन विभाग सचमुच में छोटा विभाग है जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बतलाया कि एक तरफ 60 करोड़ और एक तरफ 7 हजार करोड़ का स्वास्थ्य विभाग का बजट फिर ये परिवहन विभाग पर वाद विवाद कराना जो सभी माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा जरूरी था । महोदय, माननीय मंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि आज विभाग के अन्दर देश की आर्थिक खुशहाली लाने में, राज्य की आर्थिक खुशहाली लाने में आपकी अहम भूमिका हो सकती है । कई घर के चिराग जो बुझते हैं दुर्घटनाओं में, आप उस चिराग को भी बचा सकते हैं प्रशिक्षण देकर, आज ड्राईबिंग लाईसेंस में आप हर जिले के अन्दर प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर अच्छे प्रशिक्षित ड्राईबर के माध्यम से उस घर के बुझते हुए चिराग को बचा सकते हैं । महोदय, आज इस विभाग के अन्दर अगर जो चाहे राजस्व संग्रह के नाम पर पूर्व के वक्ताओं ने कहा तो आज यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आपको एक अच्छे डॉक्टर बनकर उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है । महोदय, आज लखीसराय जिला के अन्दर डी0टी0ओ0 नहीं है । छः माह से पूरा कार्यालय के अन्दर कामकाज बिचौलियों के बल पर चल रहा है। आज सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है वहां बस स्टैंड बना, विधान-सभा के अन्दर क्वेश्चन उठाया गया और चालू हुआ, पूरा बाजार के अन्दर बस बालों ने दलाली और पैसे के बल पर फिर बस अड्डा को बंद करा दिया। महोदय, हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की स्थिति से आपको मुक्त कराना होगा । इस विभाग को आज परिवहन विभाग के अन्दर में महोदय हमलोगों की सच्चाई क्या है कि चालक बनाने के बजाय चालाक बन रहे हैं तो कई दुर्घटनाएं घट रही है । हम चालक नहीं बना रहे चालाक बन रहे हैं और आज मौत का सौदागर बन रहे हैं महोदय इसकी बद्दुआएं कई घर के नौजवानों का जो स्थिति बद से बदतर बन रहा है, नौजवान जिनकी मोटरसाईकिल से दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसकी जिम्मेवारी भी तो तय करनी होगी । महोदय, स्वास्थ्य विभाग का मामला आया है उससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं आज सरकार की मानसिकता कहीं न कहीं बीमार है । ये चार पहिये की गाड़ी नहीं तीन पहिये की गाड़ी है तो एक पहिया घिसटकर चल रहा है महोदय और उसका स्टेयरिंग जिनके हाथ में है वे स्वयं बीमार बने हुए हैं । महोदय, बिहार की जनता का अपराध क्या है, यहां बैठे हुए माननीय विधायकों का क्या कसूर है महोदय कि स्वास्थ्य विभाग के अन्दर जो स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है उसमें विधायकों को बुलाया तक नहीं जाता है, इनसे राय विचार तक नहीं किया जाता है। क्या ये सही स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छा सुझाव नहीं दे सकते थे, क्यों इनको बंचित रखा जाता है पहले से ही ये बिहार बीमार था पहले से ही यह बिहार बीमार था, हत्या अपहरण बलात्कार का उद्योग था महोदय, कई तरह की घटनाएं घट रही थी । एन0डी0ए0 गठबंधन में इसका इलाज शुरू हुआ महोदय फिर क्यों ये बेहाल है, इलाज शुरू हुआ था फिर क्यों यह बेहाल है, क्यों स्वास्थ्य विभाग बीमार है महोदय, आज बढ़ती आबादी से सरकार बेखबर है, न डॉक्टर है न दवा है फिर भी चल रहा अस्पताल है, सात हजार करोड़ का बजट है इस विभाग को, ललचाई

आंखों से बिचौलियां खुशहाल हो रहा है महोदय, घोटाला भ्रष्टाचार का बोलवाला है, घृणित मानसिकता से सेवाभाव बीमार है, जीवन बचाने वाला आज क्यों बन रहा चंडाल है। महोदय, बेतहाशा की तरह बन रहा अस्पताल है, भ्रष्टाचारियों का बहार है । महोदय, महागठबंधन की यही सरकार है, महागठबंधन की यही सरकार है । सुनो जनता की चित्कार, सुनो जनता की चित्कार, बिहार की जनता के बद्दुआ से बचो सरकार, बिहार की जनता के बद्दुआ से बचो सरकार, मिट जायेगी निशानी, ये जनता किसी की जागिर नहीं देती है। (क्रमशः)

टर्न–21/मधुप/20.03.3017

...क्रमशः ...

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, अंत में यह कहते हुये कि आज कहते हैं कि गर्व से कहो कि बिहारी हैं, गुणगान होता है, नौजवानों की प्रतिभा को बेच रहा, नौजवानों की नौकरी को खा रहा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाली यह सरकार है, कान खोलकर सुन लो, तुष्टिकरण से नहीं बचेगी सरकार, छोटे हृदय से नहीं बचेगा बिहार । 21वीं सदी में माँ भारती का होगा जय–जयकार, होगा जय–जयकार । धन्यवाद ।

श्री मो0 इलियास हुसैन : महोदय, एक शब्द बड़ा आपत्तिजनक आ गया, सारे विद्वान लोग यहाँ मौजूद हैं । ये कुकुरमुत्ता शब्द का जो इस्तेमाल किये हैं, इसको निकलवाया जाय, असंसदीय शब्द है ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : वह असंवैधानिक है तो निकल जायेगा लेकिन उसको तो इन्होंने अच्छे सेन्स में कहा था कि उतना फैल रहा है, अस्पतालों का जाल फैल रहा है ।

श्री मो0 इलियास हुसैन : विजय सिन्हाजी के पास शब्द की कमी नहीं है, उसको निकालकर दूसरा शब्द जोड़ दें ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान । आपको अपना समय पता है।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, एक आग्रह के साथ कि यह सुशासन की सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं और न किसी को फँसाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी सामाजिक न्याय के नेता माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी पता नहीं कहाँ चले गये ।

एक सवाल है सभापति महोदय, 16.11.2016 को पी0एम0सी0एच0 में डॉ0 आलोक कुमार, दलित के बेटा को वहाँ डॉ0 सुरेन्द्रनाथ सिन्हा ने सरेआम, पूरा देश अपमानित हुआ, सरेआम एक दलित के बेटे को माँ–बहन, चमार–दुसाध कहकर तमाचे–तमाचे मार रहा है और आई0जी0 कमजोर वर्ग ने केस नम्बर 293/2016 पीरबहोर थाना कांड में संज्ञान लिया, आदेश दिया गिरफ्तारी का । सुशासन की सरकार है, कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं और न किसी को फँसाते हैं, आज तक उसकी

गिरफ्तारी नहीं हुई और पूरे बिहार में दलित अपमानित हुआ । पी0जी0 के डॉक्टर को पीटा गया ।

(व्यवधान)

बेल मिल गया कि आपने गिरफ्तार नहीं किया ? 16.11.2016 की घटना है, आज यह मार्च का महीना है । आपने इतने दिनों से, चार-पाँच महीनों से आपने उसको छोड़ रखा और आज तक उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई । उसका निलम्बन नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, स्वास्थ्य विभाग ने भी उसपर कोई कार्रवाई नहीं किया । आप कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं और न किसी को फँसाते हैं । किसी को बचाते हैं या फँसाते हैं, उसका दस्तावेज है, आई0जी0(कमजोर वर्ग) का रिपोर्ट है । महोदय, बिहार में दलित अपमानित हो रहा है, डॉक्टर पीटा जा रहा है । पी0एम0सी0एच0 का पी0जी0 का डॉक्टर अपमानित हुआ और यह दस्तावेज है । यह कमजोर वर्ग के आई0जी0 का दस्तावेज है, हम कहेंगे कि इसका जो संज्ञान लिया गया है, उसको प्रोसिडींग में, अगर प्रतिवेदन में रख लिया जाय तो हम एक आग्रह करेंगे ।

दूसरा, कहना चाहते हैं मेरे यहाँ नौहट्टा, रोहतास, चेनारी, शिवसागर चार ब्लॉक है । चार ब्लॉक में आज तक आजादी के 70 साल हो गया, अनुसूचित जाति रिजर्व कंस्टीच्यूयेंसी है, आज तक एक भी स्त्री रोग डॉक्टर नहीं गया । पहाड़ी इलाका है, आदिवासी, दलित और यादव, चमार, दुसाध, धोबी, पासी पहाड़ों पर सबसे वंचित समाज रहता है । उनकी गर्भवती महिलाओं का, पहाड़ से आवागमन नहीं है, खटिया से टाँग कर आते-आते रास्ते में डिलेवरी हो जाता है, मर जाती हैं महिलाएँ, एक भी पोस्टेड डॉक्टर नहीं है । चेरो खरवार हो, आदिवासी, ग्वाला हो, सभी जाति के गरीब रहते हैं, आज तक स्वास्थ्य विभाग का न नौहट्टा में डॉक्टर रहता है, न रोहतास में रहता है, न चेनारी में, न रूई न सूई है ।

सासाराम सदर अस्पताल में मेरे कहने पर माननीय तेज प्रताप जी गये थे, ठेहुना भर पानी लगता है, कुत्ता और बकरा बेड पर बैठता है । एक भी बेड पर बेडशीट नहीं है । इलियास साहब मुस्कुराइये मत । हम और आपको भी गोली लगेगा तो वहाँ से रेफर होगा पी0एम0सी0एच0 या बनारस, हमलोगों का कोई जान बचाने वाला नहीं है । सासाराम सदर अस्पताल की यही हालत है । कोई अतिरिक्त उप केन्द्रों पर नर्स नहीं जाती है, पहाड़ों पर नहीं जाते हैं । स्वास्थ्य विभाग की यह हालत है। दूसरा, हम आग्रह करना चाहते हैं, हमारा उग्रवाद इलाका है ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : आपस में बात नहीं कीजिये ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, एक सवाल है हमारा नौहट्टा, रोहतास, चेनारी उग्रवाद इलाका है और वहाँ कोई आवागमन नहीं है । सासाराम से 120 कि0मी0 की दूरी मेरी कंस्टीच्यूयेंसी है । हमारे यहाँ तो इतना ओवरलोड ट्रक चलता है कि एन0एच0 डेहरी से यदुनाथपुर जो सड़क जाती है, कबड़ गया है, 1 करोड़ 20 लाख रूपया तेजस्वी यादव

जी दिये भी थे, लूट लिया ठीकेदार, भरा भी नहीं, बंजारी का उधर से सीमेंट आता है, पूरा कबड़ा हुआ है, बैलगाड़ी भी नहीं जायेगा । हम जाते हैं तो तीन-चार घंटा लगता है खाली यदुनाथपुर पहुँचने में, यह हालत है । दूसरी बात, वहाँ परिवहन निगम की बस माननीय मंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, नौहट्टा से यदुनाथपुर से पटना तक गरीबों के लिये, दलितों-शोषितों के लिये, आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय के हम नेता हैं तो वहाँ से शुरू करिये ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, चेनारी से एक बस चल रही थी, अब बंद हो चुकी है । चेनारी से पटना परिवहन निगम की एक बस चल रही थी, हम चालू करने की माँग करते हैं । माननीय मंत्री, परिवहन से आग्रह करेंगे कि आप उसको चालू करिये, गरीबों का इलाका है । पहाड़ पर आज तक न बिजली, न पानी पहुँचा, सदन में चीखते रह गये। माननीय मंत्री जी रोहतास के प्रभारी मंत्री भी हैं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ललन पासवान : मात्र एक मिनट सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है । पूरे 213 गाँव पहाड़ों पर आज भी पानी के लिये तरसता है, बिजली के लिये तरसता है, बल्व नहीं देखा । कहीं न सड़क है । आदिवासी मानव जाति है, जैसे लगता है कि इंसान वहाँ नहीं रहता है । सरकार खोखली दावा करती है लेकिन आज तक वहाँ न बिजली दी, न पानी दी, न सड़क दी । हम आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार उसपर भी नजर रखने की जरूरत है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी।

श्री ललन पासवान : आजादी के 70 साल बाद नौहट्टा, रोहतास और कैमूर, रोहतास के 213 गाँव आज भी गुलाम हैं और ऐसी गुलामी से हम सरकार से मुक्ति की माँग करते हैं, सरकार गरीबों को न्याय दे । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, परिवहन विभाग पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ ।

आज की मांग के साथ स्वास्थ्य विभाग भी है । उसे मुख्य मांग रहना चाहिए था परंतु इसे नहीं रखा गया । मैं स्वास्थ्य विभाग पर ही बोलती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग राज्य की जीवनरेखा है । किसी समय जिले में तीन ही पदाधिकारी महत्वपूर्ण हुआ करते थे- जिला पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पी0डब्लू0डी0 और सिविल सर्जन । सिविल सर्जन को उस वक्त नियुक्तियों का भी अधिकार था और स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वोपरि पद के रूप में जिले में वे रहते थे परन्तु कालांतर में सिविल सर्जन के पद की महत्ता को घटा दिया गया और जिला पदाधिकारी को जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाकर सिविल सर्जन को उसका सचिव बना दिया गया ।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को चारा घोटाले में सजा हो गयी, सजा इस आधार पर हुई कि उन्होंने अनियमितता करने वाले लोगों को एक्सटेंशन दिया, लेकिन आज उल्टी स्थिति हो गयी है । स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी पर जिला पदाधिकारी, जो जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है उसके लिए सिविल सर्जन को जवाबदेह माना जाता है, जबकि सारी शक्तियां अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी में निहित हैं ।

सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ की घोर कमी इस राज्य में है । पद रिक्त रहने के बावजूद पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यदि कोई चिकित्सक या पारा मेडिकल स्टाफ आवेदन करता है तो उसको लेकर अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति वर्षों बैठ जाते हैं । इसलिए मेरी मांग है कि जिलाधिकारी के चंगुल से जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन को मुक्त किया जाय ताकि वे भयमुक्त वातावरण में जिम्मेदारीपूर्वक स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ के रूप में स्वास्थ्य सेवा संचालित कर सकें ।

...क्रमशः...

टर्न–22/आजाद/20.03.2017

..... क्रमशः .....

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, एम0सी0आई0 राज्य के हर मेडिकल कॉलेज के लिए चेतावनी देती रहती है, परन्तु यहां न चिकित्सकों का पद भरा जाता है, न पारा मेडिकल स्टाफ का पद भरा जाता है और न ही आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाती है। करोड़ों करोड़ की मशीन लगाकर डम्प कर दिया जाता है और उनपर व्यय निष्फल हो जाता है।

एम0सी0आई0 का गाइडलाइन है कि अस्पताल के कुल बेड का 10 परसेंट बेड आइ0सी0यू0 में होना चाहिए, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आई0सी0यू0 में 10 परसेंट तो क्या 5 परसेंट भी बेड उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि इस राज्य में सांस्थिक प्रसव का कार्यक्रम आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा संचालित हो रहा है और

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप पूरी बात कह दीजिये ।

श्रीमती बेबी कुमारी : जी । सारा दारोमदार उन्हीं पर है, लेकिन उनको कोई मानदेय निर्धारित नहीं है। उनको प्रति केस शुल्क दिया जाता है। इसलिए आशा कार्यकर्त्ताओं को मासिक मानदेय निर्धारित करने की मैं मांग करती हूँ।

महोदय, बिहार राज्य में दुर्घटनाएं रोज घट रही है, परन्तु किसी भी एन0एच0 के किनारे या जिला मुख्यालय यहां तक कि पटना राजधानी में भी कोई ट्रौमा सेंटर नहीं है। मैं हरेक जिला मुख्यालय के निकटस्थ एन0एच0 किनारे ट्रौमा सेंटर स्थापित करने की मांग करती हूँ।

महोदय, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 73 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। जिनमें से श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा भी सम्मिलित है । नवम्बर, 2016 में एस0के0एम0सी0एच0 का अपग्रेडेशन का काम आवंटित किया गया परन्तु 5 महीनों में 2 परसेंट ही काम हुआ है । दरभंगा मेडिकल कॉलेज का तो हाल और भी बुरा है । वहां इन 5 महीनों में 1 परसेंट ही काम हुआ है ।

सभापति महोदय, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग और राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, वह नहीं के बराबर है । एस0के0एम0सी0एच0 उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है। इसे आइ0जी0आइ0एम0एस0 की तर्ज पर विकसित किया जाय । आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत,बहुत धन्यवाद ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह किया था कि जो रिपोर्ट है, उसको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय .....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : आपने आग्रह नहीं किया था, भाषण में नहीं कहा था ।

श्री ललन पासवान : प्रतिवेदन का पार्ट जो है .....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, जो मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में मामला सबजुडीश है, वैसे मामले को सदन में नहीं उठाया जा सकता है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : बिल्कुल ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, यदि कोर्ट में मामला है, सवाल है कि यहां नहीं उठेगा तो कहां उठेगा ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : आप अलग से सरकार को दीजियेगा, सदन के माध्यम से आप नहीं दे सकते हैं । छोड़िये । माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी ।

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं परिवहन विभाग के वाद-विवाद में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । परिवहन विभाग के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनकी मनमानी रवैय्या की ओर हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं । आप यदि घर से सुबह निकलते हैं तो लगभग सारे शहरों की स्थिति ऐसी है कि ट्रैक्टर या ट्रक पर बालू रहता है और उनके द्वारा नियम-कानून की अनदेखी की जाती है । आप मोटरसाईकिल से ट्रैक्टर से साईड नहीं ले सकते हैं, बालू उड़-उड़ कर ऑखों में पड़ता है , नियम की टोटल अनदेखी की जाती है । परिवहन विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, वे पैसे के लेन-देन में व्यस्त रहते हैं । कहीं कानूनी नियम के देख-रेख का काम नहीं करते हैं । मैं आपके माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ कि लगभग बिहार के सारे शहरों में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो महाजाम की समस्या से सारा शहर चरमरा

उठता है । सारे बच्चे स्कूल से दौड़ते हुये घर की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में ही हमको लगता है कि सो जाते हैं । तो परिवहन विभाग की जो जाम की स्थिति है, वह महा बदतर स्थिति है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जो बच्चे कम से कम स्कूल से छुट्टी होते हैं, महाजाम की जो समस्या है, उसपर भी सरकार ध्यान दे कि कम से कम दो-तीन घंटे के बजाय बच्चे अपने घर आधे घंटे में पहुँच सके।

महोदय, परिवहन विभाग में रोज सैंकड़ों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हमको आज तक नहीं लगा कि 20-25 साल की गाड़ी उसका फीटनेस टेस्ट परिवहन विभाग के पदाधिकारी पैसे लेकर कर दे देते हैं । जबकि वह गाड़ी रोड पर चलने लायक स्थिति में नहीं है । आप गाड़ी से माननीय विधायक लोग मोटरसाईकिल से कभी शाम को, कभी सुबह चाहे दिन में चलें तो आप रोड पर नहीं चल सकते हैं, आपके ऑखों में धुँआ, सभी रिजेक्टेड गाड़ी है, उसमें कहीं भी परिवहन विभाग का जो नियम है, उसका पालन नहीं होता है, उनके द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ायी जाती है।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : ठीक है ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, एक मिनट । हम इससे ज्यादा टाईम नहीं लेते हैं । महोदय, हमारे यहां सोमेश्वर महादेव की नगरी है । परिवहन विभाग का हमको लगता है कि अगर प्राइवेट बस नहीं चले तो एक भी बस वहां पर नहीं चलेगी । परिवहन विभाग प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पर निर्भर हो गया है । मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से सरकार से कि कम से कम सोमेश्वर धाम अरेराज के लिए एक या दो गाड़ी देने की कृपा करें । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, दो मिनट ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, आज परिवहन विभाग पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया है, हम इसके लिए आभारी हूँ । महोदय, सबसे पहली बात मुझे कहना है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह यू0पी0 का बोर्डर है और सुदूर इलाका है और महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम ही लोग हैं बोर्डर पर कि निश्चित रूप से बिहार में भगवा को घुसने नहीं देंगे । महोदय, चूँकि मैं जानता हूँ कि भगवा दलित-महादलित विरोधी है और इसके लिए मेरे पास उदाहरण भी है । आसन से समय मिलेगा .....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें ।

श्री सत्यदेव राम : आसन से हमको समय मिलेगा तो मैं इस सवाल पर अगले दिन में प्रमाणित करूँगा कि कैसे भगवा दलित-महादलित विरोधी है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दरौली विधान सभा में दरौली प्रखंड है .....

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जहां से परिवहन विभाग की कोई गाड़ियां नहीं चलती है और वहां से पटना आने-जाने का सरकारी साधन नहीं है । इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि दरौली से परिवहन विभाग की गाड़ियां चलनी चाहिए ।

महोदय, स्वास्थ्य के विषय पर भी मुझे कहना है कि मैंने कहा कि हमारा सुदूर इलाका है और वहां जो पी0एच0सी0 है, उस पी0एच0सी0 में .....

अध्यक्ष : आप सत्यदेव जी, अपनी बात बोलते जाईए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पी0एच0सी0 में डॉक्टर नहीं हैं, महिला डॉक्टर नहीं है । एक डॉक्टर हैं महोदय, जो आज 20 वर्षों से पी0एच0सी0 में जमे हुये हैं और वे निजी प्रैक्टिश करते हैं कम और ज्यादा वे पॉलिटिक्स करते हैं । वे राजनैतिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं और इसीलिए लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाते हैं । हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इस बात की नोटिश होनी चाहिए । मैं डिटेल्स उसको दे दूँगा । वैसे डॉक्टरों को जो वर्षों से जमे हुये हैं और वे राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, उनका मैं तत्काल स्थानान्तरण करने की मांग सरकार से करता हूँ । साथ ही मुझे जो समय मिला महोदय, इसके लिए मैं फिर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : समय ही नहीं मिला, बल्कि आपको ज्यादा समय मिला ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

टर्न–23/अंजनी/दि0 20.03.2017

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रतिपक्ष के नेता को भी धन्यवाद करता हूँ और सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता जिन्होंने आर्शीवाद दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ ।....

अध्यक्ष : श्री खेमका जी, आप कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और यह प्रस्ताव माननीय सदस्य अरूण जी का है, इनको भी धन्यवाद दीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : जी । हमारे सचेतक, आदरणीय श्री अरूण कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ। महोदय, परिवहन विभाग के बजट से भी मुख्य था, प्रधान था स्वास्थ्य विभाग का लेकिन परिवहन को रखा गया है । इसलिए परिवहन की चर्चा के बाद स्वास्थ्य के बारे में भी दो बात कहना चाहूंगा । परिवहन विभाग के बिना राज्य के विकास का सर्वांग्नि विकास संभव नहीं है । परिवहन विभाग का जो बजट है, उसके आंकड़े पर गौर करने की आवश्यकता है । परिवहन विभाग के द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्तावित बजट में वर्ष 2016–17 के मुकाबले 4.30 करोड़ रूपया अधिक है, परन्तु विभाग द्वारा बजटीय राशि खर्च नहीं हो पाती है और अंत में यह राशि सरेंडर हो जाती है । इसका प्रमाण है कि जनवरी, 2017 में मात्र 7.31 प्रतिशत् राशि ही अभी तक खर्च हो पायी है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, दो महीना बचा है, कैसे वह राशि खर्च हो पायेगी आदरणीय मंत्री जी अपने उद्बोधन में बताने की कृपा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में सुरक्षा की चर्चा की गयी है । सड़क सुरक्षा के आंकड़े भी दिये गये हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से सदन में जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको हर जगह सुरक्षा की

दृष्टिकोण से उनके सामने जो घटनायें होती हैं, वह सर्वविदित है । डेली, हर विधाान सभा के हर प्रखंड चाहे वह शहर हो या गांव हो, उसमें दुर्घटनायें बढ़ी हैं । उस दिशा में कैसे दुर्घटना कम हो, उसपर सरकार को पहल करनी चाहिए । परिवहन विभाग मंत्री सुरक्षा की दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में उसको जोड़ने का काम किया है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ लेकिन मेरा इसपर भी सुझाव है कि स्काउट एवं गाईड के जो सदस्य हैं, उसके द्वारा भी सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, जांच चौकी की चर्चा हमारे माननीय मंत्री जी ने की है, मैं पूर्णिया क्षेत्र से हूँ जहां दलकोला में, जहां चौकी है, उस जांच चौकी के दोनों तरफ, इसलिए भी कि वह बंगाल का बौर्डर है और उस जांच चौकी के बंगाल की ओर और इस ओर तीन किलोमीटर तक लम्बी लाईन इसलिए लगी रहती है कि जांच दिन को न होकर उसे रात में पैसे लेकर, भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उसे टपाया जाता है । कैसे ओवरलोडिंग कम हो, निश्चितरूपेण मंत्री जी को इसकी जांच करायी जानी चाहिए और इसकी चिन्ता करनी चाहिए । हम वाहन प्रदूषण की बात करते हैं, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, उधर से हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि कुकुरमुत्ता शब्द को बाहर निकालना चाहिए । जो वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र है, वह बिहार में विभाग की ओर से कुकुरमुत्ता की तरह हर शहर में, हर चौराहे पर छा गया है और उनसे वाहन प्रदूषण के नाम पर पैसे लेकर एक कागज देकर प्रदूषण को पूरे बिहार में बढ़ाया जा रहा है । मैं सदन के माध्यम से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने कनकलुड में इसको जरूर लाइए कि कैसे इसपर अंकुश लग सकता है । अध्यक्ष महोदय, निबंधन को सरल करने की बात परिवहन विभाग में की गयी है । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निबंधन हेतु, जो नौजवान बेरोजगार हैं, वह अपना लाईसेंस बनाने के लिए निबंधन कार्यालय में दो-दो दिन, तीन-तीन दिन, चार-चार दिन खड़े रहते हैं । मैं पूर्णियां की बात कहना चाहता हूँ, इसलिए कि 1770 का उत्तर पूरब का सीमावर्त्ती जिला है, वह बहुत पुराना जिला है, वह प्रमंडल मुख्यालय है और वहां पर जो नौजवान हैं, जो रोजगार करने के लिए, लाईसेंस बनाने के लिए आते हैं, उनसे पैसे की वसूली की जा रही है बिचौलिए के माध्यम से और उस ऑफिस के कर्मचारियों के माध्यम से, कैसे परिवहन में भ्रष्टाचार दूर होगा, यह चिन्ता का विषय है । अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में महिला सशक्तिकरण के लिए व्यवस्था की गयी है .....

अध्यक्ष : अब आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : एक मिनट में सर । मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलुंगा । मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ । लेकिन मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसमें जो महिलाओं को छूट मिला है, उसमें एस0टी0,एस0सी0 के जो नौजवान हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं उनको भी कर में छूट देने का सुझाव देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए पटना में बसें दी गयी है, मैं परिवहन मंत्री जी से

कहूंगा कि ऐसे जो प्रमंडल मुख्यालय है, ऐसे जिला हैं, वहां पर भी बसें महिलाओं के लिए देने की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, एक सेंकेंड आपका और लूंगा, इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग से भी यह जुड़ा हुआ आपका बजट था, मैं सिर्फ दो-तीन चीजें मांग के रूप में रखना चाहता हूँ । पूर्णिया में बड़ा सदर अस्पताल है, जहां सीमावर्त्ती क्षेत्र से डेली दस हजार से उपर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं । वहां पर मेडिकल वेस्टेज डिसपोजल के लिए इनसीमीनेटर नहीं है, इसलिए मैं सुझाव दूंगा और मांग करूँगा कि वहां इनसीमीनेटर की व्यवस्था की जाय और डायलेसिस और आई.सी.यू. वहां बंद है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : कुल मिलाकर जो अस्पतालों की स्थिति है, बड़ी दयनीय है, बहुत खराब है, इसलिए एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि हमारे माननीय सदस्यों ने सदन के अन्दर बहुत सी बातें की है । आवश्यकता है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कहा कि सब का साथ, सब का विकास ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह । नेमतुल्लाह जी, आप पांच-सात मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिए, सरकार का उत्तर होगा ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कर देता हूँ । महोदय, परिवहन विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आपने दो-तीन मिनट का समय दिया, शुक्रिया । दुनिया में जो रेल है, उसका सबसे बड़ा नेटवर्क हिन्दुस्तान में है और उससे कम नहीं रोड है। रोड और रेल, रेल का बहुत बड़ा महत्व है और रोड का उससे भी महत्व अधिक है । जहां रेल नहीं जा पाती है, वहां रोड से जाने की व्यवस्था है । महोदय, यह इकोनोमिक व्यवस्था है रोड की । रोड आवागमन का रीढ़ है, लोगों को आवागमन के लिए रोड बहुत बड़ी सुविधा है । आने-जाने के लिए, माल ढ़ोलाई में, सेल्फ इम्पलायमेंट में रोड का बहुत बड़ा योगदान है । आज जो टेकनॉलोजी है, माननीय मंत्री जी के कुशल प्रशासन में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का डेभलपमेंट हो रहा है,

क्रमशः....

टर्न-24/शंभु/20.03.17

श्री मो0 नेमतुल्लाह : क्रमशः.....डीलक्स बस चल रहा है और जिस तरह से माल ढुलाई जो हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना सुविधा उत्पन्न हो गया है। महोदय, बिहार में रेकार्ड रजिस्ट्रेशन हुआ। विमेन्स के लिए स्पेशल बस इन्होंने दिया। प्रकाश उत्सव हुआ उसमें इन्होंने 200 बस दिया। माननीय मुख्यमंत्री का देश और विदेश में भी इसकी प्रशंसा हुई और उसमें 7 लाख 70 हजार लोग आये देश विदेश से, उसमें सफर

किया। महोदय, जहां तक स्वास्थ्य विभाग के बारे में माननीय सदस्य हमारे एक बोल रहे थे, कुछ उनको तारीफ भी करनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के बारे में- चार पांच मेडिकल कॉलेज दिया माननीय स्मार्ट हेल्थ मिनिस्टर ने बिहार को इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। महोदय, फेमली प्लानिंग के बारे में जो बोल रहे थे उसमें इनको मालूम होना चाहिए कि Bihar was awarded first prize for exemplary work at national level in female sterilization in 2015-16. इन्होंने दिया है अवार्ड और ये कह रहे हैं कि फिमेल स्ट्रजाइजेशन और फैमली प्लानिंग के बारे में इन्होंने बिहार को अवार्ड दिया फर्स्ट प्राइज। महोदय, सब डिविजन स्तर पर ए0एन0एम0 का खोला जा रहा है, बी0एस0सी0 नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज का स्थापना होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज बेगुसराय में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, भोजपुर में, महुआ वैशाली में इस्टीब्लेशमेंट हो रहा है। महोदय, ये बिहार में बाहर अब लोग नहीं जायेंगे, बिहार में आपको किडनी ट्रांस्प्लांटेशन जो होता है उसका बिहार में अब सुविधा दिया जा रहा है। अब तो भोल्व भी चेंज किया जायेगा, ओपेन हार्ट सर्जरी जो लोग भेलोर जा रहे थे अब वह सुविधा आपको बिहार में मिल रहा है। गरीबों के लिए सुविधा कोस्टली होता जाता था उसको सुविधा दी जा रही है । महोदय, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में औलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने जिस तरह से अल्पसंख्यक का बजट दुगुना करने का काम किया। यह माननीय मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री सराहनीय के काबिल हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, अगर फंड की कमी रहेगी तो अल्पसंख्यकों के बीच में विकास नहीं होगा। आज माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अभी पैसा नहीं गया है, जो बेरोजगार हैं युवक वे दरखास्त जमा कर चुके हैं। जिस तरह से दरखस्त जमा किये हैं जिला में पैसा भेजें। अब तो वित्ती मंत्री ने अपार पैसा दे दिया है, अब पैसा भेजें जिला में ताकि वह हासिल कर सकें, अपने सेल्फ इम्पलायमेंट के लिए जो ऋण चाहते हैं वह ऋण उनको सुलभ तरीके से मिल सके। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से डाक्टर की कमी है, इन्होंने माना है स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि डाक्टर की कमी है लेकिन निदेश किया है हर जिला में डी0एम0 की अध्यक्षता में और सिविल सर्जन को कि आप कंट्रेक्ट पर बहाल कीजिए आप रखिये डाक्टर। इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, डाक्टर जायेंगे प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में जायेंगे और माननीय मंत्री जी से स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि एक हमारे यहां बेलसंड में दो दरौली प्रखंड में है, एक स्वास्थ्य केन्द्र है उसकी हालत जर्जर हो गयी है। उसको बनवा दें चूंकि कब वह भवन गिर जायेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, काफी पुराना है। वहीं एक फुटानीगंज है और बेलसंड में वह भवन भी मौजूद है वहां स्वास्थ्य केन्द्र की जरूरत है। वहां स्वास्थ्य केन्द्र करवा दें। महोदय, परिवहन विभाग जिस तरह से शराबबन्दी के बाद से जिस तरह से एक्सीडेंट में कमी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद इन्होंने उसका अनुपालन किया है जो स्पीडवार्नर का वह

भी इन्होंने अनुपालन किया है, लागू किया है। आपने हरा बत्ती दिखा दिया मैं आपका, सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष : लाल बत्ती तक ले सकते हैं।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : जी।

अध्यक्ष : चलिए अब समाप्त ही कर दीजिए।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री परिवहन विभाग।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, सी0एल0 गुप्ता ने स्वास्थ्य के मामले को उठाया था और स्वास्थ्य मंत्री हैं नहीं.....

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रारंभ करें।

सरकार का उत्तर

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के बजट मांग के संबंध में माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है। उसके संबंध में करीब 16 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लेने का काम किया है। श्री राजेन्द्र राम जी, श्री रत्नेश सदा जी, डा0 सी0एन0गुप्ता जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री जयवर्द्धन यादव जी, श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, विनोद कुमार सिंह जी, अमीत कुमार जी, रामविलास पासवान जी, विजय कुमार जी, ललन पासवान जी, बेबी कुमारी जी, राजू तिवारी जी, सत्यदेव राम जी, विजय कुमार खेमका जी, नेमतुल्लाह जी ।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण ने सदन से वॉकआउट किया)

इन लोगों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिया है उसको हम ग्रहण करते हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से हमलोग विभाग को ठीक से चलाने में करेंगे। महोदय, विश्व में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था भारत में होने के बावजूद भी सड़क मार्ग से ढुलाई का काम आज भी भारत में 65 प्रतिशत किया जाता है और यात्रियों को यातायात की सुविधा 40 प्रतिशत यात्री परिवहन मार्ग को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। आर्थिक विकास में इसकी अहम भूमिका है इसको नकारा नहीं जा सकता है। महोदय, बिहार में भी गत वर्ष हमलोगों ने गाड़ियों की, जो छोटी बड़ी गाड़ियों को मिलाकर के जो निबंधन हुआ है वह सात लाख से भी ज्यादा गाड़ियों का निबंधन होने का काम किया है। महोदय, सात लाख गाड़ियां इतनी होती है कि अगर मानव श्रृंखला की तरह हम वाहन श्रृंखला बनाने का काम करें तो पटना के गांधी मैदान से दिल्ली होते हुए जयपुर तक पहुंचने का काम होगा, यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महोदय, यह तो अत्यधिक वृद्धि जो हो रही है वाहनों की बिक्री में और निबंधन में यह स्पष्ट रूप से द्योतक है कि हमारे कुशल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को इतनी ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। महोदय, आज

मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण विभाग है। हमलोगों ने काफी कोशिश और मेहनत करने के बाद हमलोगों को आशातीत सफलता हासिल होने का काम हुआ है। महोदय, जो 2006 और 2007 में इस विभाग के द्वारा महज 200 करोड़ रूपये का संग्रह किया जाता था। पिछले वर्ष हमलोगों ने 1070 करोड़ रूपया संग्रह करने का काम किया है और इस वर्ष फरवरी के अंत तक हमलोगों ने 1100 करोड़ रूपया के करीब-करीब संग्रह करने का काम किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हमलोग 1250 करोड़ संग्रह करने का काम करेंगे, जो प्रतिवर्ष अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाय तो 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष हमलोग इजाफा करते रहे हैं राजस्व संग्रह में । महोदय, सिर्फ हमलोगों ने इसी में नहीं जो बार-बार हमारे विपक्ष के सदस्य हमलोगों को बताते रहते हैं कि ओवरलोडिंग की समस्या है, है समस्या है, काफी समस्याएं हैं, मगर हमलोगों के पास जो ही जीर्णशीर्ण अवस्था में हमलोगों को जो कर्मचारियों की फौज मिली हुई है उसी के तहत हमलोग करते हैं और पिछले साल हमलोगों ने 160 करोड़ रूपया सम्मन के माध्यम से जो फाइन हमलोग लेते हैं सम्मन के माध्यम से, ओवरलोडिंग या गैर कानूनी ढंग से जो चालक चलाते हैं, उसके तहत हमलोगों ने 160 करोड़ रूपये वसूल करने का काम किया है। इस साल हमलोग उससे बढ़कर के करीब-करीब 170 करोड़ रूपये वसूलने का काम करेंगे। क्रमशः

टर्न-25/अशोक/20.03.2017

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : क्रमशः... अपने विभाग के सारे लोगों को इसके लिए बधाई देने का काम करना चाहते हैं । महोदय, सिर्फ हमलागों ने राजस्व संग्रहण करने का काम नहीं किया हैं महोदय, हमलोगों ने अपने सामाजिक दायित्वों का भलिभांति, हमलोगों ने निर्वहन करने का काम किया हैं । हमलोगों ने देखा है कि इमरजेंसी के समय जो हालात हुये थे और जे.पी. सेनानियों ने जो संघर्ष करने का काम किया था संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, हमलोगों ने फैसला किया है कि ऐसे सेनानियों को हम जो राज्य ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं उसमें पूरी तरह से उनलोगों को उसमें फ्री पास देने का हमलोग काम करेंगे । यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मगर हम उनको इस बात से हमलोग नमन करना चाहते हैं कि उनके योगदान को जो उन लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा को निभाने का काम किया हैं । महोदय, हमलोगों ने दिव्यांगों के प्रति अपने सोच को हमलोगों ने रखने का काम किया हैं, हमलोगों ने पहले दो सीट उनलोगों के लिए आरक्षित कर ही रखा हैं, हमलोग आगे बढ़े हैं हमलोग सकारात्मक ढंग से सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनलोगों को भी यातायात में, परिवहन में, राज्य ट्रासपोर्ट के बसों में हमलोग उन को भी फ्री पास देने का काम करेंगे ताकि समाज एक तरह से उनके प्रति अपनी सहानुभूति और हमारे समाज के लोग हैं ऐसा हम उनको दर्शाने का

काम करें । महोदय, हमलोगों ने महिला सशक्तिकरण के मामले में, हमलोगों ने वैसी महिलाओं को, जो अपना ड्राईविंग लाईसेंस होल्ड करते हैं, जिनके पास अपने वाहन हैं और स्वयं चलाना चाहते हैं उसमें हमलोग 100 प्रतिशत वाहन कर में हमलोगों ने छूट देने का निर्णय लिया है जिसको हमलोगों ने लागू करने का काम किया हैं । महोदय, हमलेागों ने कई ऐसे काम करने का काम किया है जिससे हमलोगों ने अपने सामाजिक दायित्वों का, हमलोगों ने भरपूर ढंग से निभाने का काम किया है, आपने देखा होगा महोदय कि अभी इसी वर्ष महाराज गुरू गोविन्द जी के जन्मोत्सव, प्रकाशोत्सव के समय हमलोगों ने काफी बड़ा योगदान इसमें करने का काम किया है, प्रकाशोत्सव के कारण राज्य, देश नहीं विश्व में भी हमलोगों की ख्याति हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ख्याति हुई है, बिहार प्रदेश की ख्याति हुई है, हमलोगा ने परिवहन विभाग के मार्फत से राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से हमलोगों ने 198 नई बुडको की बसों को चलाने का काम किया है ताकि सारे श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थान पर हमलोग भेजने का काम कर सकें हमलोगों ने रेकार्ड सात लाख सत्तर हजार, हमलोगों ने 7 लाख 70 हजार लोगों को, श्रद्धालुओं को गंतव्य स्थान पर भेजने का काम किया है, राउन्ड द क्लौक, 24 घंटा काम किया हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं ने भूरि भूरि प्रशंसा की है और हमलोगों को और हमारे विभाग को और बिहार को उन लोगों ने आशीष देने का काम किया हैं, आशीर्वाद देने का काम किया हैं महोदय । तो मैं इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूॅ कि हमलोग कोई कठोरता से खाली राजस्व संग्रहण ही नहीं करना चाहते है हम अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन भलि भांति करना चाहते हैं । हमलोगों ने आर.टी.पी.एस. के तहत सारे के सारे करीब करीब जितने भी बाते थीं हमलोगों ने, विभाग ने उन सब को रखने का काम किया हैं और त्वरित गति से विभाग का निर्णय हुआ है, आठ जितने सेवायें हैं उसको हमलोग और भी उसकी अवधि घटाने का काम करेंगे और उसको सही समय पर हमलोग लोगों को लाईसेंस या परमिट जो भी होगा उसको हमलोग देने का काम करेंगे । महोदय, मगर आज हम आपका ध्यान और सदन का ध्यान सब से महत्पूर्ण जो मुद्दा हैं उसकी तरफ हम आकृट करना चाहते हैं जिसके प्रति हमें भी लगता हैं कि हमलोगों ने, हमलोग, सरकार, हमारी सरकार या कोई भी सरकार के लोगों ने उसके प्रति चिन्तित होने का काम नहीं किया हैं, चिन्तित करने का काम नहीं किया हैं, आज हम सड़क सुरक्षा के मामले में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहते हैं कि अत्यंत ही गंभीर और मार्मिक सवाल जिसके तहत हमारे केन्द में भी नीतिन गडकरी साहब ने कहा है कि हम जितने भी किलो मीटर रोड बनाये उससे फर्क नहीं पड़ता हैं मगर सड़क सुरक्षा को हमे प्राथमिकता देनी होगी, इसमें कितने ही प्रियजनों की जानें चली जाती हैं, जिसको हमलोग रोकने का काम कर सकते थे, महोदय कुछ डाटा जरूर हम यहां रखना चाहते हैं कि विश्व भर में 15 लाख लोगों की सलाना मृत्यु

सड़क दुर्घटना में होती हैं और तीन गुणा ज्यादा लोग वैसे लोग दुर्घटनाओं में विकलांग हो जाते हैं जिसके कारण उनके परिवार पर बहुत बड़ा बोझ होने का काम होता हैं, सिर्फ भारत में 10 प्रतिशत लोग उसके यानी डेढ़ लाख मृत्यु की शिकार हो जाते हैं और चार गुणा लोग विकलांग होने का काम करते है। इसके कारण उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है महोदय । प्लानिंग कमीशन ने भी, प्लानिंग कमीश्न ने 2002 में ही, 2002 में आज से पन्द्रह साल पहले ही इसका आकलन किया था कि दुर्घटनोओं में कितना हमारा आर्थिक नुकसान होता है, कितना हमरा सोशल कॉस्ट नुकसान होता हैं इसको भी उन लोगों ने कलकुलेट करने का काम किया था और उनलोगों ने बताने का काम किया था महोदय कि इस दुर्घटनाओं से हमारी जो आर्थिक क्षति और सोशल कॉस्ट बैठता हैं वह हमारे देश के जी.डी.पी. का दो से तीन प्रतिशत बढ़ता हैं इसलिए महोदय इसको रोकना अति जरूरी है, इस गंभीर सवाल को उठाना जरूरी हैं, जन चेतना जागृत करने की आवश्यश्कता होगी अन्यथा आने वाले समय में, आज सात लाख गाड़िया सिर्फ बिहार में निबंधित होती हैं महोदय और यह 15 से 17 प्रशितत की दर से बढ़ती जा रही है महोदय । इतनी गाड़ियां हो जायेगी जिसके बाद हमे इसको संभालना, रोज दुर्घटनाओं को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जायेगा महोदय, इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि इस पर हमलोगों को गंभीरता से विचार करना होगा । महोदय, सड़क दुर्घटनाओं में जो मौते होती हैं महोदय उसका इम्पैक्ट होता है वह काफी गंभीर और मार्मिक होता हैं महोदय इस दुर्घटनाओं को लेकर के पूरे विश्व में बड़ी अंशाति हुई, लोगों ने वरसिलिया में उन लोगों ने मिटिंग करने के बाद एक वरसिलिया डिक्लरेसन करके उन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया । महोदय उसका हस्ताक्षरी भारत भी हैं, उसका सिगनेट्री भारत भी हैं, उस डिक्लेरेश्सन में ही कहा गया कि 2020 तक हमलोग दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50 प्रतिशत कम करने का काम करेंगे । महोदय बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता हैं चीन जैसे देश और स्पेन जैसे देश ने दुर्घटनाओं को काफी कम करने का काम किया है मगर भारत में आज भी जो दुर्घटनाओं में मौत और विकलांकता होती हैं वह 4.4 प्रतिशत बढ़ने का काम हुआ । महोदय, यह संक्रमण की तरह जो फैल रहा हैं इसको हमलोगों को बहुत जल्दी रोकने की जरूरत हैं महोदय, रोड एक्सीडेंट में जो दु:खदायी बातें होती हैं उसके संबंध में आज हमलोग एक वर्ल्ड रिमेम्ब्र्स डे रखा जाता है जो हरएक नवम्बर में तीसरे सन्डे को रखा जाता हैं । महोदय, सिर्फ रखा जाता हैं आब्जर्व करने के लिए, उनके दुखों को उनके परिवार के दुखों को, मैं आपकी अनुमति से चार लाईनें उसके बारे में जो वहां आबजर्व होतें हैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, सदन के सामने रखना चाहता हूँ - Road deaths and injuries are sudden, violent and traumatic events. Their impact is long lasting often permanent. Each year

millions of newly injured and grief people from every corner of the world are added to the countless millions who already suffer. The cumulative toll is truely tremendous. The grief and distress is greater because many of the victims are young, because many of the crashes could and should have been prevented which were not because government and societies responses are often inadequate, unsympathetic and inappropriate.

महोदय, दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा नौजवानों की जानें जाती हैं जिसको, दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, रोका जा सकता था, जिसको रोकना चाहिये था और हमलोग उसे रोक नहीं पाये हैं । महोदय, मगर हमलोगों ने, बिहार सरकार ने भी अपना कमर कसने का काम किया है इस संबंध में । हमलोग बिहार की सड़कों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने काकाम करेंगे । महोदय, हमलोगों में जज्बा है, हमलोगों में मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, लालू यादव जी का आशीर्वाद है और कांग्रेस का सहयोग है । हमलोग बिहार की सड़कों को सबसे ज्यादा देश में सुरक्षित बनाने का काम करेंगे । महोदय, इस बात का मैं आपलोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ महोदय । महोदय, जब भी हमलोग रोड सेफ्टी की बात करते हैं, सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, कोई भी कदम आगे लेने से पहले हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी धन की, राशि की दिक्कत होती थी, पैसों की दिक्कत होती थी । विधान सभा के मार्फत से हमलोगों ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधयेक के मार्फत से हमलोगों ने बिहार सेफ्टी फंड बनाने का, बिहार रोड सेफ्टी फंड बनाने का काम किया है । महोदय, यह एक डेडिकेटेड फंड है जिसमें अपने-आप रजिस्ट्रेशन से एक प्रतिशत जो समन्स अंश है उससे 10 प्रतिशत और लाइसेंस से जितने पैसे डायरेक्ट उस फंड में आने का काम करेंगे । यह एक डेडिकेटेड फंड होगा जिससे हम सिर्फ रोड सेफ्टी के बारे में, सड़क सुरक्षा के ही काम हमलोग करने का काम करेंगे । अभी आने वाले समय में चूंकि बिहार सरकार ने हमारे विभाग को नोडल एजेन्सी नियुक्त करने का काम किया है । इसमें कई शेयर होल्डर्स हैं, कई स्टेक-होल्डर्स हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-26/ज्योति

20-03-2017

क्रमशः

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : जैसे आर.सी.डी. है, रोड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग है, एडुकेशन विभाग है सारे विभाग इसमें हैं मगर नोड्ल औफिसर ट्रांसपोर्ट विभाग को ही बनाया गया है तो इसमें सारी प्रक्रिया रुल्स रेगुलेशंस और बाई लौज सारे बनकर तैयार हैं । कुछ ही दिन में हमलोग पूरी की

पूरी इनको ऐक्टिवेट करने का काम करेंगे । महोदय, अभी उस दिन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी ने भी बताया कि आर.सी.डी. में उनलोगों ने सेफ्टी कोषांग, रोड सुरक्षा कोषांग बनाने का काम किया है महोदय, आपको बताने में हर्ष होता है कि इसमें उनलोगों का पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त है । यहाँ जितने भी हादसे होते हैं उसमें कहीं भी रोड इंजीनियरिंग डिजाईन के कारण जो फौल्ट होंगें उसको हमलोग ठीक करने का काम करेंगे और यह भी बात तय हुई है कि हमलोग एक किलोमीटर में करीब पॉच छः करोड़ रुपया खर्च करने का काम करते हैं । महोदय, मात्र एक प्रतिशत पैसा भी हमलोग उसमें सांयस लगाने में और जो रैम्बलर्स लगाने में उसमें अगर वहाँ पर जो रोड बलौक लगाने का काम करेंगें तो दुर्घटनाओं में काफी कमी आने का काम करेगा, वहॉ सड़क सुरक्षा कोषांग भी बना है और उसको भी हमलोग जितना रोड शेफ्टी औडिट्स कराने की बात को हमलोगों ने तय किया है । महोदय, जो दुर्घटनाएं होती हैं बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें माना जाता है कि 17 प्रतिशत रोड दुर्घटनाएं इसलिए होती है कि लोगों ने ड्राईवर ने शराब पी रखा था महोदय, मैं मुझे बताने की जरुरत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के कारण जो शराब बंदी बिहार में हुई है उसके कारण दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आयी है । अभी सारे आंकड़े तो नहीं आए हैं मगर महोदय, हमलोग देखते थे गांव में जब भी हमलोग जाते थे पता चलता था कि कोई मोटर सायकिल पर शराब पी कर झरकट में गिरा हुआ है, घायल है, घवाईल है वह सब आजकल देखने को नहीं मिलता है महोदय, इसका सबसे बड़ा असर तो पहले पड़ा है कि दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु कम हुई है । आने वाले समय के आंकड़े साल भर के आंकड़े बतायेंगे कि किसतरह से हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं महोदय, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ड्राईवरों की अक्षमता के कारण, ड्राईवर उतने सक्षम नहीं होते हैं हेवी व्हीकिल्स चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, टेलर चलाते हैं, हजारों वेट्स गुड्स वाले जो व्हेकिल्स चलाते हैं मगर वो उतने दक्ष नहीं होते हैं जिसके कारण ऐक्सीडेंट्स होते हैं । महोदय, अभी अभी हमारे साथी वहॉ से बता रहे थे कि औरंगाबाद में जो आई.डी.टी.आर. है जो इंस्टीच्युट औफ ड्राईवर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीच्युट है मुझे भी दुख है कि उसमें छः आठ महीने की देरी हुई मगर कट्रैक्टर के कारण देरी होने का काम हुआ था, अब वह बन कर तैयार है । देश के सबसे बड़ा देश में सबसे अच्छा और स्टेट औफ दी आर्ट हम इस इंस्टीच्युशन को बनाने का काम किया है, 23 एकड़ में फैला हुआ औरंगाबाद में है, जिसमें हमलोग ड्राईवर को अच्छी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे । उसमें सबसे सौफिसटिकेटेड ट्रेनिंग देने का काम करेंगे । वहॉ पर हमलोगों ने मारुति सुजुकी को हमलोगों ने अपने साथ रखा है, पार्टनर बनाने का काम किया है उन्होंने सिमिलेटर लगाने का काम किया है ताकि हमारे ड्राईवर सभी तरह से सक्षम हो सके, भारी वाहन और टेलर को चलाने

में सक्षम हो सकेंगे । महोदय, यह बड़ी इन्सटीच्युट है महोदय, इसका एक दो तीन महीना में हमलोग माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन करके शुरु कराने का काम करेंगे, यह बहुत बड़ी बात होगी मगर साथ ही साथ एक ड्राईविंग स्कूल से हमलोगों का काम चलने वाला नहीं है । कई जगह छपरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल आदि आदि जगहों पर हमलोगों ने कलक्टर को लिखा है अगर हमलोगों को जमीन प्राप्ति होती है तो आई.डी.टी.आर.- टू, टियर टू को हमलोग जो ड्राईविंग इंस्टीच्युट हैं उसको भी हमलोग बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे जो ड्राईवर हैं खास कर जो हेवी डियूटी जो व्यवसायिक गाड़िया चलाते हैं वह दक्ष हों, सक्षम हों चलाने में ताकि उनके द्वारा कोई भी एक्सीडेंट होने का काम नहीं हो सके । महोदय, आज आपने देखा होगा कि सड़कों पर जुगाड़ गाड़ियां बहुत चलती है हमलोगों ने इस बात को देखा है कि वह पंपिंग सेट और मोटर सायकिल के हैण्डल को लगाकर अपने से बना लेते हैं । मोटर व्हेकिल ऐक्ट में वैसी गाड़ियों का कोई प्रावधान नहीं है । महोदय, मैंने उस दिन स्वयं देखा कि ढलाव पर गाड़िया खड़ी थी और उस पर सरिया लदा हुआ था और वह आउट औफ कंट्रोल था ड्राईवर के, अगर मेरे सुरक्षा कर्मी अगर उतर कर उसको नहीं रोकते तो न जाने कितने मोटर सायकिल वाले लोगों की जानें जा सकती थी इसलिए हमलोगों ने निर्णय किया है, निर्णय तो पहले ही से है उच्चत्तम न्यायालय का महोदय, मगर इसको हमलोगों ने पूरी कड़ाई से पालन करने का निर्णय नहीं तो जैसे कह रहे थे बेतहाशा यह उगेगा और सड़क सुरक्षा में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होने का काम होगा इसलिए हमलोगो ने उसको पूरी तरह से बैन करके इलीगल कैटेगरी में उसको हमलोगों ने रखने का काम किया है । महोदय, बहुत सारी बातें रोड सुरक्षा से संबंधित ये बातें जो हैं वह छोटी छोटी बातों को ठीक से करने से ही काम चल सकता है इसके लिए जागरुकता अभियान चलाने की जरुरत है । छोटी छोटी बातों से जैसे हैलमेट को ठीक से पहनना, ठीक से स्ट्रैप को लगाना, गाड़ी चलाते समय मोबाईल से नहीं बात करना गाना नहीं सुनना इनसब चीजों पर हमलोग जागरुकता अभियान चला रहे हैं । अब हमलोगों के पास राशि की कमी है । हमलोग जन चेतना जगाने का काम करेगे । रेडिया के मार्फत से हो , टी0वी0 के मार्फत से हो, पैम्फलेट पोस्टर के मार्फत से हो इन सब को हमलोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह सब बातें कोई हमलोग इसीतरह से नहीं बोल रहे हैं हमलोगों ने एक और निर्णय लिया है महोदय, कि जितने भी हमारी गाड़ियों का फिटनेस होता है वह आजकल उतना सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है, उतने अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है । हमलोगों ने यह निर्णय लिया है कि हमलोग सरकारी तौर पर हमलोग फिटनेस सेंटर औटोमेटेड फिटनेस सेंटर हरेक जिला में हमलोग औटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोलने का काम करेंगे । महोदय, चरणबद्ध तरीके से एक ही बार में सब जगह नहीं खोल सकते मगर कमीशनरी

और उसके बाद हमलोग डिस्ट्रीक्ट में हमलोग उसको खोलने का काम करेंगे जहॉ पर सारी चीजें कम्प्युटरारईज्ड होगी सारी चीज रियल टाईम में हमलोगों को जानकारी होगी कि कहॉ क्या हो रहा है और इसी औटोमेटेड तरीके से हमलोग इस बात की गारन्टी करेंगे कि वह वाहन पौल्युशन नहीं करता हो, वह वाहन का एलाईनमेंट ठीक हो, उसका स्टेयरिंग ठीक हो, उसका ब्रेक ठीक हो, उसकी लाईट ठीक से एडजस्टेड हो ऐसा हमलोग करने का काम करेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, शराबबंदी से सड़क सुरक्षा में कोई सहायता मिली है क्या?

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : पूरी सहायता मिली है । मैंने तो कहा कि सदन में कहा कि ....

अध्यक्ष : पूरे सदन ने संकल्प लिया था ।

श्री चन्द्रिका राय : पूरे सदन ने संकल्प लिया था महोदय, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है अभी तक हमलोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से 17 से 20 प्रतिशत दुर्घटनाओं में और मृत्यु दर में कमी आयी है और आने वाले समय में जब हमारे पास पूरे आंकड़े आ जायेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा लाभ हुआ है ऐसा मेरा अपना मानना है महोदय, तो औटोमेटेड सेंटर में हमलोग उसके एलाईनमेंट को चेक करने का काम करेंगे, उसकी स्टेयरिंग ठीक है या ठीक नहीं है उसको देखने का काम करेंगे उसकी बत्तियॉ ठीक से जलती है कि नहीं जलती है और रात में चलाने के समय उसमें रिफलेक्टर्स लगे हुए हैं कि नहीं है, उसमें स्पीड गवर्नर्स लगे हुए कि नहीं है इन सारी चीजों को रियल टाईम में और ठीक से कम्प्युटराईज्ड हमलोग चेकिंग करने का काम करेंगे ताकि जो सड़कों पर दुर्घटना होती है वह कम से कम हो सके, नहीं के बराबर होने का काम करें । महोदय, मैं कुछ बस परिचालन के संबंध में भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमलोगों की आर्थिक स्थिति जैसा कि सभी जानते हैं बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आर्थिक स्थिति कई वर्ष दर वर्ष खराब रही है आज के समय में हमलोग साढ़े बारह सौ करोड़ की देनदारी में लेकर बैठे हुए हैं फिर भी हमलोगों ने इसमें आने वाले समय में इनको सुधारने का इसके रिस्ट्रक्चरिंग करने की इसको रिकंस्ट्रक्शन हेतु केन्द्र सरकार को लिखने का काम किया है ताकि फिर से स्टडी हो कि इसको किसतरह से इसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगें मगर फिर भी उसके बावजूद भी हमलोगों ने हम आज आपको आज से कुछ एक दो महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास के एक इन्टर स्टेट बस टर्मिनल का उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया था यही से पटना से और वह 350 करोड़ की संपत्ति होने जा रही है जिसमें सारे परिवहन की सारी आधुनिक सुविधाएं उसमें मौजूद होंगी । मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमलोगों ने कई राज्यों से हमलोगों ने पारस्परिक समझौता करने का काम किया है । सड़क समझौता करने का काम किया हमलोगों ने झारखंड से 200 मार्गो पर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से उत्तर प्रदेश से, बंगाल से ताकि हमलोग परस्पर हमलोग आपस में वाहॅ से गाड़िया

चल सके आने वाले समय में हमलोग दिल्ली से भी समझौता करने का काम करेंगे । बुडको के हमलोगों के पास जो बसें मिली हैं 225 बसें मिली है, पहले 141 बसें मिली हैं । महोदय, बताते हुए खुशी हो रही है कि 88 लाख लोगों ने इसपर ट्रैवल करने का काम किया है जो अपने आप में एक रेकर्ड है ।

क्रमशः

टर्न-27/20.3.2017/बिपिन

श्री चन्द्रिका राय,मंत्रीः क्रमशः महोदय, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, बात तो बहुत सारी करनी थी मगर समय का अभाव होने के कारण मैं इतना ही कह सकता हूं महोदय कि यह सरकार कृतसंकल्पित है बिहार को आगे ले जाने में । कोई विभाग हो, परिवहन विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसको आगे ले जाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार आगे जाएगा, चन्द आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा । इन्हीं चंद शब्दों के साथ महोदय, मैं परिवहन का बजट स्वीकृति के लिए रखता हूं और माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का काम करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''इस शीर्षक की मांग 10/-से घटाई जाए ।'

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 60,05,80,000/-(साठ करोड़ पांच लाख अस्सी हजार)रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 45 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिए जाएं ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 21.03.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....